



RAS 2024

INTERVIEW GUIDANCE PROGRAM

OPINION BUILDING WORK BOOK

With

PROBABLE & COUNTER QUESTIONS



Scan the
QR Code For
Mock Interview
Registration

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय-सूची	पृष्ठ संख्या
1.	राजस्थान, भारत और विश्व के पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक मुद्दे (Environmental and Ecological issues of Rajasthan, India and World)	1-13
2.	भारत और विश्व के आर्थिक मुद्दे (Economic Issues of India and the World)	14-24
3.	समकालीन नैतिक मुद्दे (Contemporary Ethical Issues)	25-34
4.	नवीनतम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास (Latest Science and Technology Developments)	35-45
5.	भारतीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध और समकालीन विदेश नीति के मुद्दे (Indian Polity, International relations and contemporary foreign policy issues)	46-57
6.	राजस्थान की राजनीति, शासन और संबंधित मुद्दे (Rajasthan Polity, Governance and Related Issues)	58-60
7.	राजस्थान के आर्थिक मुद्दे और नवीनतम विकास (Economic Issues of Rajasthan and Latest Developments)	61-68

RAS 2024 INTERVIEW GUIDANCE PROGRAM



डॉ. ललित के. पंवार सर
(रिटायर्ड आईएएस) पूर्व अध्यक्ष, RPSC



अंशुक सिंग
(Rank 20, RAS 2023)



डॉ. ए के मलिक सर
विगत लोकसभा सांसद राजस्थान विधानसभा



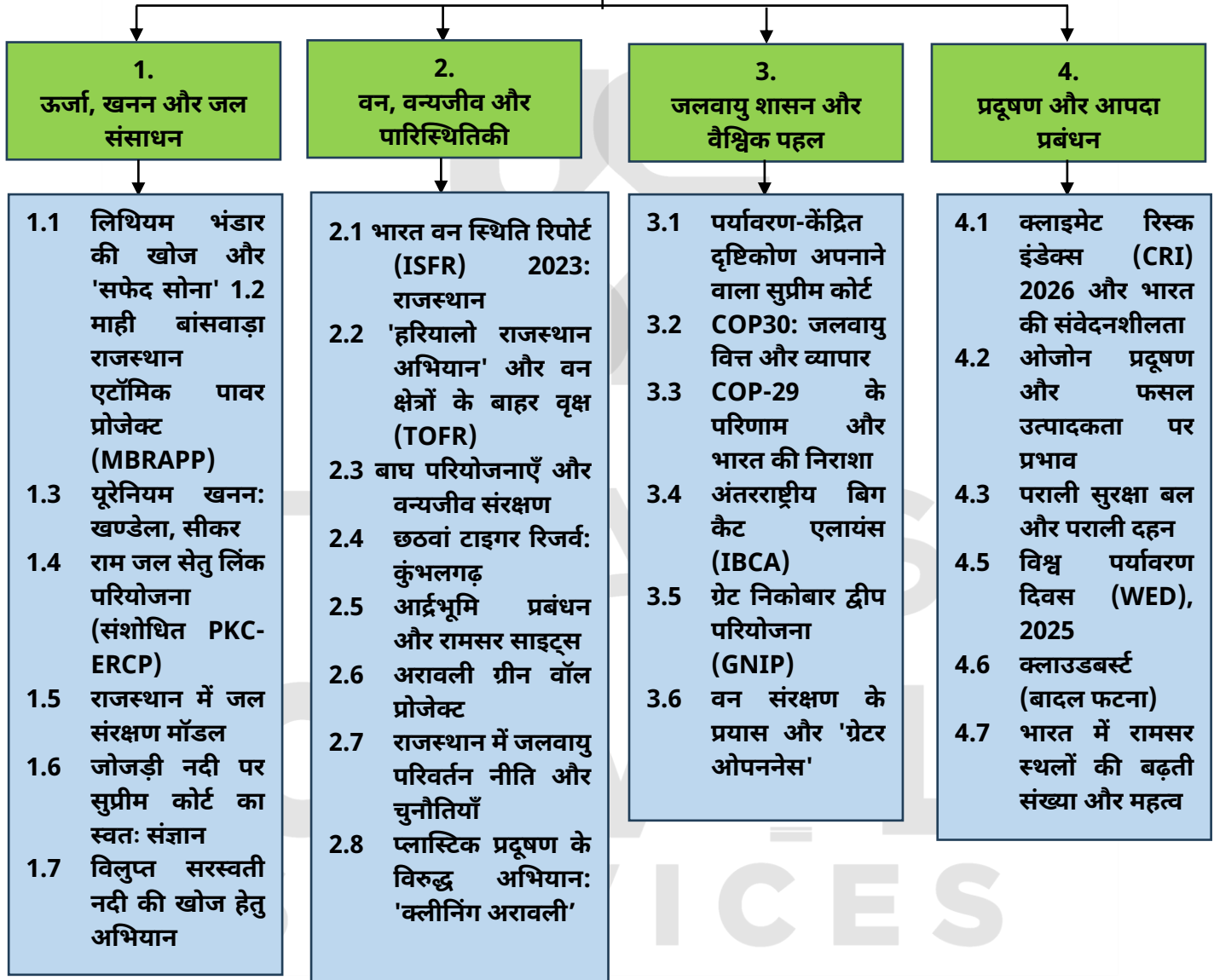
दौलत खान सर
विगत लोकसभा सांसद राजस्थान विधानसभा



Scan the
QR Code
to watch the
**Detailed video
solution of Probable
& Counter Questions**

01. राजस्थान, भारत और विश्व के पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक मुद्दे (Environmental and Ecological issues of Rajasthan, India and World)

राजस्थान, भारत और विश्व के पर्यावरणीय और पारिस्थितिक मुद्दे



RAS 2024 INTERVIEW GUIDANCE PROGRAM



डॉ. ललित के. पंवार सर
(रिटायर्ड आईएएस) पूर्व अध्यक्ष, RPSC



अंशु सिंह
(Rank 20, RAS 2023)



डॉ. ए. के. मलिक सर
पिछले वर्ष राजस्थान सरकार के सचिव



डॉ. ललित पंवार सर
सिक्किम संरक्षण दल के निदेशक



Scan the
QR Code
to watch the
**Detailed video
solution of Probable
& Counter Questions**



राजस्थान विशेष मुद्दे
(Rajasthan Specific Issues)

1. ऊर्जा, खनन और जल संसाधन
(Energy, Mining and Water Resources)

1.1 लिथियम भंडार की खोज और 'सफेद सोना' (Lithium Reserves: White Gold)

यह ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition) और भारत की आत्मनिर्भरता (Atmanirbharta) के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन खनन के पर्यावरणीय प्रभाव भी हैं।

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **स्थान:** राजस्थान के नागौर जिले में डेगाना की रेंवत पहाड़ियों में लिथियम (Lithium) के बड़े भंडार की खोज की गई है 1।
- **महत्व:** अधिकारियों के अनुसार, यह भंडार जम्मू-कश्मीर में पाए गए भंडार से अधिक हो सकता है और भारत की लगभग 80 % लिथियम मांग को पूरा कर सकता है 2।
- **उपयोग:** लिथियम एक "सफेद सोना" (White Gold) है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs), लैपटॉप और मोबाइल बैटरी के साथ-साथ परमाणु रिएक्टरों में उपयोग के लिए आवश्यक है 3।
- **आयात निर्भरता:** वर्तमान में, भारत अपनी लिथियम मांग का 70 - 80 % तक चीन से आयात करता है। खनन शुरू होने से चीन पर निर्भरता कम होगी 5।
- **खनन प्रकार:** डेगाना में यह भंडार पेगमेटाइट (Pegmatite) चट्टानों में पाया गया है, जबकि जम्मू-कश्मीर में यह क्ले (Soft Material) में मिलता है 6।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- राजस्थान में लिथियम की खोज भारत की EV नीति (Electric Vehicle Policy) और ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) को कैसे प्रभावित करेगी? 7
- लिथियम को 'सफेद सोना' क्यों कहा जाता है, और यह परमाणु ऊर्जा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 8

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- लिथियम खनन के पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक खतरे क्या हैं, विशेषकर डेगाना जैसी संवेदनशील जगहों पर?

1.2 माही बाँसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट (MBRAPP) ✳

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **शिलान्यास:** 25 सितंबर, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाँसवाड़ा में।
- **स्थान:** बाँसवाड़ा में माही नदी के किनारे।
- **रिएक्टर:** 700 मेगावाट क्षमता के 4 परमाणु रिएक्टर (700 * 4) स्थापित किए जाएंगे।
- **प्रकार:** प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर (PHWR), जो शीतलक (Coolant) और मॉडरेटर (Moderator) के रूप में भारी जल (D2O) तथा ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करता है।
- **राजस्थान की स्थिति:** यह बाँसवाड़ा में स्थापित होने वाली राजस्थान की दूसरी न्यूक्लियर साइट होगी।
- **प्रथम साइट:** राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना (RAPP) रावतभाटा, चित्तौड़गढ़।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- माही बाँसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट (MBRAPP) का महत्व क्या है, और इससे राजस्थान को क्या लाभ होगा?
- परमाणु ऊर्जा (Nuclear Energy) को भारत में 'स्वच्छ ऊर्जा' स्रोत के रूप में क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्या परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से संबंधित कोई पर्यावरणीय या सुरक्षा संबंधी चिंताएँ (Safety Concerns) हैं?

1.3 यूरेनियम खनन: खण्डेला, सीकर

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **स्थान:** सीकर जिले की खण्डेला तहसील के रोहिल में यूरेनियम के विपुल भण्डार खोजे गए।
- **कार्यकारी संस्था:** यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (UCIL)।
- **निवेश:** लगभग 3 हजार करोड़ रुपये का निवेश।
- **महत्व:** यह भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए घरेलू यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**

- खण्डेला में यूरेनियम खनन परियोजना का महत्व क्या है?
- परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए यूरेनियम का क्या उपयोग है?

- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

- यूरेनियम खनन (Uranium Mining) से संबंधित पर्यावरणीय खतरे क्या हैं, और इनसे निपटने के लिए क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं?
- राजस्थान में अन्य कौन-कौन से महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं?

1.4 राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित PKC-ERCP)

यह पूर्वी राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण जल परियोजना (Water Project) है।

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**

- **पूर्व नाम:** पार्वती-कालीसिंध-चंबल-पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (PKC-ERCP) ।
- **नया नाम:** 22 जनवरी, 2025 को राजस्थान के 'रा' और मध्य प्रदेश के 'मा' को मिलाकर 'राम जल सेतु लिंक परियोजना' रखा गया ।
- **समझौता ज्ञापन:** राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के मध्य दिसंबर, 2024 में हस्ताक्षर किए गए।
- **उद्देश्य:** चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, रूपारेल, पार्वती और गंभीर नदी बेसिनों में भेजना ।
- **लाभान्वित जिले:** राजस्थान के 17 जिले और मध्य प्रदेश के 13 जिले ।
- **मुख्य बैराज/बाँध:** नवनेरा बैराज (कालीसिंध नदी, कोटा), ईसरदा बाँध (बनास नदी, सवाई माधोपुर) ।

- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**

- 'राम जल सेतु लिंक परियोजना' राजस्थान के विकास के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है?
- राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जल-बंटवारे (Water Sharing) को लेकर क्या समझौते किए गए हैं?

- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

- क्या नदी जोड़ो परियोजनाओं (River Linking Projects) के कोई पर्यावरणीय खतरे (Environmental Hazards) भी होते हैं?
- राजस्थान में जल प्रबंधन (Water Management) के लिए अन्य प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं?

1.5 राजस्थान में जल संरक्षण मॉडल (Water Conservation Model)

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**

- **नया मॉडल:** जयपुर के कूकस गाँव में 50 जलवायु अनुकूल कृषि तालाबों (Climate-Resilient Agricultural Ponds) का उपयोग करके 10 करोड़ लीटर वर्षा जल के संरक्षण का लक्ष्य ।
- **भूजल की स्थिति:** जयपुर जिले में निष्कर्षण (Extraction) की दर प्राकृतिक पुनर्भरण (Natural Recharge) की दर से 2.22 गुना अधिक है ।
- **जैसलमेर की स्थिति:** अत्यधिक दोहन के चार्ट में सबसे ऊपर, जहाँ प्रत्येक 1 लीटर पुनर्भरण पर 3.56 लीटर भूजल निकाला गया ।
- **पारंपरिक जल संचयन प्रणालियाँ (Traditional Water Harvesting Systems):** बावड़ी, जोहड़, तालाब, टांका (Taanka), खड़ीन (Khadeen), कुंडी ।

- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**

- राजस्थान में भूजल (Groundwater) के अत्यधिक दोहन (Over-exploitation) की समस्या पर चर्चा करें और इसके परिणाम क्या हैं?
- जयपुर के कूकस गाँव के जल संरक्षण मॉडल की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

- आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भूजल निष्कर्षण को विनियमित (Regulate) करने के लिए क्या कदम उठाएँगे?
- टांका (Taanka) और खड़ीन (Khadeen) जैसी पारंपरिक प्रणालियाँ आधुनिक जल प्रबंधन (Modern Water Management) में कैसे प्रासंगिक हैं?

1.6 जोजड़ी नदी पर सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान

यह नदी प्रदूषण (River Pollution) और न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) का मामला है।

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):**

- **मुद्दा:** सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने राजस्थान की जोजड़ी नदी में औद्योगिक इकाइयों के परिणामस्वरूप बढ़ते प्रदूषण को लेकर स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लिया।
- **कारण:** औद्योगिक अपशिष्ट (Industrial Waste) के कारण नदी पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है, जिससे पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो गया है।
- **संवैधानिक लिंक:** सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पर्यावरण संरक्षण और संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) से जोड़कर देखा।
- **प्रदूषित नदियाँ:** जोजड़ी के साथ-साथ पाली की बांडी नदी और जोधपुर की लूणी नदी भी रासायनिक प्रदूषण से प्रभावित हैं।

- संभावित प्रश्न (Potential Questions):**

- जोजड़ी नदी प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेना क्या दर्शाता है?
- अनुच्छेद 21 (Right to Life) का संबंध पर्यावरण संरक्षण से कैसे है?

- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

- लूणी और जोजड़ी नदी की भौगोलिक विशेषताएँ क्या हैं? ये नदियाँ क्यों प्रदूषित हो रही हैं?
- प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों (Industrial Units) के खिलाफ एक प्रशासक के रूप में आप क्या कदम उठाएँगे?

1.7 विलुप्त सरस्वती नदी की खोज हेतु अभियान

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):**

- **अभियान:** राजस्थान सरकार द्वारा सरस्वती नदी के अस्तित्व की तलाश के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा और अलग बजट जारी किया जाएगा।
- **पद्धति:** डेनमार्क की वैज्ञानिक स्टडी पद्धति का सहारा लिया जाएगा, जिसमें तरंगों की मदद से प्राचीन नदी मार्ग (पैलियो चैनल) का पता लगाया जा सकेगा।
- **संभावित क्षेत्र:** पश्चिमी राजस्थान में लगभग 900 किलोमीटर लंबा संभावित बहाव क्षेत्र चिह्नित किया गया है।
- **सहभागिता:** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), डेनमार्क सरकार, CAZRI (काजरी) जोधपुर, IIT (BHU) वाराणसी।
- **प्राचीन नदी तंत्र:** ASI को डीग जिले के बहज गाँव में 3500 से 1000 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेषों के पास एक प्राचीन नदी तंत्र मिला है, जिसे शोधार्थी सरस्वती नदी से जोड़ रहे हैं।

- संभावित प्रश्न (Potential Questions):**

- विलुप्त सरस्वती नदी की खोज के लिए अभियान क्यों चलाया जा रहा है?
- यदि यह नदी तंत्र फिर से खोजा जाता है, तो पश्चिमी राजस्थान के जल संकट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

- सरस्वती नदी की खोज में ISRO और CAZRI जैसे संस्थानों की क्या तकनीकी भूमिका है?
- घग्घर नदी को सरस्वती नदी का अवशेष क्यों माना जाता है?

2. वन, वन्यजीव और पारिस्थितिकी (Forest, Wildlife and Ecology)

2.1 भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2023: राजस्थान

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):**

- **जारीकर्ता:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 21 दिसंबर, 2024 को जारी।
- **कुल वन एवं वृक्ष आवरण:** 27,389.33 वर्ग किमी (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8 %)।
- **कुल वनावरण क्षेत्र:** 16,548.21 वर्ग किमी (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.84 %)।
- **वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि:** 394.46 वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज (वन आवरण में 83.80 वर्ग किमी की कमी, जबकि वृक्ष आवरण में 478.26 वर्ग किमी की वृद्धि)।

- सर्वाधिक वनावरण वाले जिले (Area):
 1. उदयपुर (Udaipur)
 2. अलवर (Alwar)।
- सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले (Percentage):
 1. उदयपुर (23.60 %)
 2. प्रतापगढ़ (Pratapgarh) (22.48 %)।
- वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले:
 1. सीकर (Sikar)
 2. बाड़मेर (Barmer)।
- संभावित प्रश्न (Potential Questions):
 - ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में वन और वृक्ष आवरण की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालें।
 - राजस्थान में 'वन आवरण में कमी' और 'वृक्ष आवरण में वृद्धि' का क्या निहितार्थ (Implication) है?
- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):
 - राजस्थान में वन आवरण कम होने के बावजूद वृक्ष आवरण में वृद्धि क्यों हुई है? आप इसके लिए कौन-से सरकारी प्रयासों को श्रेय देंगे?
 - वन आवरण (Forest Cover) और वृक्ष आवरण (Tree Cover) में मुख्य अंतर क्या है?

2.2 'हरियाली राजस्थान अभियान' और वन क्षेत्रों के बाहर वृक्ष (TOFR)

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):
 - **अभियान:** 'हरियाली राजस्थान अभियान' को एक जन आंदोलन (Mass Movement) का रूप दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हरियाली का संरक्षण और संवर्धन (Conservation and Augmentation) करना है।
 - **लक्ष्य:** आगामी वर्षाकाल में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। पिछले मानसून सीजन में 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे।
 - **TOFR योजना:** 'राजस्थान में वन क्षेत्रों के बाहर वृक्ष' (Trees Outside Forests in Rajasthan - TOFR) योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य था।
 - **घोषणाएँ:** घड़ियाल (Gharial) संरक्षण पालीघाट सवाई माधोपुर में, कुरजां (Demoiselle Crane) संरक्षण खींचन जोधपुर में, और गोडावण (Great Indian Bustard) संरक्षण राष्ट्रीय मरु उद्यान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर को वेटलैंड पक्षी संरक्षण केंद्र (Wetland Birds Conservation Centre) के रूप में विकसित करना।
- संभावित प्रश्न (Potential Questions):
 - 'हरियाली राजस्थान अभियान' और TOFR योजना में क्या अंतर है? ये दोनों राज्य के वन आवरण (Forest Cover) को बढ़ाने में कैसे सहायक होंगे?
 - खींचन (Khichan) को कुरजां संरक्षण के लिए क्यों चुना गया है, और कुरजां (Demoiselle Crane) की क्या पारिस्थितिकीय भूमिका है?
- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):
 - केवल पौधे लगाना ही काफी नहीं है; पौधों के जीवित रहने की दर (Survival Rate) बढ़ाने के लिए आप क्या प्रशासनिक कदम उठाएंगे?
 - राजस्थान की जलवायु के अनुकूल, देशी वृक्षों (Indigenous Trees) को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

2.3 बाघ परियोजनाएँ (Tiger Projects) और वन्यजीव संरक्षण (Wildlife Conservation)

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):
 - **राजस्थान में बाघ परियोजनाएँ (वर्तमान):**
 1. रणथम्भौर (Ranthambore) (1974),
 2. सरिस्का (Sariska) (1979)
 3. मुकुन्दरा (Mukundra) (2013)
 4. रामगढ़ विषधारी (Ramgarh Vishdhari) (2021) (देश का 52वां)
 5. धौलपुर-करौली (Dholpur-Karauli) (2023) (देश का 55वां)।
 - **प्रस्तावित परियोजना:** कुम्भलगढ़ टाइगर रिजर्व (Kumbhalgarh Tiger Reserve)।

- **सरिस्का मुद्दा:** उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने भक्तों के लिए निजी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंधों में ढील देने की मांग पर सुनवाई की और इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने का सुझाव दिया।
- **टाइगर मैन ऑफ इण्डिया:** जोधपुर निवासी डॉ. कैलाश साँखला।
- **गिद्ध ब्रिडिंग कॉलोनी (Vulture Breeding Colony):** कोटा स्थित मुकुंदरा हिल्स में साउथ-ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी ब्रिडिंग कॉलोनी स्थित है।
- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**
 - राजस्थान में बाघों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रमुख प्रयास क्या हैं?
 - सरिस्का टाइगर रिजर्व (Sariska Tiger Reserve) के संदर्भ में विकास और वन्यजीव संरक्षण (Development vs. Conservation) के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है?
- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**
 - क्या टाइगर रिजर्व (Tiger Reserve) के कोर ज़ोन (Core Zone) में पर्यटन (Tourism) की अनुमति दी जानी चाहिए? अपने विचार तर्क सहित प्रस्तुत करें।
 - गिद्धों की घटती संख्या के लिए डाइक्लोफेनाक (Diclofenac) कैसे जिम्मेदार है?

2.4 छठवां टाइगर रिजर्व: कुंभलगढ़ (Proposed 6th Tiger Reserve)

यह राजस्थान में बाघों के आवास (Tiger Habitat) और पर्यटन (Tourism) के विस्तार की नवीनतम योजना है।

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**
 - **प्रस्तावित रिजर्व:** राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने अगस्त 2023 में कुंभलगढ़ को राजस्थान का छठवां टाइगर रिजर्व (Sixth Tiger Reserve) बनाने के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी।
 - **विस्तार क्षेत्र:** यह टाइगर रिजर्व पाँच जिलों उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर, पाली और सिरोही के हिस्सों में फैला होगा, जिसका कुल क्षेत्रफल 1397 वर्ग किलोमीटर प्रस्तावित है।
 - **उद्देश्य:** वन्यजीवों के संरक्षण, जैव विविधता (Biodiversity) को बढ़ावा देने और क्षेत्र में पर्यटन (Tourism) को गति देने के लिए।
 - **वर्तमान रिजर्व:** राजस्थान में अब तक 5 टाइगर रिजर्व हैं: रणथम्भौर, सरिस्का, मुकुन्दरा, रामगढ़ विषधारी (4वां) और धौलपुर-करौली (5वां)।
- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**
 - कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का प्रस्ताव किस संदर्भ में आया है?
 - यह रणथम्भौर और सरिस्का पर बाघों के दबाव को कम करने में कैसे मदद करेगा?
 - कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य (Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary) के प्रमुख वन्यजीव कौन से हैं?
- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**
 - क्या एक टाइगर रिजर्व का पाँच जिलों में फैलना प्रबंधन (Management) और समन्वय (Coordination) के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं होगा?
 - टाइगर सफारी (Tiger Safari) की अनुमति कोर एरिया (Core Area) में दी जानी चाहिए या बफर एरिया (Buffer Area) में?

2.5 आर्द्रभूमि प्रबंधन और रामसर साइट्स (Wetlands and Ramsar Sites)

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**
 - **आयोजक:** राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी (Rajasthan State Wetland Authority) और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उदयपुर में कार्यशाला का आयोजन।
 - **रामसर साइट्स (Ramsar Sites)** - राजस्थान: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर, 1981), सांभर झील (जयपुर, 1990), खिचन वेटलैंड (फलोदी/जोधपुर, 2025) 106, मेनार वेटलैंड (उदयपुर, 2025)।
 - **वेटलैंड सिटी मान्यता:** इंदौर (मध्य प्रदेश) और उदयपुर (राजस्थान) रामसर कन्वेंशन के वेटलैंड सिटी प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त करने वाले पहले दो भारतीय शहर हैं।
 - **परिचय:** उदयपुर शहर पाँच प्रमुख आर्द्रभूमियों - पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलई से घिरा हुआ है।

- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**

- राजस्थान की रामसर साइट्स (Ramsar Sites) कौन-सी हैं, और उनकी पारिस्थितिकीय विशेषताएँ (Ecological Features) क्या हैं?
- उदयपुर को 'वेटलैंड सिटी' मान्यता मिलने का क्या महत्व है, और यह शहर की पारिस्थितिकी को कैसे प्रभावित करेगा?

- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

- राजस्थान में झीलों और आर्द्रभूमियों के संरक्षण के सामने प्रमुख चुनौतियाँ (जैसे अतिक्रमण, प्रदूषण) क्या हैं?
- 'रामसर कन्वेंशन' क्या है, और भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है?

2.6 अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**

- **शुभारंभ:** प्रधानमंत्री द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) के अवसर पर।
- **प्रेरणा:** अफ्रीका की 'ग्रेट ग्रीन वॉल' परियोजना से प्रेरित
- **उद्देश्य:** अरावली पर्वत श्रृंखला (Aravalli Range) के चारों ओर 5 किलोमीटर का बफ़र ज़ोन (Buffer Zone) बनाकर थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर विस्तार को रोकना।
- **शामिल राज्य/केंद्र शासित प्रदेश:** हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली।
- **योजना:** बंजर और अवक्रमित वन भूमि पर पेड़ों और झाड़ियों की देशी प्रजातियों (Native Species) के पौधे लगाए जाएंगे।

- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**

- 'अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट' क्या है और मरुस्थलीकरण को रोकने में इसकी क्या भूमिका है?
- यह परियोजना 'ग्रेट ग्रीन वॉल' परियोजना से किस प्रकार प्रेरित है?

- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

- अरावली पर्वतमाला के पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem) के लिए सबसे बड़े खतरे क्या हैं? (जैसे- अवैध खनन, अनियंत्रित शहरीकरण)
- मरुस्थलीकरण से निपटने में 'देशी प्रजातियों' के रोपण का क्या महत्व है?

2.7 राजस्थान में जलवायु परिवर्तन नीति (Climate Change Policy) और चुनौतियाँ

यह राज्य के पर्यावरण शासन (Environmental Governance) और दीर्घकालिक रणनीति (Long-term Strategy) का हिस्सा है।

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**

- **चुनौतियाँ:** पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीकरण (Desertification), जल संकट (Water Crisis), भूमि क्षरण (Land Degradation), और जैव विविधता के ह्रास (Loss of Biodiversity) जैसी समस्याओं से गंभीर रूप से प्रभावित है।
- **प्रभाव:** अनियमित वर्षा (Erratic Rainfall) और लंबे सूखे की अवधि मिट्टी के कटाव (Soil Erosion) को बढ़ावा देती है।
- **नीति के लक्ष्य:** कम पानी की खपत वाली फसलों को प्रोत्साहित करना और फसल विविधीकरण (Crop Diversification) को बढ़ाना। भूगर्भ जल के सीमा से अधिक दोहन की जांच करना और पारंपरिक जल संचयन प्रणाली का संरक्षण करना। वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण (Tree Outside Forest - TOF) को प्रोत्साहित करना और मरुस्थलीकरण रोकने में वनों की भूमिका की रणनीति बनाना। सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) को बढ़ावा देना और कचरे से ऊर्जा (Waste-to-Energy) प्राप्त करने की तकनीकों को बढ़ावा देना।

- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**

- राजस्थान के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभाव क्या हैं, और राज्य की जलवायु परिवर्तन नीति इन प्रभावों से निपटने के लिए क्या रणनीतियाँ सुझाती है?
- "मरुस्थलीकरण" क्या है, और आप इसे रोकने के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या विशिष्ट उपाय करेंगे?

- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

- क्या भिवाड़ी (Bhiwadi) जैसे शहरों का अत्यधिक प्रदूषित होना (विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल) राज्य की औद्योगिक नीति में किसी कमी को दर्शाता है?
- सिलिकोसिस (Silicosis) की समस्या क्या है, और जल संरक्षण का इससे क्या संबंध है, जैसा कि बरकी गाँव के उदाहरण में देखा गया है?

2.8 प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध अभियान: 'क्लीनिंग अरावली'

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **थीम:** विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम "वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण का अन्त" थी।
- **स्थानीय पहल:** राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड (Rajasthan State Biodiversity Board) द्वारा नींदड़ के अरावली पहाड़ियों के जंगल में 'क्लीनिंग अरावली' (Cleaning Arawali) कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें प्लास्टिक कचरे का एकत्रण किया गया।
- **जागरूकता:** विद्याधर नगर के आंगनवाड़ी केंद्र में महिलाओं और युवाओं को प्लास्टिक के दुष्प्रभाव बताकर कपड़े का बैग (Cloth Bags) वितरित किया गया।
- **अंतरराष्ट्रीय दिवस:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उदयपुर (राजस्थान) में जैव विविधता और जैव संसाधनों पर एक प्रदर्शनी के साथ अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 मनाया।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- अरावली पहाड़ियों (Aravalli Hills) जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण का जैव विविधता पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है?
- आप एक शहर में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए कपड़े के बैग वितरण से आगे बढ़कर क्या दीर्घकालिक समाधान (Long-term Solutions) अपनाएंगे?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- आप राजस्थान में ग्रामीण स्तर पर ई-कचरा (E-Waste) प्रबंधन के लिए कौन सी प्रभावी रणनीति सुझाएंगे?
- 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' (Biodiversity Hotspot) और 'जैव विविधता बोर्ड' (Biodiversity Board) की भूमिका में क्या अंतर है?

भारत और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे (India and International Issues)

3. जलवायु शासन और वैश्विक पहल (Climate Governance and Global Initiatives)

3.1 पर्यावरण-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने वाला सुप्रीम कोर्ट

यह न्यायशास्त्र (Jurisprudence) और पर्यावरण संरक्षण (Environmental Protection) में भारत के वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है।

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **वैश्विक पहल:** भारत का सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों में मानव-केंद्रित (human-centric) से पर्यावरण-केंद्रित (environment-centric) अप्रोच अपनाने वाला विश्व का पहला न्यायालय बन गया है।
- **दृष्टिकोण का आधार:** यह अप्रोच संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और उसके सभी घटकों की भलाई को प्राथमिकता देती है, प्रकृति को केवल मानव उपयोग के नज़रिए से नहीं, बल्कि स्वयं प्रकृति के अस्तित्व और हित के लिए भी मूल्यवान मानती है।
- **संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग:** सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) और अनुच्छेद 142 (पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश देने का अधिकार) का उपयोग किया।
- **समर्थन करने वाले संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A (G), और सार्वजनिक न्यास का सिद्धांत (Public Trust Doctrine)।
- **ऐतिहासिक फैसले:** टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (2012) केस में 'वन' की परिभाषा का विस्तार किया गया।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण न्यायशास्त्र (Environmental Jurisprudence) में मानव-केंद्रित से पर्यावरण-केंद्रित दृष्टिकोण में कैसे बदलाव किया है?
- 'सार्वजनिक न्यास का सिद्धांत' (Public Trust Doctrine) क्या है, और यह पर्यावरण संरक्षण में कैसे लागू होता है?

- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

- क्या न्यायालयों का इतना अधिक पर्यावरण-केंद्रित होना आर्थिक विकास (Economic Development) में बाधा नहीं डालता? आपका क्या दृष्टिकोण है?
- गोदावर्मन केस को 'ग्रीन मैन' केस क्यों कहा जाता है, और इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा?

3.2 COP30: जलवायु वित्त और व्यापार (Climate Finance and Trade)

यह अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ता (International Climate Negotiations) और ग्लोबल साउथ (Global South) की स्थिति को दर्शाता है।

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**

- **नेतृत्व:** भारत ने COP30 (Belém, Brazil) में BASIC (Brazil, South Africa, India, China) और Like-Minded Developing Countries (LMDC) समूहों की ओर से वक्तव्य दिया।
- **मुख्य मांग:** भारत ने जलवायु वित्त (Climate Finance) के लिए एक स्पष्ट और सार्वभौमिक रूप से सहमत परिभाषा (Universally Agreed Definition) की मांग की, और अनुकूलन (Adaptation) के लिए सार्वजनिक वित्त को बढ़ाने का आह्वान किया।
- **व्यापार पर चेतावनी:** भारत ने चेतावनी दी कि एकतरफा जलवायु-संबंधी व्यापार उपाय (Unilateral Climate-related Trade Measures) संरक्षणवाद (Protectionism) के उपकरण बन सकते हैं, जो बहुपक्षीय सहयोग (Multilateral Cooperation) को कमजोर करते हैं।
- **सिद्धांत:** 'इक्विटी' (Equity) और CBDR-RC (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities) के सिद्धांतों को वैश्विक जलवायु शासन का आधार बताया।

- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**

- COP30 में भारत ने BASIC समूह का नेतृत्व करते हुए क्या प्रमुख मांगें रखीं?
- भारत क्यों मानता है कि कुछ जलवायु नीतियां 'संरक्षणवाद' का रूप ले सकती हैं? उदाहरण देकर समझाएं।

- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

- ग्लोबल गोल ऑन अडैप्टेशन (GGA) क्या है, और यह विकासशील देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
- जलवायु वित्त पर विकसित देशों के बीच विश्वास की कमी (Trust Deficit) को कैसे दूर किया जा सकता है?

3.3 COP-29 के परिणाम और भारत की निराशा

यह जलवायु वित्त (Climate Finance) और वैश्विक उत्तरदायित्व (Global Responsibility) का संवेदनशील मुद्दा है।

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**

- **भारत की निराशा:** COP-29 में नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (New Collective Quantified Goal - NCQG) के परिणाम पर भारत ने निराशा व्यक्त की।
- **कारण:** भारत का मानना है कि यह विकासशील देशों (Developing Nations) की आवश्यकताओं को संबोधित नहीं करता और साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।
- **लक्ष्य बनाम आवश्यकता:** COP-29 में 2035 तक प्रति वर्ष 300 बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया, जबकि UNFCCC के अनुसार विकासशील देशों की वित्तीय आवश्यकताएँ 2030 तक 5.1 - 6.8 ट्रिलियन डॉलर (प्रति वर्ष 455 - 584 बिलियन डॉलर) तक हो सकती हैं।
- **भारत का प्रस्ताव:** भारत ने "1.3T के लिए बाकू से बेलेम रोडमैप" पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**

- जलवायु वित्त (Climate Finance) के मुद्दे पर 'साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व' (CBDR) सिद्धांत की व्याख्या करें।
- विकसित देशों (Developed Countries) पर जलवायु वित्त प्रदान करने की 'नैतिक' और 'कानूनी' जिम्मेदारी क्यों है?

- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

- भारत में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आपको सबसे बड़ी बाधा क्या लगती है, और आप इसे कैसे दूर करेंगे?
- भारत के 'पंचामृत' लक्ष्य (Panchamrit Targets) क्या हैं?

3.4 अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA)

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **शुभारंभ:** 9 अप्रैल, 2023 को 'प्रोजेक्ट टाइगर' के 50 वर्ष पूरे होने पर कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया।
- **उद्देश्य:** बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा - इन 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना।
- **भारत में पाई जाने वाली प्रजातियाँ:** 7 में से 5 प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं (बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता)।
- **मुख्यालय:** इसका मुख्यालय और सचिवालय भारत में स्थापित किया जाएगा।
- **अध्यक्ष/महानिदेशक:** केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) क्या है और भारत के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?
- 'प्रोजेक्ट चीता' और 'प्रोजेक्ट लायन' का IBCA के उद्देश्यों के साथ क्या संबंध है?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- भारत वैश्विक वन्यजीव संरक्षण में नेतृत्व क्यों करना चाहता है? क्या यह 'सॉफ्ट पावर' (Soft Power) का एक हिस्सा है?
- आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (CDRI) और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसे वैश्विक संगठनों में भारत की क्या भूमिका है?

3.5 ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना (GNIP)

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **नोडल एजेंसी:** नीति आयोग (NITI Aayog) इसका नेतृत्व कर रहा है, और इसे अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO) के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
- **अवसंरचना परियोजनाएँ:** गैलेथिया बे (Galathea Bay) में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT), एक ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक टाउनशिप, आदि।
- **प्रमुख मुद्दे:** जनजातीय अधिकार (शोम्पेन और निकोबारी आदिवासियों का अधिवास स्थल)। जैव विविधता (गैलेथिया बे संकटग्रस्त लेदरबैक कछुए और निकोबार मेगापोड के नेस्टिंग स्थल हैं)।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना क्या है, और इससे संबंधित प्रमुख पर्यावरणीय और जनजातीय चिंताएँ क्या हैं?
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act, 2006) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) को क्या अधिकार प्राप्त हैं?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्या भारत को अंडमान और निकोबार जैसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों में विकास परियोजनाओं को रोकना चाहिए? विकास और संरक्षण में संतुलन कैसे बिठाया जाए?
- आप एक अधिकारी के रूप में इस परियोजना से प्रभावित जनजातियों के अधिकारों और आजीविका (Livelihood) की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे?

3.6 वन संरक्षण के प्रयास और 'ग्रेटर ओपननेस' 🌳

यह भारत की वन्यजीव शासन (Wildlife Governance) और वन प्रबंधन (Forest Management) पर बहस से संबंधित है।

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **वन संरक्षण पर जोर:** भारत के जंगलों में देश का भविष्य निहित है, और वन संरक्षण प्रयासों को फिर से मजबूत करने की आवश्यकता है।
- **वन्यजीव शासन में पारदर्शिता:** भारत में वन्यजीव शासन (Wildlife Governance) में अधिक पारदर्शिता (Greater Openness) और भागीदारी की मांग है।
- **उदाहरण:** सुप्रीम कोर्ट द्वारा झारखंड के सरंडा (Saranda) में 314 वर्ग किमी के साल वनों (Sal Forest) को संरक्षण प्रदान करना।
- **जैव विविधता का महत्व:** भारत ने 'इक्विटी' (Equity) और 'जलवायु न्याय' (Climate Justice) के सिद्धांतों को दोहराते हुए COP30 में वैश्विक जलवायु शासन (Global Climate Regime) के लिए आधारभूत सिद्धांतों पर जोर दिया।

- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**

- वन संरक्षण (Forest Conservation) और वन्यजीव प्रबंधन (Wildlife Management) में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता क्यों है?
- 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' और 'वन संरक्षण अधिनियम' के बीच संघर्ष के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

- बायोस्फीयर रिजर्व (Biosphere Reserves) क्या होते हैं, और वे राष्ट्रीय उद्यानों (National Parks) और वन्यजीव अभयारण्यों (Wildlife Sanctuaries) से किस प्रकार भिन्न हैं?
- वन क्षेत्रों में अतिक्रमण (Encroachment) और मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-Wildlife Conflict) को कम करने के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे?

4. प्रदूषण और आपदा प्रबंधन (Pollution and Disaster Management)

4.1 क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (CRI) 2026 और भारत की संवेदनशीलता

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**

- **CRI 2026:** यह रिपोर्ट दर्शाती है कि विश्व स्तर पर शीर्ष 10 CRI देश ग्लोबल साउथ (Global South) से हैं।
- **भारत की रैंक/वल्नरेबिलिटी:** 2024 में, भारत जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों में 15वें स्थान पर रहा। 1995-2024 के बीच, भारत में 430 अत्यधिक मौसमी घटनाओं (Extreme Weather Events - EWEs) के कारण 170 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।
- **प्रमुख प्रभाव:** जल संकट (हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना, भूजल का तेज़ी से घटना, आर्सेनिक संदूषण), तटीय खतरे (बढ़ते समुद्र स्तर, लवणीकरण)।
- **आर्थिक लागत:** वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि जलवायु संकट 2100 तक भारत की GDP में 6.4 - 10 % की कटौती कर सकता है।

- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**

- क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (CRI) 2026 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं, और यह भारत के लिए क्या चेतावनी देता है?
- जलवायु परिवर्तन किस प्रकार भारत के चार जैव विविधता हॉटस्पॉट (Biodiversity Hotspots) (हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड, इंडो-बर्मा) को खतरे में डाल रहा है?

- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

- 'ब्लैक कार्बन' (Black Carbon) क्या है, और यह हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र (Himalayan Ecosystem) को कैसे नुकसान पहुंचाता है?
- क्या भारत में आपदा शमन कोष (Disaster Mitigation Fund) पर्याप्त हैं? आपदा राहत और शमन (Relief and Mitigation) में क्या अंतर है?

4.2 ओजोन प्रदूषण और फसल उत्पादकता पर प्रभाव

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**

- **अध्ययन:** आईआईटी खड़गपुर (IIT Kharagpur) के अध्ययन के अनुसार, सतही ओजोन प्रदूषण (Surface Ozone Pollution) ग्रामीण भारत को प्रभावित कर रहा है।
- **फसल उत्पादकता में गिरावट:** गेहूँ (Wheat) में 20% तक; चावल (Rice) व मक्का (Maize) में 7% तक।
- **जोखिम:** प्रमुख कृषि क्षेत्रों में ओजोन का जोखिम सुरक्षित सीमा से छह गुना अधिक हो सकता है।
- **परिणाम:** यह SDG 1 (गरीबी उन्मूलन) और SDG 2 (भुखमरी समाप्त करना) की प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है।
- **सतही ओजोन निर्माण:** नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं से।

- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**

- सतही ओजोन प्रदूषण (Surface Ozone Pollution) किस प्रकार भारत की खाद्य सुरक्षा (Food Security) को प्रभावित कर रहा है?
- सतही ओजोन (Surface Ozone) और समतापमंडलीय ओजोन (Stratospheric Ozone) में क्या अंतर है?

- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

- आप एक प्रशासक के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में ओजोन प्रदूषण के स्रोतों (जैसे VOCs) को कैसे नियंत्रित करेंगे?
- क्लाइमेट चेंज (Climate Change) और प्रदूषण (Pollution) किस प्रकार भारत के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्रभावित कर रहे हैं?

4.3 पराली सुरक्षा बल और पराली दहन

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**

- **निर्देश:** वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को पराली जलाने पर रोक लगाने हेतु पराली संरक्षण बल (Parali Suraksha Bal) स्थापित करने का निर्देश दिया।
- **पराली दहन से उत्सर्जन:** एक टन पराली जलाने पर लगभग 1,460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) और 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) उत्सर्जित होती है।
- **तकनीकी उपाय:** टर्बो हैप्पी सीडर मशीन (Turbo Happy Seeder) और पूसा डीकंपोजर (Pusa Decomposer)।

- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**

- CAQM द्वारा पराली सुरक्षा बल के गठन का निर्देश क्यों दिया गया?
- पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण में 'पर्टिकुलेट मैटर' (Particulate Matter - PM) की भूमिका क्या है?

- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

- क्या पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाना एक न्यायसंगत (justified) समाधान है? आप कोई वैकल्पिक, किसान-हितैषी मॉडल (Farmer-Friendly Model) सुझाएँ।
- टर्बो हैप्पी सीडर या पूसा डीकंपोजर जैसी तकनीकों को किसानों तक पहुँचाने में क्या चुनौतियाँ हैं?

4.4 विश्व पर्यावरण दिवस (WED) 2025

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**

- **मेज़बानी (Host):** कोरिया गणराज्य (Republic of Korea)।
- **थीम (Theme):** "बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन" (Beat Plastic Pollution)।
- **प्लास्टिक पर भारत के प्रयास:** एकल-उपयोग प्लास्टिक (Single-Use Plastic) पर प्रतिबंध, EPR पोर्टल और 'प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021' जैसे कदम उठाए हैं।
- **एक पेड़ माँ के नाम अभियान:** 5 जून, 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान पहल को आगे बढ़ाया गया।

- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**

- 'बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन' थीम के संदर्भ में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में भारत की विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) योजना की भूमिका क्या है?
- 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान की पर्यावरणीय प्रासंगिकता और सामाजिक प्रासंगिकता क्या है?

- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

- प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में 'चक्रीय अर्थव्यवस्था' (Circular Economy) के महत्व को समझाएँ।
- माइक्रोप्लास्टिक (Microplastics) क्या हैं और वे मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं?

4.5 क्लाउडबर्स्ट (बादल फटना)

यह एक तीव्र मौसमी घटना (Weather Event) और आपदा प्रबंधन (Disaster Management) से संबंधित है।

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**

- **परिभाषा (IMD के अनुसार):** यह एक ऐसी घटना है, जिसमें 20 - 30 वर्ग किमी के क्षेत्र में 100 मिमी/घंटा से अधिक वर्षा होती है।
- **संबंधित बादल:** प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में क्यूमुलोनिम्बस बादलों (Cumulonimbus Clouds) से जुड़ी होती है।
- **पहाड़ी क्षेत्र अधिक संवेदनशील क्यों:** खड़ी ढलानें, पर्वतीय उत्थान, और चट्टानी भूभाग।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming) से वायुमंडल में 7% अधिक जलवाष्प जमा हो सकता है, जिससे बादल फटने की घटनाएँ बढ़ सकती हैं।

- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**

- 'बादल फटने' (Cloudburst) की घटना को परिभाषित करें और यह सामान्य भारी वर्षा से किस प्रकार भिन्न है?
- पहाड़ी क्षेत्र (Hilly Areas) बादल फटने की घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील क्यों होते हैं?

- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

- क्या भारत में बादल फटने की घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी (Accurate Prediction) करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र है?
- यदि आप उत्तरकाशी के जिलाधिकारी होते, तो आपदा प्रबंधन (Disaster Management) के लिए आपके तत्काल कदम क्या होते?

4.6 भारत में रामसर स्थलों की बढ़ती संख्या और महत्व

यह भारत की आर्द्रभूमि (Wetlands) संरक्षण के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**

- **वर्तमान संख्या:** 2025 तक भारत में रामसर स्थलों (Ramsar Sites) की कुल संख्या 93 हो गई है।
- **नए स्थल (2025):** 2025 में 4 नई रामसर साइटें जोड़ी गईं, जिनमें राजस्थान की मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और खिचन वेटलैंड शामिल हैं।
- **सर्वाधिक स्थल:** तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर साइटें (18-20 स्थल) हैं।
- **हस्ताक्षर:** भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन (Ramsar Convention) को अपनाया था।
- **महत्व:** रामसर दर्जा संरक्षण प्रयासों, वित्तपोषण (Financing) और वैश्विक मान्यता को बढ़ाता है।

- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**

- भारत में रामसर स्थलों की संख्या में अचानक वृद्धि क्यों हुई है? यह वैश्विक मंच पर क्या दर्शाता है?
- आर्द्रभूमियां (Wetlands) बाढ़ नियंत्रण (Flood Control) और जलवायु परिवर्तन शमन (Climate Change Mitigation) में कैसे सहायक होती हैं?

- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

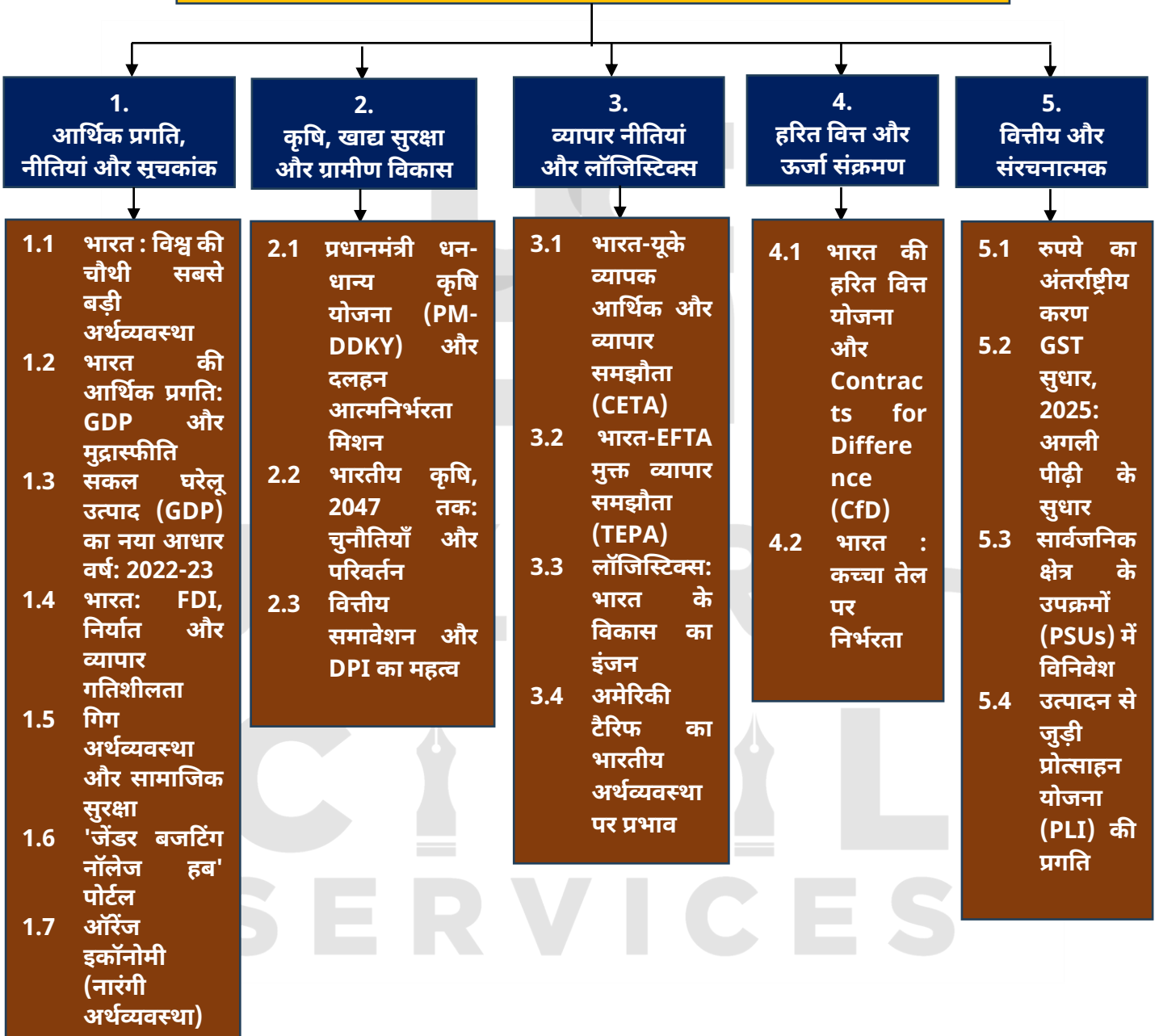
- रामसर साइट्स को मॉन्ट्रो रिकॉर्ड (Montreux Record) में क्यों रखा जाता है?
- 'वेटलैंड सिटी प्रत्यायन कार्यक्रम' (Wetland City Accreditation Programme) क्या है, और यह शहरों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

□□□

CIVIL
SERVICES

02. भारत और विश्व के आर्थिक मुद्दे (Economic Issues of India and the World)

भारत और विश्व के आर्थिक मुद्दे



RAS 2024 INTERVIEW GUIDANCE PROGRAM



डॉ. ललित के. पंवार सर
(रिटायर्ड आईएएस) पूर्व अध्यक्ष, RPSC



अशोक गोयल
(Rank 20, RAS 2023)



डॉ. ए. के. मलिक सर
विमान संचालन एवं वायुमार्ग नियंत्रण



दीपल खानन सर
सिखित संचालन एवं वायुमार्ग नियंत्रण



Scan the QR Code to watch the Detailed video solution of Probable & Counter Questions



1. आर्थिक प्रगति, नीतियां और सूचकांक (Economic Progress, Policies, and Indices)

1.1 भारत - विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **घोषणा:** नीति आयोग के CEO बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने IMF के आँकड़ों के हवाले से भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया।
- **GDP अनुमान:** IMF की रिपोर्ट (अप्रैल 2025) के अनुसार, भारत का GDP 4.19 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित है, जो जापान के 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
- **शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाएँ:** संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी, भारत और जापान।
- **भविष्य की संभावना:** आगामी 2.5-3 वर्षों में भारत जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।
- **आर्थिक वृद्धि दर:** भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसकी वार्षिक संवृद्धि दर अगले दो वर्षों तक 6 % से अधिक रहने का अनुमान है।
- **उपलब्धि के कारक:** जनसांख्यिकीय लाभांश (औसत आयु 29 वर्ष), घरेलू मांग में वृद्धि, GST और IBC जैसे सुधार, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (UPI, जैम ट्रिनिटी)।
- **घरेलू विकास:** भारत की GDP 2014 से दोगुनी होकर 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गई, और प्रति व्यक्ति आय 1438 डॉलर (2014) से बढ़कर 2880 डॉलर (2025) हो गई।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- भारत के जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के निहितार्थ (Implications) क्या हैं?
- भारत की उच्च आर्थिक वृद्धि दर में "जनसांख्यिकीय लाभांश" (Demographic Dividend) और "घरेलू मांग" (Domestic Demand) की क्या भूमिका है?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्या क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parity - PPP) के आधार पर भी भारत की रैंकिंग समान है?
- प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) के मामले में भारत अभी भी जापान से काफी पीछे क्यों है, और इस अंतर को कम करने के लिए क्या करना चाहिए?

1.2 भारत की आर्थिक प्रगति: GDP और मुद्रास्फीति

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **GDP वृद्धि:** 2024-25 में वास्तविक GDP बढ़ोतरी का अनुमान 6.5 प्रतिशत था, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है।
- **मुद्रास्फीति (Inflation):** मई 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति दर गिरकर 2.82 प्रतिशत रही, जो फरवरी 2019 के बाद का निम्नतम स्तर है।
- **RBI का लक्ष्य:** रिजर्व बैंक का मानना है कि मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के अपने मध्यम अवधि के लक्ष्य के अनुरूप रहेगी।
- **आर्थिक लचीलापन:** मजबूत घरेलू मांग, घटती मुद्रास्फीति, मजबूत पूंजी बाजार और बढ़ते निर्यात के कारण देश की तस्वीर व्यापक आर्थिक लचीलेपन (Macroeconomic Resilience) और संतुलन की है।
- **निर्यात:** कुल निर्यात 2024-25 में रिकॉर्ड 824.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
- **जीडीपी आकार:** 2014-15 में मौजूदा कीमतों पर GDP ₹106.57 लाख करोड़ थी, जो 2024-25 में बढ़कर ₹331.03 लाख करोड़ होने की उम्मीद है (दस साल में लगभग तीन गुना उछाल)।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- वास्तविक GDP (Real GDP) में 6.5 % की बढ़ोतरी के बावजूद मुद्रास्फीति (Inflation) इतनी कम कैसे रही?
- भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत 'घरेलू मांग' (Domestic Demand) के पीछे क्या कारण हैं, और यह वैश्विक मंदी के माहौल में कैसे मदद करती है?
- "पड़ोस में उथल-पुथल" (जैसे पड़ोसी देशों में भुगतान संतुलन संकट) के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था इतनी स्थिर (Stable) कैसे बनी हुई है?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्या निम्न मुद्रास्फीति दर किसानों और उत्पादकों के लिए चिंता का विषय हो सकती है?
- 'नॉमिनल GDP' (Nominal GDP) और 'वास्तविक GDP' (Real GDP) में क्या अंतर है? भारत के आर्थिक स्वास्थ्य को मापने के लिए आप किस पर अधिक भरोसा करेंगे?

1.3 सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का नया आधार वर्ष: 2022-23**● प्रमुख तथ्य (Factual Details):**

- **संशोधन:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) ने GDP के आधार वर्ष (Base Year) को **2011-12 से संशोधित कर 2022-23** करने की घोषणा की है।
- **कार्यान्वयन:** संशोधित आँकड़े 27 फरवरी, 2026 को जारी किए जाएंगे।
- **समिति:** विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में **राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर 26-सदस्यीय सलाहकार समिति (ACNAS)** का गठन किया गया।
- **आवश्यकता:** आधार वर्ष संशोधन से **नए उद्योगों** (जैसे डिजिटल सेवाएँ, गिग इकोनॉमी) को शामिल करना, **बेहतर डेटा स्रोतों** को अपनाना और **वास्तविक आर्थिक विकास का अधिक सटीक माप** सुनिश्चित होता है।
- **तर्क:** अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करना (कृषि-प्रधान से सेवा-प्रधान में परिवर्तन), डेटा सटीकता में सुधार, और मुद्रास्फीति विकृतियों को दूर करना।
- **चुनौतियाँ:** कॉरपोरेट डेटा (MCA-21) पर अत्यधिक निर्भरता से छोटे उद्यमों की कवरेज में कमी, **एकल बनाम द्वैध अपस्फीति** (Single vs. Double Deflation) पर चर्चा, और असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) का अधूरा डेटा।
- **सुधार के उपाय:** हाइब्रिड डेटा दृष्टिकोण (MCA-21, ASI, IIP, NSSO का मिश्रण) अपनाना और **दोहरी अपस्फीति** की ओर परिवर्तन।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- GDP के आधार वर्ष को संशोधित करने की आवश्यकता क्यों है, और नया आधार वर्ष 2022-23 क्या संरचनात्मक परिवर्तन प्रतिबिंबित करेगा?
- GDP की गणना में असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) से डेटा एकत्र करने की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- आप एक प्रशासक के रूप में असंगठित क्षेत्र की GDP भागीदारी को अधिक विश्वसनीय (Reliable) बनाने के लिए क्या तकनीकी समाधान (Technical Solutions) सुझाएंगे?
- "द्वैध अपस्फीति" (Double Deflation) पद्धति "एकल अपस्फीति" (Single Deflation) से बेहतर क्यों मानी जाती है?

1.4 भारत का बाहरी क्षेत्र: FDI, निर्यात और व्यापार गतिशीलता (External Sector: FDI, Exports and Trade Dynamics)**● प्रमुख तथ्य (Factual Details):**

- **FDI प्रवाह:** वित्त वर्ष 2024-25 में FDI प्रवाह बढ़कर **81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर** (प्रोविजनल) हो गया, जो वित्त वर्ष 2023-24 से 14 % अधिक है।
- **FDI में वृद्धि वाले क्षेत्र:** सेवा क्षेत्र (नेतृत्व किया), कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, और विनिर्माण क्षेत्र (18 % की बढ़ोतरी)।
- **विदेशी मुद्रा भंडार:** 20 जून 2025 तक **697.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर**, जो 11 महीने से अधिक के माल आयात को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
- **चालू खाता अधिशेष (Current Account Surplus):** 2024-25 की चौथी तिमाही में **13.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का अधिशेष दर्ज किया गया, जो मजबूत सेवा निर्यात और विदेशों से धन के लगातार आने के कारण हुआ।
- **कुल निर्यात:** 2024-25 में **824.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के नए उच्चतम स्तर को छू गया।
- **सेवा निर्यात:** 2024-25 में 387.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो वैश्विक ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएँ देने की भारत की क्षमता को रेखांकित करता है।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- भारत के बाहरी क्षेत्र (External Sector) की मजबूती के प्रमुख संकेतक (Indicators) क्या हैं, और ये वैश्विक झटकों से निपटने में कैसे मदद करते हैं?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- चालू खाता घाटा (Current Account Deficit - CAD) और चालू खाता अधिशेष (Current Account Surplus) में क्या अंतर है? भारत के लिए 0.6 % का CAD कितना प्रबंधनीय है?

1.5 गिग अर्थव्यवस्था (Gig Economy) और सामाजिक सुरक्षा (Social Security)

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **घोषणा:** केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार गिग वर्कर्स को पेंशन के साथ **कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)** की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
- **परिभाषा:** गिग अर्थव्यवस्था एक मुक्त बाज़ार प्रणाली है, जिसमें संगठन अल्पकालिक जुड़ाव के लिये **स्वतंत्र श्रमिकों** या **कार्यकर्ता** के साथ अनुबंध करते हैं।
- **गिग वर्कर:** एक ऐसा व्यक्ति जो पारंपरिक "नियोक्ता-कर्मचारी संबंध" के बाहर काम करता है।
- **लाभ (श्रमिक परिप्रेक्ष्य):** स्वतंत्रता, लचीलापन (कार्य के घंटे स्वयं चुनने की छूट) और अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर।
- **लाभ (व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य):** प्रभावी लागत (भौतिक कार्यस्थलों, लाभों पर बचत), कोई मध्यस्थ नहीं, और अद्वितीय अवसर।
- **प्रमुख कंपनियां:** ओला, उबर, ज़ोमैटो और स्विगी।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- गिग अर्थव्यवस्था (Gig Economy) को परिभाषित करें, और भारत में इसके विस्तार के क्या कारण हैं?
- सरकार गिग वर्कर्स को ESIC जैसी सामाजिक सुरक्षा (Social Security) देने की पहल क्यों कर रही है?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में क्या चुनौतियाँ हैं, खासकर जब उनका कोई पारंपरिक नियोक्ता नहीं होता है?
- क्या गिग अर्थव्यवस्था भारत के विशाल युवा कार्यबल (Young Workforce) के लिए एक स्थायी (Sustainable) आजीविका समाधान है?

1.6 'जेंडर बजटिंग नॉलेज हब' पोर्टल (Gender Budgeting Knowledge Hub)

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **शुभारंभ:** केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने **जेंडर बजटिंग पर राष्ट्रीय परामर्श** के दौरान 'जेंडर बजटिंग नॉलेज हब' पोर्टल का शुभारंभ किया।
- **जेंडर बजटिंग (GB) परिभाषा:** यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सरकारी योजनाओं और बजट में **लैंगिक समानता** को शामिल करता है।
- **उद्देश्य:** यह समझना कि बजट किस प्रकार महिलाओं और पुरुषों के लिए **समान अवसर और अधिकार** सुनिश्चित करने में मददगार हो सकता है।
- **आवश्यकता:** जेंडर-संवेदनशील नीतियाँ, उत्तरदायी शासन व्यवस्था (Responsible Governance) और कानूनी ढाँचे (Legal Framework) को मजबूत करना (जैसे आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013)।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- जेंडर बजटिंग (Gender Budgeting) क्या है, और यह पोर्टल किस प्रकार महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) में मदद करेगा?
- जेंडर बजटिंग को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में लागू करने की क्या आवश्यकता है?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्या भारत का केंद्रीय बजट जेंडर बजटिंग के सिद्धांतों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित करता है?
- जेंडर बजटिंग के सामने कार्यान्वयन (Implementation) की क्या चुनौतियाँ हैं, विशेषकर डेटा और निगरानी (Monitoring) के स्तर पर?

1.7 ऑरेंज इकोनोमी (नारंगी अर्थव्यवस्था)

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **संदर्भ:** प्रधानमंत्री ने वेक्स-2025 (विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन) में भारत की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला, और **"नारंगी अर्थव्यवस्था"** (Orange Economy) की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित किया।
- **परिभाषा:** रचनात्मक अर्थव्यवस्था (Creative Economy) को ऑरेंज इकोनोमी के रूप में जाना जाता है, जो **संस्कृति**, **रचनात्मकता**, **प्रौद्योगिकी** और **आईपी (बौद्धिक संपदा)** को एकीकृत करती है।

- **महत्व:** यह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाती है, और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का समर्थन करने की क्षमता रखती है।
- **विकास दर:** अर्स्ट एंड यंग के अनुसार, भारत की सृजनकर्ता अर्थव्यवस्था 18 % चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने का अनुमान है।
- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**
 - 'ऑरेंज इकोनॉमी' (Orange Economy) क्या है, और भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था के विकास में इसकी क्या क्षमता है?
 - IP (बौद्धिक संपदा) का संरक्षण ऑरेंज इकोनॉमी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**
 - ऑरेंज इकोनॉमी को भारत में बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या नीतिगत हस्तक्षेप (Policy Interventions) किए जा सकते हैं?
 - स्टार्टअप इकोसिस्टम (Startup Ecosystem) ऑरेंज इकोनॉमी के विकास में कैसे योगदान दे सकता है?

2. कृषि, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास (Agriculture, Food Security and Rural Development)

यह खंड कृषि क्षेत्र के संरचनात्मक बदलावों, चुनौतियों और नई योजनाओं पर केंद्रित है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं।

2.1 प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM-DDKY) और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**
 - **PM-DDKY (घोषणा):** केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित; वार्षिक परिव्यय ₹24,000 करोड़; समयावधि 6 वर्ष (2025-26 से 2030-31)।
 - **PM-DDKY (उद्देश्य):** नीति आयोग के आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम से प्रेरित 100 पिछड़े ज़िलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना; बेहतर सिंचाई, भंडारण, ऋण की पहुँच और संधारणीय कृषि पद्धतियों के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करना।
 - **DDKY की विशेषता:** यह योजना 11 केंद्रीय मंत्रालयों की 36 योजनाओं को एकीकृत करती है (जैसे PM-KISAN, PMFBY, PMKSY)।
 - **दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (घोषणा):** केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित; बजट आवंटन ₹1,000 करोड़
 - **दलहन मिशन (उद्देश्य):** 6 वर्ष (2025-26 से 2030-31) में दालों के उत्पादन एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, और 2029 तक आयात पर निर्भरता समाप्त करना।
 - **विशेष फोकस:** तुअर (अरहर), उड़द एवं मसूर के उत्पादन पर।
 - **भारत की दलहन स्थिति:** विश्व स्तर पर सबसे बड़ा उत्पादक (25 %), उपभोक्ता (27 %) और आयातक (14%)।
 - **DDKY के समाधान:** e-NAM और नई PMDDKY ऐप से किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ना, उच्च उत्पादकता वाले बीज/उपकरण, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, और KCC/NABARD के माध्यम से ऋण।
- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**
 - प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM-DDKY) किस प्रकार अन्य कृषि योजनाओं (जैसे PM-KISAN) से भिन्न है, और इसके "एकीकृत कृषि सहायता प्रणाली" का क्या महत्व है?
 - "दलहन आत्मनिर्भरता मिशन" भारत की खाद्य सुरक्षा (Food Security) के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**
 - क्या केवल 100 पिछड़े ज़िलों पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त है, जबकि कृषि संकट राष्ट्रीय स्तर पर है?
 - दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की क्या भूमिका हो सकती है?

2.2 भारतीय कृषि 2047 तक: चुनौतियाँ और परिवर्तन

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**
 - **रिपोर्ट:** ICAR-राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान संस्थान (ICAR-NIAP) ने "भारतीय कृषि 2047 तक" शीर्षक से पॉलिसी पेपर जारी किया।

- **संरचनात्मक परिवर्तन:** भारत खाद्य-अभाव से खाद्य-अधिशेष राष्ट्र तक का सफर तय कर चुका है।
- राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 43 % से घटकर 18 % हो गया है, और कार्यबल में हिस्सेदारी 74 % से घटकर 46 % हो गई है।
- **चुनौतियाँ:** जोतों का घटता आकार (1 हेक्टेयर वाले सीमांत खेतों का अनुपात 68 % तक), उर्वरकों का अधिक उपयोग, अकुशल सिंचाई प्रणाली (भूजल का अत्यधिक दोहन), और जलवायु परिवर्तन का चरम घटनाओं के कारण उत्पादकता में कमी।
- **परिवर्तन की सिफारिशें:** वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, सूक्ष्म सिंचाई, कृषि अनुसंधान एवं विकास में निवेश, और बिजली सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना।
- **आधुनिकीकरण:** AIF (कृषि अवसंरचना कोष) द्वारा भंडारण, कोल्ड चेन और बाजार संपर्क का आधुनिकीकरण। डिजिटल कृषि मिशन और एग्रीस्टैक का उद्देश्य कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक अवसंरचना (DPI) स्थापित करना है।
- **जैविक खेती:** 2025 तक जैविक उत्पादों का बाजार ₹75,000 करोड़ तक पहुंचने वाला है।
- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**
 - भारतीय कृषि में 'जोतों के घटे आकार' (Fragmented Land Holdings) की समस्या को आप कैसे देखते हैं, और इसका समाधान क्या है?
 - जलवायु-प्रतिरोधी फसल किस्मों (Climate-Resilient Crop Varieties) के विकास में ICAR की क्या भूमिका है?
- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**
 - क्या भारत में कृषि के लिए बिजली पर दी जाने वाली भारी सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना उचित है? इसके सामाजिक प्रभाव क्या होंगे?
 - MSME और असंगठित क्षेत्र के लिए कृषि उत्पादों के बाजार पहुंच को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

2.3 वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) और DPI का महत्व

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**
 - **DPI परिभाषा:** डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) नागरिकों, सरकार और कॉर्पोरेट क्षेत्र को सुसंगत, सस्ती और समग्र मूल्य प्रदान करता है। इंडिया स्टैक में आधार, ई-केवाईसी, UPI, और डिजिलॉकर जैसे बिल्डिंग ब्लॉक शामिल हैं।
 - **DPI उपलब्धि:** भारत डिजिटल पहचान (आधार), रियल-टाइम तेज़ भुगतान (UPI), और डेटा अधिकारिता संरक्षण व्यवस्था (DEPA) पर निर्मित प्लेटफॉर्म विकसित करने वाला पहला देश बन गया है।
 - **UPI का प्रभाव:** UPI अब देश में सभी डिजिटल लेनदेन के 85 प्रतिशत और वैश्विक रियल-टाइम डिजिटल भुगतानों के लगभग 50 प्रतिशत को संचालित करता है।
 - **समावेशन योजनाएँ:**
 - **PM जन धन योजना (PMJDY):** 55.98 करोड़ लाभार्थी, जिनमें 55 % से अधिक खाते महिलाओं के पास हैं।
 - **PM सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):** ₹20 के वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा।
 - **अटल पेंशन योजना (APY):** ग्राहकों में 48 % महिलाएं हैं।
 - **PM मुद्रा योजना:** ₹35.13 लाख करोड़ मूल्य के 53.85 करोड़ ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।
 - **वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI Index):** यह 97 संकेतकों पर आधारित है (पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता को मापता है) और 2025 में बढ़कर 67 हो गया, जो 2021 के मुकाबले 24.3 % अधिक है।
- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**
 - डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) भारत में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) के लिए एक "गेम चेंजर" कैसे साबित हुआ है?
 - UPI की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या हैं, और यह वैश्विक स्तर पर वित्तीय समावेशन को कैसे बढ़ावा दे रहा है?
- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**
 - वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI Index) के तीन उप-सूचकांक (पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता) क्या दर्शाते हैं?
 - DPI के बावजूद, हाशिये पर स्थित समुदायों (Marginalized Communities) के लिए डिजिटल समावेशन में क्या चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं?

3. व्यापार नीतियां और लॉजिस्टिक्स (Trade Policies and Logistics)

यह खंड भारत के FTA समझौतों, वैश्विक व्यापार संबंधों, और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधारों पर केंद्रित है।

3.1 भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA)

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **प्रकृति:** व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA), जो एक द्विपक्षीय **मुक्त व्यापार समझौता (FTA)** है।
- **शुल्कों में कमी:** यूके भारत के **99 प्रतिशत** निर्यात पर शुल्क समाप्त करता है।
- **लाभान्वित क्षेत्र:** कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग, रसायन, और ऑटो कंपोनेंट जैसे श्रम-प्रधान और उच्च-विकास वाले क्षेत्र।
- **सेवाएँ और गतिशीलता:** आईटी, स्वास्थ्य सेवा, वित्त, और शिक्षा क्षेत्र के पेशेवरों के लिए आवागमन को आसान बनाया गया (गतिशीलता प्रावधान)।
- **दोहरी अंशदान संधि (DCC):** दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे भारतीय फर्मों और श्रमिकों को **₹4,000 करोड़ से अधिक की बचत** होगी।
- **भारत का बाज़ार खोलना:** भारत ने अपनी **89.5 % टैरिफ लाइनें** खोली हैं।
- **संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा:** भारत ने डेयरी, अनाज, दालें, सोना, प्रयोगशाला में तैयार हरी जैसे **संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा** की है।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- भारत-यूके CETA में "दोहरी अंशदान संधि" (DCC) का क्या महत्व है?
- इस FTA में भारत ने कौन से संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखा है, और यह घरेलू उद्योगों (Domestic Industries) की रक्षा कैसे करेगा?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के बढ़ते व्यापार घाटे (Trade Deficit) से संबंधित क्या चिंताएँ हैं?
- क्या FTA, मेक इन इंडिया (Make in India) पहल के विपरीत नहीं हैं, या वे पूरक (Complementary) हैं?

3.2 भारत-EFTA मुक्त व्यापार समझौता (TEPA)

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **EFTA ब्लॉक:** स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेस्टीन।
- **समझौता:** व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA), मार्च 2024 में अंतिम रूप दिया गया।
- **निवेश प्रतिबद्धता:** EFTA के सदस्य देश **15 वर्षों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की बाध्यकारी निवेश प्रतिबद्धता लाएँगे, जिससे भारत में **1 मिलियन प्रत्यक्ष रोज़गार** सृजित होने की उम्मीद है।
- **बाज़ार पहुँच:** EFTA ने भारत के औद्योगिक और गैर-कृषि उत्पादों के लिये **100 % बाज़ार पहुँच** प्रदान की है।
- **चिंताएँ:** बढ़ता व्यापार घाटा (भारत-आसियान FTA के तहत आयात 44 बिलियन डॉलर तक पहुँचा), गैर-टैरिफ बाधाएँ, और छोटे किसान और MSME जोखिम में।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- भारत-EFTA FTA में EFTA देशों की **100 बिलियन डॉलर** की बाध्यकारी निवेश प्रतिबद्धता का क्या महत्व है?
- FTA से भारत को होने वाले प्रमुख लाभ (जैसे बाज़ार पहुँच, निवेश में वृद्धि) और संबंधित चिंताएँ (जैसे व्यापार घाटा, गैर-टैरिफ बाधाएँ) क्या हैं?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्या FTA में **श्रम और पर्यावरण संबंधी प्रावधानों** (जैसे यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र) को शामिल करना भारत के निर्यात को नुकसान पहुँचा सकता है?
- वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है? (जैसे निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को मज़बूत करना, MSME को समर्थन)।

3.3 लॉजिस्टिक्स: भारत के विकास का इंजन

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **रोजगार:** यह क्षेत्र **2.2 करोड़ से ज्यादा** लोगों को रोजगार देता है।

-:: 20 ::-

- सरकारी पहल: राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP), PM गतिशक्ति मास्टर प्लान, समर्पित माल ढुलाई गलियारे (DFC), और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP)।
- डिजिटलीकरण: यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) और लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (LDB) जैसी डिजिटल पहल। ULIP ने मार्च 2025 तक 100 करोड़ API लेनदेन दर्ज किए।
- GST का प्रभाव: GST लागू होने के बाद परिवहन समय में 33 % से अधिक की वृद्धि हुई और समग्र कर संरचना सरल हुई।
- LPI रैंकिंग: भारत 2023 के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) में 139 देशों की सूची में 38 वें स्थान पर पहुंच गया (2018 से 6 स्थानों का सुधार)।
- लक्ष्य: 2030 तक दुनिया के शीर्ष 25 लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल होना।
- ग्रीन लॉजिस्टिक्स: स्थिरता (Sustainability) पर जोर, रेल ग्रीन पॉइंट्स, और 2030 तक रेलवे की माल ढुलाई हिस्सेदारी को 45 % तक बढ़ाना।
- संभावित प्रश्न (Potential Questions):**
 - PM गतिशक्ति मास्टर प्लान और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) के बीच क्या संबंध है, और ये दोनों भारत के लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में कैसे मदद करते हैं?
 - LPI रैंकिंग में सुधार के पीछे कौन से प्रमुख कारक हैं?
- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**
 - समर्पित माल ढुलाई गलियारों (DFCs) का विनिर्माण (Manufacturing) और निर्यात (Export) पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
 - ग्रीन लॉजिस्टिक्स (Green Logistics) को बढ़ावा देने के लिए रेलवे की माल ढुलाई हिस्सेदारी को बढ़ाना क्यों महत्वपूर्ण है?

3.4 अमेरिकी टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):**
 - टैरिफ के कारण: भारत द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ और गैर-शुल्कीय अवरोध, रूसी तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद, और अमेरिका के साथ 45 अरब डॉलर का व्यापार घाटा।
 - प्रभावित निर्यात: टैरिफ का सीधा असर भारत के अमेरिका को होने वाले कुल निर्यात के लगभग 10 % पर पड़ेगा। सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, परिधान, रत्न और आभूषण शामिल हैं।
 - आर्थिक विकास पर दबाव: एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के GDP वृद्धि पूर्वानुमान को 6.7 % से घटाकर 6.5 % कर दिया।
 - प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी: भारतीय उत्पाद वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे अन्य एशियाई देशों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे, जिससे "चीन प्लस वन" विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को खतरा हो सकता है।
 - समाधान के उपाय: अमेरिका के साथ वार्ता में तेजी लाना, निर्यात बाजारों में विविधता लाना (EU, EFTA, खाड़ी देशों), और घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना।
- संभावित प्रश्न (Potential Questions):**
 - अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने के पीछे के प्रमुख कारण क्या हैं?
 - अमेरिकी टैरिफ से भारत के किन प्रमुख निर्यात क्षेत्रों को सबसे अधिक जोखिम होगा?
- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**
 - "चीन प्लस वन" (China Plus One) रणनीति क्या है, और यह भारत की विनिर्माण (Manufacturing) महत्वाकांक्षाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
 - भारत को अपने व्यापार संबंधों में विविधता लाने के लिए कौन से भौगोलिक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए?

4. हरित वित्त और ऊर्जा संक्रमण (Green Finance and Energy Transition)

यह खंड भारत के जलवायु लक्ष्यों, नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण और कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने की रणनीतियों पर केंद्रित है।

4.1 भारत की हरित वित्त योजना और Contracts for Difference (CfD)

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):**
 - वित्तपोषण लक्ष्य: भारत 2030 तक अपने 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के लिये लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का हरित वित्त (Green Finance) जुटाना चाहता है।

- **कुल आवश्यकता:** पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये भारत को 2030 तक 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, और नेट ज़ीरो (Net Zero) लक्ष्य के लिये 2070 तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है।
- **CfD तंत्र:** Contracts for Difference (CfD) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों और सरकार के बीच राजस्व स्थिरीकरण हेतु एक वित्तीय समझौता है, जो जोखिम को कम करता है।
- **वित्त पहलें:** राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा एवं पर्यावरण कोष (NCEEF), भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) द्वारा रियायती ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL)।
- **जलवायु वित्त सिद्धांत:** प्रदूषणकर्ता भुगतान करता है (Polluter Pays Principle), और समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारी और संबंधित क्षमताएँ (CBDR-RC)।
- **अंतरराष्ट्रीय कोष:** वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF), हरित जलवायु कोष (GCF), अनुकूलन कोष (AF), और लॉस एंड डैमेज फंड (L&D Fund)।
- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**
 - भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में Contracts for Difference (CfD) तंत्र की क्या भूमिका है?
 - जलवायु वित्त (Climate Finance) की परिभाषा क्या है, और 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करता है' सिद्धांत किस प्रकार कार्य करता है?
- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**
 - लॉस एंड डैमेज फंड (Loss and Damage Fund) भारत जैसे विकासशील देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
 - क्या भारत में हरित परियोजनाओं के लिए निजी वित्तपोषण (Private Financing) प्राप्त करने में कोई बड़ी बाधाएँ हैं?

4.2 कच्चे तेल निर्भरता काम करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदम

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**
 - **घरेलू उत्पादन को बढ़ावा:** हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (HELP), PSC विस्तार नीति, निचली रॉयल्टी दरें, और अपतटीय 'नो-गो' क्षेत्र को मुक्त करना।
 - **उपभोक्ताओं पर बोझ कम करना:** पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी (2021-22), तेल कंपनियों द्वारा खुदरा मूल्य कटौती।
 - **विविधता:** कच्चे तेल के आयात स्रोतों में विविधता लाना; पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देना।
 - **हरित ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन:** BS-VI ईंधन अपनाना, इथेनॉल मिश्रण, संपीड़ित जैव गैस (CBG), बायोडीजल, और हरित हाइड्रोजन उत्पादन।
 - **CO₂ कटौती:** 10 वर्षों में 578 लाख मीट्रिक टन CO₂ उत्सर्जन में कमी।
 - **योजना:** प्रधानमंत्री जी-वन योजना (जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा)।
- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**
 - भारत कच्चे तेल (Crude Oil) के आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए क्या रणनीतियाँ अपना रहा है?
 - इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme) भारत की ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) और किसानों की आय को कैसे प्रभावित करता है?
- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**
 - भारत के घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाने में 'नो-गो' क्षेत्रों को मुक्त करने का क्या महत्व है?
 - हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen) को 'भविष्य का ईंधन' क्यों कहा जाता है, और भारत की इसमें क्या महत्वाकांक्षा है?

5. वित्तीय और संरचनात्मक सुधार (Financial and Structural Reforms)

यह खंड रुपये के अंतरराष्ट्रीय करण, कर सुधारों और बैंकिंग क्षेत्र के स्थायित्व पर केंद्रित है।

5.1 रुपये का अंतरराष्ट्रीय करण (Internationalisation of the Rupee)

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**
 - **उद्देश्य:** भारतीय रुपये (INR) को वैश्विक व्यापार और वित्तीय लेन-देन के लिए उपयोग करने को बढ़ावा देना।
 - **प्रमुख उपाय:**
 - **अनिवासियों को INR में ऋण:** भूटान, नेपाल और श्रीलंका के निवासियों को भारतीय रुपये में ऋण देने की अनुमति।

- **पारदर्शी रेफरेंस रेट:** FBIL द्वारा प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के सापेक्ष रुपये के लिए पारदर्शी रेफरेंस रेट विकसित करना ।
- **SRVAs का उपयोग बढ़ाना:** स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स (SRVAs) के बैलेंस का उपयोग अब कॉर्पोरेट बॉण्ड्स और कमर्शियल पेपर्स में निवेश करने के लिए किया जा सकता है ।
- **SRVA परिभाषा:** एक ऐसा खाता जिसे एक विदेशी बैंक द्वारा भारतीय बैंक में खोला जाता है, ताकि व्यापारिक लेन-देन रुपये को विदेशी मुद्रा में बदले बिना सीधे भारतीय रुपये में निपटाए जा सकें ।
- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**
 - 'रुपये का अंतरराष्ट्रीय करण' (Internationalisation of the Rupee) क्या है, और यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
- **SRVA (Special Rupee Vostro Accounts)** किस प्रकार रुपये के अंतरराष्ट्रीय करण में सहायता करते हैं?
- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**
 - रुपये के अंतरराष्ट्रीय करण में चीन के युआन और अमेरिका के डॉलर से क्या सीखा जा सकता है?
 - क्या रुपये के अंतरराष्ट्रीय करण में कोई जोखिम (Risks) शामिल हैं, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर बाहरी झटकों का प्रभाव?

5.2 जीएसटी सुधार 2025: अगली पीढ़ी के सुधार (Next-Gen GST Reforms)

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**
 - **उद्देश्य:** आम आदमी के लिए राहत, व्यवसायों के लिए बढ़ावा, और कर का बोझ कम करना ।
 - **सरलीकरण:** जीएसटी को दो-स्लैब संरचना में सरलीकृत किया गया: **5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत** ।
 - **दरों में कटौती:** घरेलू आवश्यक वस्तुओं (साबुन, टूथपेस्ट) पर **5 %** या शून्य; जीवन रक्षक दवाओं पर **12 %** से घटाकर शून्य या **5 %**; दोपहिया वाहन, छोटी कारें, AC, सीमेंट पर **28 %** से घटकर **18 %** ।
 - **उच्च कर:** तंबाकू, पान मसाला, एरेटेड ड्रिंक्स और लक्जरी वस्तुओं पर **40 %** कर लगाया गया
 - **7 स्तंभ:** सरलीकृत संरचना, प्रौद्योगिकी के माध्यम से फाइलिंग को सरल बनाना, उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देना, MSME को सशक्त बनाना, मजबूत राज्य-मजबूत राष्ट्र, और कम कर-उच्च खर्च ।
 - **उपलब्धि:** 17 अलग-अलग करों और 13 उपकरणों को एक समेकित कर में समाहित किया, और **करों के कैस्केडिंग (आवर्ती) प्रभाव को समाप्त** कर दिया।
- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**
 - जीएसटी सुधार 2025 में दो-स्लैब संरचना (5% और 18%) का क्या महत्व है, और यह सरलीकरण (Simplification) कैसे सुनिश्चित करेगा?
 - जीएसटी को भारत की अर्थव्यवस्था का "एकल राष्ट्रीय बाजार" (Single National Market) का प्रतीक क्यों कहा जाता है?
- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**
 - क्या लक्जरी वस्तुओं पर **40 %** कर लगाना **राजस्व संतुलन (Revenue Balance)** और **सामाजिक न्याय (Social Justice)** के सिद्धांत के अनुरूप है?
 - जीएसटी परिषद (GST Council) की संरचना क्या है, और यह सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) का उदाहरण कैसे है?

5.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में विनिवेश (Disinvestment)

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**
 - **परिचय:** विनिवेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में **रणनीतिक या वित्तीय खरीदारों** को सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री शामिल है, जिसका उपयोग **सामाजिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण** के लिए और राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु किया जाता है।
 - **लक्ष्य:** केंद्रीय बजट 2023-24 में **₹51,000 करोड़** का विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो सात वर्षों में सबसे कम था।
 - **उपलब्धियां:** 2022-23 के विनिवेश लक्ष्य को LIC के IPO से **20,516 करोड़ रुपये** सहित, प्राप्त किया गया था।
 - **लाभ:** विनिवेश से **राजकोषीय बोझ कम** होता है, **मजबूत पूंजी बाजार** की स्थापना का अवसर मिलता है, और आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं, जिससे **रोजगार के नए अवसर** पैदा होते हैं।

- आलोचना: विनिवेश केवल सरकार के लिए धन जुटाने का एक साधन बन गया है। लाभांश आय में कमी आ सकती है, और रणनीतिक कंपनियों (जैसे BPCL) में विनिवेश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है।
- संभावित प्रश्न (Potential Questions):
 - विनिवेश (Disinvestment) और निजीकरण (Privatization) में क्या अंतर है? सरकार विनिवेश का विकल्प क्यों चुनती है?
 - विनिवेश नीति की आलोचनाएँ क्या हैं, विशेषकर रणनीतिक क्षेत्र की कंपनियों के संदर्भ में?

5.4 उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) की प्रगति

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):
 - उद्देश्य: आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन को बढ़ाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना, तथा भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाना।
 - कवरेज: वर्तमान में 14 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। कुल प्रोत्साहन ₹1.97 लाख करोड़ है।
 - निवेश और बिक्री: PLI योजना ने ₹1.76 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया है। PLI लाभार्थियों की ओर से की गई कुल बिक्री 2025 के मध्य तक ₹16.5 लाख करोड़ को पार कर गई है।
 - रोजगार सृजन: इस योजना के तहत 12 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मित हुए हैं।
 - क्षेत्रीय प्रभाव:
 - मोबाइल फोन: भारत एक प्रमुख मोबाइल फोन निर्माण देश बन गया है, जिसका उत्पादन में 146 % की बढ़ोतरी हुई है।
 - ऑटोमोबाइल: PLI ऑटो योजना के अंतर्गत ₹67,690 करोड़ मूल्य के प्रतिबद्ध निवेश आकर्षित हुए हैं।
 - MSME पर प्रभाव: PLI से संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में नए सप्लायर और वेंडर नेटवर्क विकसित होने की उम्मीद है, जिसमें MSME क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।
- संभावित प्रश्न (Potential Questions):
 - उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, और यह 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान का समर्थन कैसे करती है?
 - PLI योजना ने भारत को मोबाइल फोन निर्माण में वैश्विक केंद्र बनने में कैसे मदद की है?
- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):
 - PLI योजना के कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं, खासकर MSME के लिए?
 - क्या PLI योजना विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मानदंडों के अनुरूप है?

□□□

03. समकालीन नैतिक मुद्दे (Contemporary Ethical Issues)

समकालीन नैतिक मुद्दे

भारत और अंतरराष्ट्रीय

1. सुरक्षा, उग्रवाद और कूटनीति

- 1.1 नक्सल मुक्त भारत विजन और नक्सलवाद (LWE)
- 1.2 ऑपरेशन सिंदूर: आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ संकल्प
- 1.3 ऑपरेशन सिंधु: निकासी कूटनीति

2. सामाजिक सशक्तिकरण और न्याय

- 2.1 कार्यबल में महिलाओं का सशक्तिकरण और समावेशी कार्यस्थल
- 2.2 'सरपंच पति' संस्कृति और 'लखपति दीदी' पहल
- 2.3 शासन के लिए AI का उपयोग और नैतिक मुद्दे
- 2.4 मातृ मृत्यु दर (MMR) की प्रवृत्ति

3. शासन, पारदर्शिता और नैतिकता

- 3.1 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम गलत सूचना
- 3.2 डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम और बिग टेक विनियमन
- 3.3 हेट स्पीच का विनियमन और संवैधानिक संतुलन
- 3.4 NCERT की पाठ्यपुस्तकों में विवाद और संशोधन की नैतिकता

राजस्थान विशेष

1. शासन, विधि और सामाजिक विकास

- 1.1 राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025
- 1.2 राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक
- 1.3 राजस्थान में जनजातीय क्षेत्र विकास
- 1.4 राजस्थान में युद्ध मॉक ड्रिल / ऑपरेशन शीलड
- 1.5 भारत की 16वीं जनगणना (वर्ष 2027) और जातिगत जनगणना

RAS 2024 INTERVIEW GUIDANCE PROGRAM



डॉ. ललित के. पुरी सर
(रिटायर्ड आईएएस) पूर्व अध्यक्ष, RPSC



अंशुक कुमार
(Rank 20, RAS 2023)



डॉ. ए. के. मलिक सर
विभागाध्यक्ष एवं निदेशक, उत्कर्ष



दिलीप कुमार सर
सिनिअर सेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर



Scan the
QR Code
to watch the
**Detailed video
solution of Probable
& Counter Questions**



1. सुरक्षा, उग्रवाद और कूटनीति
(Security, Extremism, and Diplomacy)

1.1 नक्सल मुक्त भारत विजन और नक्सलवाद (LWE)

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- स्थिति में सुधार: नक्सलवाद (LWE) से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर सिर्फ 3 रह गई है।
- सर्वाधिक प्रभावित जिले: अब केवल छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर ही वामपंथी उग्रवाद (LWE) से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं।
- लक्ष्य: मोदी सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है।
- भौगोलिक संकुचन: LWE का भौगोलिक विस्तार ('रेड कॉरिडोर') नेपाल से आंध्र प्रदेश तक फैला था, लेकिन अब यह मुख्य रूप से मध्य भारत के कुछ छोटे क्षेत्रों, मुख्यतः छत्तीसगढ़ तक सीमित रह गया है।
- सरकारी रणनीति: परिचालन रणनीति 'समाधान' (SAMADHAN) द्वारा पूरक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015।
- (S-Smart Leadership, A-Aggressive Strategy, M-Motivation & Training, A-Actionable Intelligence, D-Dashboard-based KPIs/KRAs, H-Harnessing Technology, A-Action Plan for Each Theatre, N-No access to Financing)
- जिम्मेदार कारक: विकास परियोजनाओं/खनन के कारण जनजातीय आबादी का विस्थापन, निर्धनता/बेरोज़गारी, प्रभावी शासन का अभाव, और नक्सली दुष्प्रचार।

● चुनौतियाँ (Mnemonic): "INSURGENT" (राज्य की अपर्याप्त पहुँच, विकास की कमी, सामाजिक-आर्थिक शिकायतें, गुरिल्ला रणनीति)।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में भारत की प्रगति को आप एक प्रशासक के रूप में कैसे देखते हैं? नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की संख्या कम होने के क्या निहितार्थ हैं?
- नक्सलवाद से निपटने के लिए भारत सरकार की 'समाधान' (SAMADHAN) रणनीति क्या है, और यह क्यों प्रभावी साबित हुई है?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्या केवल सुरक्षा बल (Security Forces) LWE को समाप्त कर सकते हैं, या समस्या का मूल सामाजिक-आर्थिक शिकायतें और शासन का अभाव है?
- बंदोपाध्याय समिति (2006) की प्रमुख सिफारिशें क्या थीं, और उनका कार्यान्वयन LWE को रोकने में क्यों महत्वपूर्ण है?

1.2 ऑपरेशन सिंदूर: आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ संकल्प

यह भारत की शून्य-सहिष्णुता की नीति (Zero-Tolerance Policy) और रणनीतिक प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- प्रसंग: पहलगाम में आतंकी हमला (सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की स्पष्ट कोशिश)।
- ऑपरेशन उद्देश्य: आतंक के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करना।
- गैर-सैन्य उपाय (आर्थिक दबाव): भारत द्वारा सिंधु जल संधि (IWT) को समाप्त करना (पाकिस्तान की कृषि भूमि और जल उपयोग के 80% - 93% पर निर्भरता);
- अटारी-वाघा सीमा बंद करना और सभी द्विपक्षीय व्यापार निलंबित करना।
- IWT निलंबन का कूटनीतिक संदेश: "रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते"।
- परिणाम: नौ आतंकी शिविर नष्ट, 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान की वायु रक्षा कमजोरियों का खुलासा हुआ।

- **नया सिद्धांत:** भविष्य में होने वाले किसी भी आतंकवादी हमले को युद्ध की कार्यवाई माना जाएगा, जिससे आतंकवादियों और उनके राज्य प्रायोजकों के बीच के भेद को समाप्त कर दिया गया।
- **भविष्य की वार्ता की शर्त:** यदि पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो वह केवल आतंकवाद पर और केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) पर होगी।
- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**
 - 'ऑपरेशन सिंधु' के तहत भारत द्वारा सिंधु जल संधि (IWT) को निलंबित करने का निर्णय कितना नैतिक और रणनीतिक था?
- आतंकवाद के विरुद्ध भारत के नए 'राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत' (National Security Doctrine) की व्याख्या करें।
- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**
 - क्या किसी युद्ध जैसी स्थिति में सिंधु जल संधि जैसे अंतरराष्ट्रीय संधियों को एक हथियार के रूप में उपयोग करना उचित है? इसके वैश्विक कूटनीतिक परिणाम क्या हो सकते हैं?
 - क्या 'आतंक और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते' का सिद्धांत किसी भी प्रकार के कूटनीतिक समाधान (Diplomatic Solution) की संभावना को समाप्त करता है?

1.3 ऑपरेशन सिंधु (Operation Sindhu): निकासी कूटनीति

यह संकट काल में भारत की 'जन-केंद्रित' विदेश नीति (People-Centric Foreign Policy) का उदाहरण है।

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**
 - **प्रसंग:** ईरान पर इजरायल-अमेरिकी सैन्य हमलों की आशंका बढ़ने के बाद ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया।
 - **रणनीतिक मार्ग:** आर्मेनिया के रास्ते निकासी की योजना बनाई गई।
 - **आर्मेनिया का महत्व:** ईरान के साथ 44 किलोमीटर लंबी सीमा और नूरदुज-अगारक क्रॉसिंग, जो सबसे व्यावहारिक और सुरक्षित भूमि मार्ग प्रदान करती है।
 - **अन्य सीमाओं से चुनौतियाँ:** पाकिस्तान (भू-राजनीतिक तनाव), तुर्की/अज़रबैजान (प्रतिकूल समर्थन), अफगानिस्तान (तालिबान शासन), और इराक (सक्रिय संघर्ष क्षेत्र)।
 - **राजदूत संबंध:** आर्मेनिया अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के लिए समर्थन करता है (जैसे कश्मीर मुद्दा), और भारत उसका शीर्ष सैन्य आपूर्तिकर्ता है (पिनाका रॉकेट लांचर)।
 - **अन्य प्रमुख अभियान:** ऑपरेशन कावेरी (सूडान, 2023), ऑपरेशन अजय (इज़राइल, 2023), ऑपरेशन गंगा (यूक्रेन, 2022)।
- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**
 - 'ऑपरेशन सिंधु' की सफलता में आर्मेनिया की भू-रणनीतिक स्थिति (Geo-Strategic Position) क्यों महत्वपूर्ण थी?
 - भारत की "निकासी कूटनीति" (Evacuation Diplomacy) क्या दर्शाती है, और यह उसकी वैश्विक सॉफ्ट पावर को कैसे मजबूत करती है?
- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**
 - अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में तटस्थता बनाए रखते हुए, भारत अपनी विदेश नीति (Foreign Policy) को जन-केंद्रित कैसे रखता है?
 - क्या आर्मेनिया को सैन्य आपूर्ति प्रदान करना भारत की गुटनिरपेक्ष (Non-Alignment) नीति से विचलन है?

2. सामाजिक सशक्तिकरण और न्याय (Social Empowerment and Justice)

2.1 कार्यबल में महिलाओं का सशक्तिकरण और समावेशी कार्यस्थल

यह विकसित भारत (@2047) के लिए महिला-नेतृत्व वाले विकास (Women-Led Development) पर केंद्रित है।

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **LFPR में वृद्धि:** महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 2017-18 में 23.3 % से बढ़कर 2023-24 में **41.7 %** हो गई है।
- **कानूनी ढाँचा:** मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (संशोधित 2017) में अवकाश **12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह**; 50 से अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए **शिशुगृह (क्रेच)** अनिवार्य। **यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013** (आंतरिक शिकायत समितियाँ - ICC अनिवार्य)।
- **सरकारी पहल:**
 - **मिशन शक्ति:** 'संबल' (सुरक्षा) और 'सामर्थ्य' (सशक्तिकरण) पर केंद्रित। इसमें **वन स्टॉप सेंटर (OSC)** और **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)** शामिल।
 - **आर्थिक सशक्तिकरण:** पीएम मुद्रा योजना (68 % से अधिक खाताधारक महिलाएँ)। **स्टैंड-अप इंडिया** (2.01 लाख महिलाओं के स्वामित्व वाले खाते)।
 - **शी-बॉक्स (She-Box):** यौन उत्पीड़न की शिकायतों की निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल।
- **ब्रिक्स तुलना:** भारत ने पिछले एक दशक में ब्रिक्स देशों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में **सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि** दर्ज की है।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में हुई वृद्धि को आप किन प्रमुख नीतिगत सुधारों का परिणाम मानते हैं?
- कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में 'मातृत्व लाभ अधिनियम' (Maternity Benefit Act) और 'क्रेच सुविधाएँ' (Crèche Facilities) क्यों महत्वपूर्ण हैं?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- लैंगिक वेतन समानता (Gender Pay Parity) के मामले में भारत अभी भी अन्य देशों से पीछे क्यों है? इसे दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
- मिशन शक्ति के 'संबल' और 'सामर्थ्य' घटकों के बीच क्या अंतर है?

2.2 'सरपंच पति' संस्कृति और 'लखपति दीदी' पहल

यह **जमीनी स्तर पर (Grassroots Level)** नेतृत्व और आर्थिक सशक्तिकरण की चुनौतियों को दर्शाता है।

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **सरपंच पति संस्कृति:** इसमें चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों की जगह उनके **पति या पुरुष रिश्तेदार फैसले लेते हैं**, जिससे महिलाओं के संवैधानिक अधिकार कमजोर पड़ जाते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने इसे खत्म करने के लिए **डिजिटल मुहिम** शुरू की है।
- **पहल:** "सशक्त पंचायत नेत्री अभियान" के तहत डिजिटल सामग्री तैयार की गई ("असली प्रधान कौन?")।
- **लखपति दीदी पहल:** स्वयं सहायता समूह (SHG) की वह सदस्य जिसने सफलतापूर्वक **₹1 लाख या उससे अधिक** की वार्षिक घरेलू आय प्राप्त कर ली हो।
- **उद्देश्य:** दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (**DAY-NRLM**) द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य **स्थायी आजीविका प्रथाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना** है।
- **उपलब्धियाँ:** एक करोड़ महिलाओं को पहले ही लखपति दीदी बनाया जा चुका है, और लक्ष्य को **2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़** करने की घोषणा की गई है।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- 'सरपंच पति' संस्कृति पंचायती राज संस्थाओं में **महिला आरक्षण (Women's Reservation)** के उद्देश्य को कैसे कमजोर करती है?

● 'लखपति दीदी' पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rural Economy) में SHG की भूमिका को किस प्रकार बढ़ाती है?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में **पंचायतों में महिला सदस्यों के वास्तविक नेतृत्व (Actual Leadership)** को कैसे सुनिश्चित करेंगे?
- **SHG** को माइक्रोफाइनेंस (Microfinance) से आगे बढ़कर बड़े पैमाने पर उद्यमशीलता (Entrepreneurship) की ओर ले जाने के लिए क्या किया जाना चाहिए?

2.3 शासन के लिए AI का उपयोग और नैतिक मुद्दे

यह AI (Artificial Intelligence) के अनुप्रयोगों और उससे उत्पन्न होने वाली नैतिक दुविधाओं (Ethical Dilemmas) पर केंद्रित है।

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **AI अनुप्रयोग:** नीति निर्माण (डेटा-संचालित), सार्वजनिक सेवा वितरण (चैटबॉट, स्वचालन), कानून प्रवर्तन (फेशियल रिकग्निशन), स्वास्थ्य सेवा (रोग निदान), कृषि उत्पादकता (परिशुद्ध कृषि)।
- **AI और महिला सशक्तिकरण:** महिलाओं को प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा (AI चैटबॉट सरकारी योजनाओं तक पहुँच आसान बनाता है), सुरक्षा (AI आधारित आपातकालीन अलर्ट), और स्वास्थ्य (AI आधारित मेमोग्राफी सिस्टम) में मदद।
- **AI द्वारा उत्पन्न मुद्दे:**
 - नौकरी विस्थापन (कम-कुशल नौकरियों को खतरा, 2025 तक 75 मिलियन नौकरियों का खतरा)।
 - एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह (जाति, लिंग भेदभाव को मजबूत कर सकता है)।
 - गोपनीयता का उल्लंघन (फेशियल रिकग्निशन)।
 - डीपफेक और गलत सूचना।
 - डिजिटल डिवाइड (शहरी/ग्रामीण असमानता)।
- **भारत की रणनीति:** 'नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (2018), और 'रिस्पॉन्सिबल AI' पर ड्राफ्ट (2021) जिसमें नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को प्राथमिकता।
- **सुझाए गए उपाय:** जोखिम-आधारित AI गवर्नेंस मॉडल, राष्ट्रीय AI नियामक प्राधिकरण (AIGA) की स्थापना, व्याख्या योग्य AI (XAI) को अनिवार्य बनाना।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- AI का उपयोग कानून प्रवर्तन (Law Enforcement) में कैसे किया जा रहा है, और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) से संबंधित नैतिक चिंताएँ क्या हैं?
- 'डीपफेक' (Deepfake) लोकतंत्र (Democracy) और चुनावी अखंडता (Electoral Integrity) के लिए क्या खतरा उत्पन्न करते हैं?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- AI के एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रहों (Algorithmic Bias) को आप एक प्रशासक के रूप में कैसे दूर करेंगे?
- AI के विकास में महिलाओं की भागीदारी क्यों आवश्यक है (AI में सहानुभूति और नैतिकता समाहित करने हेतु)?

2.4 मातृ मृत्यु दर (MMR) की प्रवृत्ति

यह भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र (Healthcare Sector) और SDG लक्ष्यों की प्रगति पर केंद्रित है।

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **वैश्विक स्थिति:** भारत (19,000 मातृ मृत्यु) नाइजीरिया के बाद सर्वाधिक मातृ मृत्यु वाला दूसरा देश है।
- **MMR में गिरावट:** भारत ने MMR (मातृ मृत्यु अनुपात) में महत्वपूर्ण प्रगति की है: वर्ष 2000 के 384 से घटकर 2023 में 80 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म हो गया।
- **SDG लक्ष्य:** SDG 3.1 लक्ष्य (वर्ष 2030 तक वैश्विक MMR को 70 से नीचे लाना)।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने 70 से नीचे MMR हासिल किया है, लेकिन असम (195), मध्य प्रदेश (173), उत्तर प्रदेश (167) और बिहार (118) राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं।
- **चिंताएँ:** मातृ मृत्यु की उच्च निरपेक्ष संख्या (7.2% वैश्विक मृत्यु), कुशल प्रसव देखभाल तक पहुँच में चुनौतियाँ, और मधुमेह/उच्च रक्तचाप जैसी गैर-संचारी रोग (NCD) के कारण मृत्यु में वृद्धि।
- **सरकारी पहल:** जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, और जननी सुरक्षा योजना।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- MMR में गिरावट के बावजूद, भारत के MMR को SDG 3.1 लक्ष्य तक ले जाने में क्षेत्रीय असमानताएँ (Regional Disparities) एक बड़ी बाधा क्यों हैं?
- आप MMR को कम करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (PHC) केंद्रों को कैसे मजबूत करेंगे?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- निरपेक्ष संख्या (Absolute Number) के आधार पर MMR की तुलना करना क्यों त्रुटिपूर्ण माना जाता है?
- पोषण (Nutrition) और लैंगिक समानता (Gender Equality) MMR को कम करने में कैसे योगदान दे सकते हैं?

3. शासन, पारदर्शिता और नैतिकता (Governance, Transparency, and Ethics)

इस श्रेणी में सरकार, न्यायपालिका और नागरिकों के बीच विश्वास (Trust) और जवाबदेही (Accountability) को प्रभावित करने वाले मौलिक मुद्दे शामिल हैं।

3.1 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Free Speech) बनाम गलत सूचना (Misinformation)

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **विवाद:** केंद्र सरकार द्वारा प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के तहत फैक्ट-चेकिंग यूनिट (FCU) स्थापित करने की पहल, जिसे डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 'फर्जी या झूठी या भ्रामक' जानकारी को हटाने का अधिकार दिया गया।
- **न्यायिक हस्तक्षेप:** बॉम्बे हाई कोर्ट में दो जजों की बेंच के विभाजित फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी।
- **आलोचना:** आलोचकों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Article 19(1)(a)) का उल्लंघन बताया और तर्क दिया कि सरकार स्वयं के विवादों में 'न्यायाधीश' (Judge in its own cause) बन जाएगी।
- **संवैधानिक पहलू:** Article 19(2) में भाषण पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो परिस्थितियाँ सूचीबद्ध हैं, उनमें 'सही या गलत' (True or False) के आधार पर प्रतिबंध शामिल नहीं है।

● चिलिंग इफेक्ट: आलोचकों का मानना था कि FCU की स्थापना से आत्म-सेंसरशिप (Self-censorship) बढ़ेगी।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना (Misinformation) के प्रसार को रोकने के लिए आप एक प्रशासक के रूप में क्या उपाय सुझाएंगे, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Expression) का उल्लंघन न करें?
- FCU के मुद्दे पर 'सरकार द्वारा सत्य पर एकाधिकार' (Monopoly over truth by the government) के तर्क का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।
- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**
 - **हेट स्पीच (Hate Speech) और गलत सूचना (Misinformation)** में क्या अंतर है? क्या दोनों को Article 19(2) के तहत समान रूप से विनियमित किया जा सकता है?
 - क्या सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में 'सेफ हार्बर' (Safe Harbour) प्रावधान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उनके दायित्वों से छूट देता है?

3.2 डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम (Digital Competition Act) और बिग टेक विनियमन

यह डिजिटल एकाधिकार (Digital Monopolies), डेटा प्रभुत्व (Data Dominance) और एल्गोरिथम पारदर्शिता (Algorithmic Transparency) के नैतिक प्रश्न उठाता है।

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **आवश्यकता:** भारत का प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (Competition Act, 2002) डिजिटल बाजारों के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह पारंपरिक बाजारों पर केंद्रित है और डेटा-केंद्रित प्रभुत्व (Data-centric dominance) को संबोधित नहीं करता है।
- **प्रस्तावित कानून:** डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम (DCA), जो प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को Ex-Ante (घटना होने से पहले) विनियमन के लिए सशक्त करेगा।
- **SSDEs:** DCA बड़े प्लेटफॉर्म को 'सिस्टमेटिकली सिनिफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेज' (SSDEs) के रूप में वर्गीकृत करेगा।
- **प्रतिबंधित व्यवहार:** SSDEs को स्व-वरीयता (Self-preferencing), बंडलिंग, और उपयोगकर्ता की गैर-सार्वजनिक डेटा का दुरुपयोग करने से रोका जाएगा।
- **केस उदाहरण:** CCI ने Meta (WhatsApp) पर ₹213 करोड़ का जुर्माना लगाया और डेटा साझाकरण पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया, जिसे NCLAT ने स्टे कर दिया।
- **नैतिक चिंता:** पारदर्शिता की कमी, एल्गोरिथम पूर्वाग्रह (Algorithmic Bias), और छोटे व्यवसायों पर बिग-टेक का एकाधिकार।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून (DCA) की आवश्यकता क्यों है? Ex-ante (पूर्व-व्यापी) विनियमन Ex-post (पश्चात-व्यापी) विनियमन से कैसे बेहतर है?
- एल्गोरिथम पारदर्शिता (Algorithmic Transparency) से आप क्या समझते हैं, और यह डिजिटल प्लेटफॉर्म की नैतिक जवाबदेही को कैसे सुनिश्चित कर सकता है?

- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्या कठोर DCA कानून भारत में तकनीकी नवाचार (Tech Innovation) और स्टार्टअप्स के विकास को प्रभावित कर सकता है?
- डेटा एकाधिकार (Data Monopolization) छोटे व्यवसायों के लिए क्या खतरे पैदा करता है?

3.3 हेट स्पीच (Hate Speech) का विनियमन और संवैधानिक संतुलन

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **संवैधानिक दुविधा:** भारतीय संविधान Article 19(1)(a) के तहत भाषण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन Article 19(2) के तहत 'उचित प्रतिबंध' (Reasonable Restrictions) (जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, मानहानि) की अनुमति देता है।
- **समस्या:** भारत में हेट स्पीच से संबंधित कानूनी प्रावधान (IPC §153A, §505) अस्पष्ट (Vague) और व्यापक (Broad) हैं, जिससे इनका दुरुपयोग (Misuse) राजनीतिक असंतोष को दबाने के लिए हो सकता है।
- **न्यायिक रुख:** सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी भलाई संगठन केस में स्पष्ट किया कि हेट स्पीच को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है, लेकिन इसने सटीकता, आनुपातिकता और संदर्भ पर जोर दिया।
- **आवश्यकता:** विधि आयोग (Law Commission) ने स्पष्ट परिभाषाओं के साथ नए प्रावधानों की सिफारिश की है, क्योंकि वर्तमान कानून डिजिटल युग की चुनौतियों का समाधान करने में अपर्याप्त हैं।
- **नैतिक आधार:** हेट स्पीच को रोकना मानव गरिमा (Article 21) और सामाजिक सद्भाव (Social Harmony) की रक्षा के लिए आवश्यक है।

- संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- हेट स्पीच (Hate Speech) के विनियमन में Article 19(1)(a) और Article 19(2) के बीच संवैधानिक संतुलन कैसे स्थापित किया जाता है?
- भारत में हेट स्पीच कानूनों की अस्पष्टता (Vagueness) से क्या चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, और आप हेट स्पीच की एक स्पष्ट परिभाषा कैसे देंगे?

- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्या हेट स्पीच को रोकने के लिए न्यायिक निगरानी (Judicial Oversight) प्रशासनिक कार्रवाई से अधिक महत्वपूर्ण है?
- सामाजिक ध्रुवीकरण (Communal Polarization) को रोकने में एक प्रशासनिक अधिकारी की क्या नैतिक जिम्मेदारी (Ethical Responsibility) है?

3.4 NCERT की पाठ्यपुस्तकों में विवाद और संशोधन की नैतिकता

यह शैक्षिक ईमानदारी (Academic Integrity), ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व और सांप्रदायिक राजनीति का संवेदनशील मुद्दा है।

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **संशोधन का आधार:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और सामग्री का युक्तिकरण (Content Rationalization) (COVID-19 के कारण छात्रों पर सामग्री का बोझ कम करना)।
- **मुख्य विवाद:**
 - **इतिहास का विलोपन/संशोधन:** आलोचकों ने मुगल इतिहास, गुजरात दंगों, आपातकाल, और अयोध्या विवाद (बाबरी मस्जिद को "तीन गुंबद वाली संरचना" कहा गया) जैसे संवेदनशील विषयों के संदर्भों को हटाने या कम करने का आरोप लगाया है।
 - **भगवाकरण:** विपक्षी दलों ने पाठ्यपुस्तकों का "भगवाकरण" (Saffronisation) करने का आरोप लगाया है, जिसमें हिंदुत्व सांस्कृतिक मानदंडों पर जोर दिया गया है।
 - **वैज्ञानिक अवधारणाओं का विलोपन:** चार्ल्स डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत, ग्रीनहाउस प्रभाव और जलवायु परिवर्तन जैसे वैज्ञानिक विषय हटाए या कमजोर किए गए हैं।
 - **भाषाई विवाद:** अंग्रेजी माध्यम की पाठ्यपुस्तकों के लिए हिंदी शीर्षकों (जैसे मृदंग) का उपयोग करना ("सांस्कृतिक थोपे जाने" के रूप में देखा गया)।
- **NCERT का तर्क:** परिवर्तन भारतीय विरासत और लोकाचार से जुड़ने, तथ्यात्मक सटीकता सुनिश्चित करने और छात्रों में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं।

- संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- NCERT की पाठ्यपुस्तकों में संशोधन की शैक्षिक नैतिकता (Educational Ethics) क्या है? क्या शिक्षा नीति में राजनीतिक विचारधारा (Political Ideology) का हस्तक्षेप होना चाहिए?
- पाठ्यक्रम से विकासवाद का सिद्धांत (Theory of Evolution) या जलवायु परिवर्तन (Climate Change) जैसे विषयों को हटाने के क्या दीर्घकालिक परिणाम (Long-term Consequences) हो सकते हैं?

- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- छात्रों पर 'सामग्री का बोझ कम करने' (Reducing Student Burden) के लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे नैतिक तरीका क्या हो सकता है?
- ऐतिहासिक घटनाओं के प्रतिनिधित्व में 'तथ्यात्मक सटीकता' (Factual Accuracy) और 'राष्ट्रीय गौरव' (National Pride) के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए?

राजस्थान विशेष
(Rajasthan Special)

1. शासन, विधि और सामाजिक विकास
(Governance, Law and Social Development)

1.1 राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025

यह छात्र आत्महत्या (Student Suicides), मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) और व्यावसायिक शिक्षा (Commercialization of Education) से संबंधित एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है।

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- उद्देश्य: कोचिंग संस्थानों के व्यावसायीकरण पर अंकुश लगाना, छात्र कल्याण सुनिश्चित करना, और छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकना।
- प्रावधान:
 - अनिवार्य पंजीकरण: 50 या अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों का अनिवार्य पंजीकरण।
 - शुल्क नियंत्रण: मनमाने शुल्क पर रोक; कोर्स छोड़ने पर 10 दिनों के भीतर आनुपातिक आधार पर शेष शुल्क वापस करना अनिवार्य; शुल्क एकमुश्त लेने की मनाही।
 - विनियमन प्राधिकरण: 'राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन प्राधिकरण' का गठन।
 - दैनिक अवधि: कक्षा की अधिकतम अवधि प्रति दिन 5 घंटे; सप्ताह में एक दिन अवकाश अनिवार्य।
 - मानसिक स्वास्थ्य: काउंसलिंग सिस्टम विकसित करने का प्रावधान।

- संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- राजस्थान, विशेषकर कोटा में छात्र आत्महत्याओं (Student Suicides in Kota) के पीछे के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक क्या हैं?
- राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) और वित्तीय शोषण (Financial Exploitation) को रोकने में कितना प्रभावी होगा?

- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्या फीस को विनियमित (Regulate) करने से कोचिंग संस्थानों की गुणवत्ता (Quality) पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है?
- एक प्रशासक के रूप में आप छात्रों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए कौन से Non-Legal Measures सुझाएंगे?

1.2 राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक

यह धर्म की स्वतंत्रता (Freedom of Religion), व्यक्तिगत पसंद (Individual Choice) और राज्य के हस्तक्षेप (State Intervention) से संबंधित एक संवेदनशील मुद्दा है।

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- उद्देश्य: धोखाधड़ी, बलपूर्वक या अनुचित प्रभाव के माध्यम से किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने पर अंकुश लगाना।

- **प्रावधान:**
 - **विवाह का निरस्तीकरण:** विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन करवाने के उद्देश्य से किया गया विवाह, सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
 - **दोषसिद्धि पर कठोर दंड:** छल कपट से धर्म परिवर्तन पर न्यूनतम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 से 14 वर्ष तक का कारावास। अल्प वयस्क/महिला/SC/ST के मामले में न्यूनतम 10 से 20 वर्ष तक कारावास और 10 लाख रुपए का जुर्माना।
 - **पूर्व सूचना:** धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट को 90 दिन पूर्व जानकारी देनी होगी, और धर्माचार्य को 2 माह पूर्व नोटिस देना होगा।
- **संवैधानिक आधार:** अनुच्छेद 25 (अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचारित करने का अधिकार)।
- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**
 - यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) का उल्लंघन कैसे करता है, जैसा कि याचिकाकर्ता का दावा है?
 - बलपूर्वक धर्म परिवर्तन (Forced Conversion) और व्यक्तिगत पसंद (Individual Choice) से धर्म परिवर्तन में क्या अंतर है? इसे कानून में कैसे परिभाषित किया जाना चाहिए?
- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**
 - क्या एक वयस्क व्यक्ति को अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करने के लिए राज्य को पूर्व सूचना (Prior Notice) देना आवश्यक है? यह गोपनीयता के अधिकार (Right to Privacy) को कैसे प्रभावित करता है?
 - क्या कानून विवाह के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाकर, अंतर-धार्मिक विवाह (Inter-Religious Marriages) को हतोत्साहित करता है?

1.3 राजस्थान में जनजातीय क्षेत्र विकास (Tribal Area Development)

यह सामाजिक न्याय (Social Justice), सांस्कृतिक संरक्षण (Cultural Preservation) और समावेशी विकास (Inclusive Development) पर केंद्रित है।

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**
 - **जनजाति गौरव दिवस:** भगवान बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवम्बर को 'जनजाति गौरव दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा।
 - **अभियान:** 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (16 जून 2025 को उदयपुर के कोटड़ा ब्लॉक से शुभारंभ)।
 - **उद्देश्य:** 'सबका साथ, सबका विकास' भावना के साथ जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, जल प्रबंधन, रोजगार और संस्कृति संरक्षण आदि का विकास और संवर्धन करना।
 - **विकास योजनाएँ:**
 - **TSP फंड:** राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान हेतु TSP फंड को ₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,500 करोड़ किया है।
 - **शिक्षा:** मां-बाड़ी केंद्रों की स्थापना, एकलव्य स्कूल, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, और प्रोजेक्ट चितेरा (मांडना/चित्रकला को पुनर्जीवित करना)।
 - **स्वास्थ्य:** सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च (आबूरोड) और ड्रोन दवा आपूर्ति सुविधा का शुभारंभ।
 - **सांस्कृतिक:** जनजाति नायकों के स्मारक (वीर बालिका काली बाई संग्रहालय) और 'बनफूल डिज़ाइन स्टूडियो' की स्थापना।
- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**
 - 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' जनजातीय विकास के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण (Multi-Dimensional Approach) कैसे प्रदान करता है?
- **भगवान बिरसा मुंडा का योगदान क्या था, और 'जनजाति गौरव दिवस' मनाने के पीछे का नैतिक उद्देश्य क्या है?**
- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**
 - जनजातीय क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 का उल्लंघन नहीं हो, यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है?
 - जनजातीय उप-योजना (TSP) फंड का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में क्या चुनौतियाँ हैं, और आप लीकेज को कैसे रोकेंगे?

1.4 राजस्थान में युद्ध मॉक ड्रिल / ऑपरेशन शील्ड

यह आपदा प्रबंधन (Disaster Management), नागरिक सुरक्षा (Civil Defence) और रणनीतिक तत्परता (Strategic Preparedness) से संबंधित है।

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**

- **उद्देश्य:** हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना; नागरिकों को बुनियादी नागरिक सुरक्षा उपायों का प्रशिक्षण देना; नियंत्रण कक्षों के कामकाज का आकलन करना; और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (Critical Infrastructure) की शीघ्र छलावरण सुनिश्चित करना।
- **संवेदनशील क्षेत्र (3 श्रेणियाँ):**
 - **सबसे संवेदनशील:** रावतभाटा (न्यूक्लियर प्लांट), कोटा।
 - **मध्यम संवेदनशील:** जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर (थल सेना, वायुसेना प्रतिष्ठान)।
 - **कम संवेदनशील:** फुलेरा, ब्यावर, जालौर, नागौर।
- **नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल:** इसका उद्देश्य घबराहट को कम करना, तत्परता बढ़ाना और जान-माल की सुरक्षा की भावना बनाए रखना है।

- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**

- राजस्थान में युद्ध मॉक ड्रिल आयोजित करने का उद्देश्य क्या है, और नागरिक सुरक्षा (Civil Defence) में इसका क्या महत्व है?
- रावतभाटा (Nuclear Plant) को सबसे संवेदनशील क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करने का कारण क्या है, और इसकी सुरक्षा के लिए क्या विशेष प्रोटोकॉल हैं?

- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

- क्या युद्ध मॉक ड्रिल से आम नागरिकों में घबराहट या पैनिक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? आप इसे कैसे प्रबंधित करेंगे?
- एक प्रशासक के रूप में, आप महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (Critical Infrastructure) को साइबर हमलों (Cyber Attacks) से बचाने के लिए क्या उपाय सुझाएंगे?

1.5 भारत की 16वीं जनगणना (2027) और जातिगत जनगणना

यह राष्ट्रीय नीति (National Policy), सामाजिक डेटा (Social Data) और संवैधानिक प्रावधानों (Constitutional Provisions) से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**

- **16वीं जनगणना:** 2021 में विलंबित; अब 2027 में आयोजित होगी। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी।
- **राज्य समिति:** जनगणना के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन।
- **प्रक्रिया:** दो चरण: हाउस लिस्टिंग और जनसंख्या की गणना (आयु, शिक्षा, रोजगार, जाति शामिल)।
- **जातिगत जनगणना को मंजूरी:** केंद्र सरकार ने विलंबित जनगणना 2021 में जाति गणना को शामिल करने की मंजूरी दी है।
- **जातिगत जनगणना का महत्व:** विभिन्न जाति समूहों के सामाजिक-आर्थिक वितरण को समझना; आरक्षण और कल्याण से संबंधित नीतियों को प्रभावी रूप से तैयार करना।
- **चुनौतियाँ (जातिगत):** जातिगत पहचान को सुदृढ़ करने का जोखिम (सामाजिक विभाजन); राजनीतिक शोषण (वोट बैंक की राजनीति); आरक्षण की 50 % सीमा की पुनः समीक्षा की मांग।
- **अंतिम पूर्ण जाति जनगणना:** वर्ष 1931।

- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**

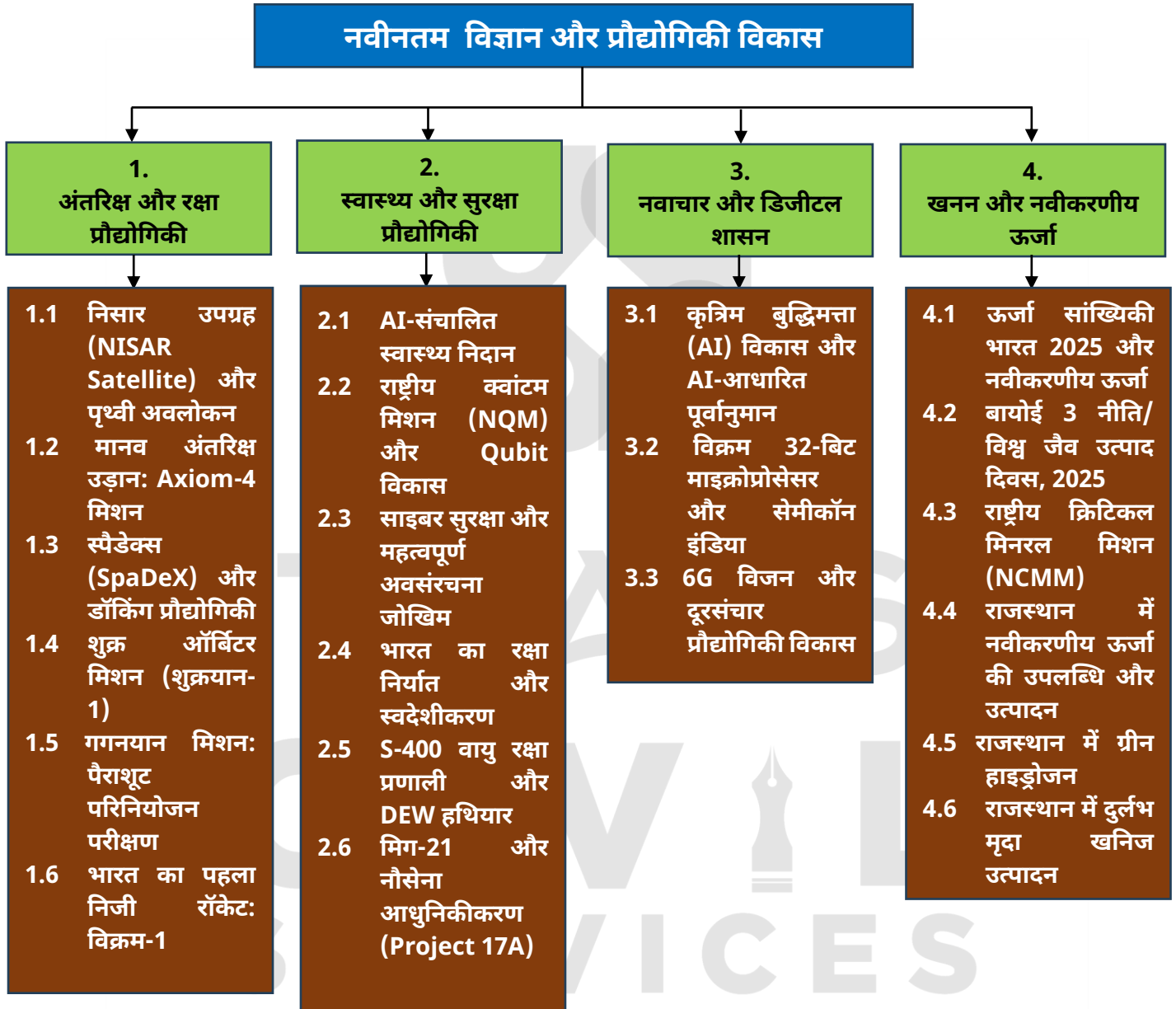
- जातिगत जनगणना (Caste Census) कराने के पक्ष और विपक्ष में नैतिक तर्क (Ethical Arguments) क्या हैं?
- भारत की पहली डिजिटल जनगणना की चुनौतियाँ और लाभ क्या हैं, विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में?

- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

- क्या जातिगत जनगणना समाज में 'समता' (Equity) लाने में मदद करेगी, या यह 'जातिवाद' (Casteism) और विभाजन (Division) को मजबूत करेगी?
- इंदिरा साहनी निर्णय (1992) के तहत आरक्षण की 50 % सीमा को देखते हुए, जातिगत जनगणना के बाद क्या संवैधानिक चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी?



04. नवीनतम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास (Latest Science and Technology Developments)



RAS 2024 INTERVIEW GUIDANCE PROGRAM



डॉ. ललित के. पुरी सर
(रिटायर्ड आईएएस) पूर्व अध्यक्ष, RPSC



अशोक गौड़
(Rank 20, RAS 2023)



डॉ. ए. के. मलिक सर
विज्ञान सचिव और राजस्थान विज्ञान



दीपल खान सर
सिखित सचिव और राजस्थान विज्ञान



Scan the QR Code to watch the **Detailed video solution of Probable & Counter Questions**



1. अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी
(Space and Defence Technology)

1.1 निसार उपग्रह (NISAR Satellite) और पृथ्वी अवलोकन

यह भारत-अमेरिका सहयोग से पृथ्वी अवलोकन (Earth Observation) और आपदा प्रबंधन (Disaster Management) में एक बड़ी सफलता है।

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- पूर्ण रूप: नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar)।
- प्रकृति: भूमि और बर्फ की निगरानी के लिए दोहरी आवृत्ति एसएआर तकनीक का उपयोग करने वाला संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह।
- रडार बैंड: L-बैंड SAR (नासा द्वारा) और S-बैंड SAR (इसरो द्वारा)। L-बैंड वन आच्छादन और बर्फ में प्रवेश कर सकता है।
- प्रक्षेपण: 31 जुलाई, 2025 को जीएसएलवी-एफ16 के माध्यम से श्रीहरिकोटा से।
- उद्देश्य: सेंटीमीटर स्तर की सटीकता के साथ भूमि और बर्फ की सतह की सूक्ष्म गतिविधियों का पता लगाना; भूकंप, बाढ़, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर नज़र रखना; वनों के बायोमास और कार्बन स्टॉक का मापन करना।
- भारत के लिए महत्व: भारत-अमेरिका अंतरिक्ष संबंधों में महत्वपूर्ण कदम; आपदा प्रबंधन, कृषि और जलवायु निगरानी का समर्थन करता है।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- NISAR मिशन क्या है, और आपदा प्रबंधन (Disaster Management) तथा जलवायु परिवर्तन (Climate Change) की निगरानी में यह कैसे सहायक होगा?
- L-बैंड और S-बैंड रडार में क्या अंतर है, और NISAR में दोनों का उपयोग क्यों किया जा रहा है?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्या NISAR से प्राप्त डेटा का उपयोग कृषि में भी किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे?
- क्या भारत ने Artemis Accords पर हस्ताक्षर किए हैं? यह अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की नीति को कैसे प्रभावित करता है?

1.2 मानव अंतरिक्ष उड़ान: Axiom-4 मिशन और गगनयान

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- Ax-4 मिशन: अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए चौथी निजी अंतरिक्ष उड़ान; शुभांशु शुक्ला ने पायलट के रूप में संचालन किया।
- उपलब्धि: शुभांशु शुक्ला ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय और अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय (राकेश शर्मा के बाद) बने।
- महत्वपूर्ण प्रयोग: सूक्ष्म और अत्यंत सहनशील जीव टार्डिग्रेड्स (Water Bears) को ISS पर भेजा गया, ताकि जीवन का चरम स्थितियों में अस्तित्व का अध्ययन किया जा सके।
- टार्डिग्रेड्स: सूक्ष्म, अष्टपदीय जीव जो क्रिप्टोबायोसिस (लगभग पूर्ण चयापचय बंद हो जाना) और एनहाइड्रोबायोसिस ('टन' अवस्था में प्रवेश) द्वारा -272.95°C से 150°C तक के तापमान को सहन कर सकते हैं।
- गगनयान कार्यक्रम (लक्ष्य): 2027 की पहली तिमाही में पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान; 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) की स्थापना; 2040 तक भारतीय चालक दल का चंद्रमा पर उतरना।
- ट्रेनिंग: भारतीय वायु सेना के चार परीक्षण पायलटों का चयन किया गया है, जिनमें ग्रुप कैप्टन एस शुक्ला भी शामिल हैं।

- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**

- गगनयान मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए Ax-4 मिशन के दौरान किए गए वैज्ञानिक प्रयोग (जैसे टार्डिग्रेड्स) कितने महत्वपूर्ण हैं?
- गगनयान कार्यक्रम की महत्वाकांक्षाएँ (2035 तक BAS, 2040 तक चंद्रमा) भारत की 'अंतरिक्ष शक्ति' (Space Power) के रूप में स्थिति को कैसे मजबूत करेगी?

- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

- टार्डिग्रेड्स (Water Bears) में 'क्रिप्टोबायोलिसिस' (Cryptobiosis) की प्रक्रिया क्या है? इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है?
- मानव अंतरिक्ष उड़ान (Human Space Flight) के लिए **डॉकिंग तकनीक** (Docking Technology) क्यों आवश्यक है, जैसा कि चंद्रयान-4 मिशन में भी देखा गया है?

1.3 स्पेडेक्स (SpaDeX) और डॉकिंग प्रौद्योगिकी

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**

- **प्रकृति:** इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन।
- **उद्देश्य:** निम्न-पृथ्वी कक्षा में दो छोटे उपग्रहों (SDX01 - चेज़र, SDX02 - टारगेट) को **डॉकिंग और अनडॉक करने** की क्षमता को प्रमाणित करना।
- **उपलब्धि:** डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी करने वाला **भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश** बन गया है।
- **महत्व:** यह **मॉड्यूलर स्पेस इन्फ्रास्ट्रक्चर** (अंतरिक्ष स्टेशन) बनाने, **अंतरग्रहीय और चंद्र मिशनों** के लिए कक्षीय ईंधन भरने (Orbital Refueling) में और **उपग्रह सर्विसिंग** (Satellite Servicing) के लिए महत्वपूर्ण है।

- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**

- SpaDeX मिशन की तकनीकी उपलब्धि क्या है, और यह **भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS)** के निर्माण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
- **'स्पेस डॉकिंग'** (Space Docking) तकनीक का उपयोग किन अन्य अंतरिक्ष अभियानों (जैसे ISS) में किया गया है?

- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

- **'उपग्रह सर्विसिंग'** (Satellite Servicing) क्या है, और यह **अंतरिक्ष मलबे** (Space Debris) की चुनौती से कैसे निपट सकती है?
- क्या यह उपलब्धि **चंद्रयान-4** मिशन की जटिलता को कम करने में सहायता करेगी?

1.4 शुक्र ऑर्बिटर मिशन (शुक्रयान-1)

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**

- **घोषणा/लक्ष्य:** केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा **सितंबर 2024** में मंजूरी; **2028** में लॉन्च की उम्मीद।
- **प्रकृति:** इसरो का शुक्र ग्रह (Venus) पर पहला मिशन, जिसे GSLV Mk II रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** शुक्र के वायुमंडल, सतह और सूर्य के साथ इसकी परस्पर क्रिया का व्यापक अध्ययन करना।
- **पेलोड:** इसमें **S-बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR)** और **ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार** जैसे उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपकरण शामिल होंगे।
- **महत्व:** सक्रिय ज्वालामुखी (Active Volcanism) की खोज करना, सल्फ्यूरिक एसिड बादलों (Sulfuric Acid Clouds) के नीचे की सतह का मानचित्रण करना, और ग्रह के विकास (Planetary Evolution) को समझना।
- **जीवन के संकेत:** शुक्र के बादलों में **फॉस्फीन (Phosphine)** की खोज ने **सूक्ष्मजीव जीवन (Microbial Life)** की संभावनाओं को बढ़ाया है, जिसकी यह मिशन जांच कर सकता है।

- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**

- शुक्र ऑर्बिटर मिशन (VOM) के प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य क्या हैं, और यह मिशन शुक्र पर **सल्फ्यूरिक एसिड बादलों** के नीचे की सतह का अध्ययन कैसे करेगा?
- शुक्र को **"पृथ्वी का जुड़वाँ"** (Earth's Twin) क्यों कहा जाता है? शुक्र का अध्ययन करना पृथ्वी के विकास को समझने में कैसे मदद कर सकता है?

- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

- गहरे अंतरिक्ष मिशनों (Deep Space Missions) में **शक्ति प्रणाली** (Power Systems) की क्या चुनौतियाँ हैं, खासकर शुक्र के सघन बादलों के कारण?
- क्या शुक्रयान मिशन भारत के **स्पेस विजन 2047** का हिस्सा है?

1.5 गगनयान मिशन: पैराशूट परिनियोजन परीक्षण

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **परीक्षण:** इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल (Crew Module) के लिए मुख्य पैराशूटों का एकीकृत मुख्य पैराशूट एयरड्रॉप टेस्ट (IMAT) झाँसी के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक आयोजित किया।
- **सुरक्षा प्रोटोकॉल:** गगनयान पैराशूट प्रणाली में कुल 10 पैराशूट (4 प्रकार के) शामिल हैं। तीन मुख्य पैराशूटों में से दो सुरक्षित लैंडिंग के लिए पर्याप्त हैं (अतिरेक/Redundancy सुनिश्चित)।
- **तकनीकी चुनौती:** परीक्षण ने दो मुख्य पैराशूटों के बीच "डिस्-रीफिंग में देरी" (Delay in Disreefing) के एक संभावित चरम परिदृश्य को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया, जो असममित भार (Asymmetric Load) स्थितियों में प्रणाली की मजबूती को मान्य करता है।
- **प्रक्रिया:** पैराशूट रीफ़्ड इन्फ्लेशन प्रक्रिया (Reefed Inflation Process) के माध्यम से पहले आंशिक रूप से और फिर विलंब के बाद पूरी तरह से खुलते हैं।
- **महत्व:** यह मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए पैराशूट प्रणाली को अर्हता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- गगनयान मिशन के लिए पैराशूट प्रणाली का परीक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? "अतिरेक" (Redundancy) का सिद्धांत अंतरिक्ष मिशनों में कैसे काम करता है?
- पैराशूटों में "रीफ़्ड इन्फ्लेशन" (Reefed Inflation) प्रक्रिया क्या है, और यह क्यों आवश्यक है?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- पैराशूट परीक्षण में भारतीय वायु सेना के IL-76 विमान का उपयोग क्यों किया गया?
- गगनयान मिशन में व्योममित्र (Vyommitra) की भूमिका क्या होगी?

1.6 भारत का पहला निजी रॉकेट: विक्रम-1

यह अंतरिक्ष क्षेत्र के उदारीकरण (Space Sector Liberalization) और निजी नवाचार में भारत की सफलता को दर्शाता है।

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **कंपनी:** हैदराबाद स्थित स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace), पूर्व इसरो वैज्ञानिकों द्वारा 2018 में स्थापित।
- **मिशन:** भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित वाणिज्यिक रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी।
- **पिछला मिशन:** स्काईरूट ने 2022 में 'मिशन प्रारंभ' के तहत भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम-एस (उप-कक्षीय परीक्षण) लॉन्च करके इतिहास रचा था।
- **रॉकेट प्रौद्योगिकी:** विक्रम-श्रृंखला के रॉकेट कार्बन कंपोजिट और 3D-मुद्रित इंजन (3D-Printed Engines) का उपयोग करते हैं, जिससे विनिर्माण तेज और लागत कम होती है।
- **लक्ष्य:** छोटे उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करके वैश्विक वाणिज्यिक लॉन्च बाजार में भारत के प्रवेश को चिह्नित करना।
- **समर्थन:** IN-SPACe की देखरेख में निजी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 2020 के अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों का प्रतीक

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- विक्रम-1 रॉकेट का लॉन्च भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक "नया अध्याय" क्यों है?
- रॉकेट निर्माण में 3D-मुद्रित इंजनों (3D-Printed Engines) और कार्बन कंपोजिट (Carbon Composites) का उपयोग करने के क्या लाभ हैं?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- IN-SPACe की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था?
- निजी रॉकेटों का उदय इसरो (ISRO) के मिशनों और भूमिका को कैसे प्रभावित करेगा?

2. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रौद्योगिकी (Health and Security Technology)

2.1 AI-संचालित स्वास्थ्य निदान (AI in Healthcare Diagnostics)

यह दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और दक्षता में क्रांति ला रहा है।

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- समस्या: दूरदराज के क्षेत्रों में समय पर और सटीक रेडियोलॉजी निदान की सीमित पहुंच, और रेडियोलॉजिस्टों पर अत्यधिक बोझ।
- समाधान (भारतीय स्टार्टअप्स):
 - Qure.ai: qXR और qER जैसे AI-संचालित उपकरण एक्स-रे और सीटी स्कैन का विश्लेषण करके तपेदिक, स्ट्रोक और सिर की चोटों जैसे गंभीर रोगों का सेकंडों में पता लगाते हैं।
 - Niramai: विकिरण-मुक्त (Radiation-free) थर्मल इमेजिंग का उपयोग करके स्तन कैंसर का जल्दी पता लगाना, जिससे कम सेवा वाले क्षेत्रों में स्क्रीनिंग सुलभ होती है।
 - Tricog Health: InstaECG प्लेटफॉर्म रीयल-टाइम ECG की व्याख्या प्रदान करता है, जिससे दूरस्थ क्लिनिकों में भी दिल के दौरे (Heart Attacks) का तुरंत निदान संभव होता है।
 - Dozee: गद्दे के नीचे सेंसर का उपयोग करके हृदय गति और श्वसन जैसे महत्वपूर्ण संकेतों की संपर्क रहित निगरानी।
- तकनीकी आधार: ये उपकरण GPU क्लाउड (GPU Cloud) का उपयोग करके बड़े डेटासेट पर प्रशिक्षित हैं, जिससे सटीकता 5 % से कम त्रुटि दर के साथ बढ़ जाती है।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- AI-संचालित निदान (AI-Powered Diagnostics) भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में क्षेत्रीय असमानताओं (Regional Disparities) को कम करने में कैसे मदद कर सकता है?
- टेलीमेडिसिन (Telemedicine) और AI निदान के एकीकरण से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- AI निदान में डेटा गोपनीयता (Data Privacy) और सुरक्षा (Security) सुनिश्चित करने के लिए क्या नैतिक उपाय आवश्यक हैं?

2.2 राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) और Qubit विकास

यह अगली पीढ़ी के कंप्यूटिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत की लंबी अवधि की रणनीति है।

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- मिशन: राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM), 2023 - 24 से 2030 - 31 तक ₹6,003.65 करोड़ के बजट के साथ स्वीकृत।
- उद्देश्य: संचार, क्रिप्टोग्राफी, कंप्यूटिंग और सेंसिंग जैसे क्षेत्रों में क्वांटम प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना।
- लक्ष्य (Qubit): 8 वर्षों में 50 - 1000 भौतिक क्यूबिट (Physical Qubits) वाले मध्यवर्ती-स्केल क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना।
- उपलब्धियां:
 - भारतीय स्टार्टअप QpiAi ने 25 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर 'Indus' का अनावरण किया, जो देश का पहला फुल-स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है।
 - DRDO और TIFR के वैज्ञानिकों ने 6-क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर का सफल परीक्षण किया।
- सुरक्षा: क्वांटम कुंजी वितरण (QKD) का उपयोग करके 2000 किमी तक उपग्रह-सक्षम क्वांटम-सुरक्षित संचार स्थापित करना।
- अनुप्रयोग: दवा खोज (Drug Discovery), अंतरिक्ष अन्वेषण, बैंकिंग, और सुरक्षा।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- क्वांटम कंप्यूटिंग (Quantum Computing) पारंपरिक सुपरकंप्यूटिंग से कैसे भिन्न है? 'क्यूबिट' (Qubit) क्या है?
- राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) और क्रिप्टोग्राफी को कैसे सुरक्षित करेगा?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्वांटम कुंजी वितरण (QKD) की अवधारणा क्या है? क्या यह भविष्य में साइबर हमलों को पूरी तरह से रोक सकता है?
- QpiAi-Indus का विकास भारत के 'टेक्नोलॉजी हब' बनने की महत्वाकांक्षाओं को कैसे बल देता है?

2.3 साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण अवसंरचना जोखिम

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- घटनाओं में वृद्धि: CERT-In के डेटा के अनुसार, भारत में रिपोर्ट किए गए साइबर सुरक्षा घटनाओं की संख्या 2022 में 13.9 लाख से बढ़कर 2024 में 20.4 लाख हो गई।
- खतरे का स्वरूप: AI-जनित धोखाधड़ी, पहचान-आधारित कमजोरियाँ (Identity-driven threats), रैंसमवेयर, और आपूर्ति श्रृंखला हमले (Supply Chain Attacks) प्रमुख हैं।
- दूसरा चरण का खतरा: विशेषज्ञ भारत के खिलाफ "साइबर-आतंक के दूसरे चरण" की चेतावनी दे रहे हैं, जहाँ हमलावर जांच प्रक्रिया को ही विफल करने की कोशिश करते हैं।
- जांच की कमजोरी: SCADA कमांड या सर्वर लॉग जैसे डिजिटल साक्ष्य (Digital Evidence) बहुत नाजुक होते हैं; गलत वर्गीकरण और जांच में देरी से डिजिटल साक्ष्य नष्ट हो जाता है।
- समाधान की मांग: मानकीकृत वर्गीकरण प्रोटोकॉल, 72-घंटे डिजिटल साक्ष्य संरक्षण अधिदेश, और विशेषज्ञों को काम पर रखने की मांग (Rubrik रिपोर्ट के अनुसार, 90% भारतीय संगठन विशिष्ट पेशेवरों को काम पर रखने की तैयारी कर रहे हैं)।
- बीमा: साइबर बीमा बाजार का तेजी से बढ़ना (29 % CAGR) बढ़ रहे जोखिम को प्रबंधित करने का एक तरीका है।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं की बढ़ती संख्या और परिष्कार (Sophistication) के पीछे मुख्य कारण क्या हैं?
- महत्वपूर्ण अवसंरचना (Critical Infrastructure) की सुरक्षा के लिए डिजिटल साक्ष्य संरक्षण (Digital Evidence Preservation) क्यों इतना आवश्यक है?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- साइबर बीमा (Cyber Insurance) राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के लिए एक सक्रिय (Proactive) या प्रतिक्रियाशील (Reactive) समाधान है?
- एक प्रशासक के रूप में आप साइबर स्वच्छता (Cyber Hygiene) के बारे में जागरूकता कैसे बढ़ाएंगे?

2.4 भारत का रक्षा निर्यात और स्वदेशीकरण

यह भारत की रक्षा विनिर्माण शक्ति और 'मेक इन इंडिया' को प्रदर्शित करता है।

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- रिकॉर्ड निर्यात: वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात ₹23,622 करोड़ (लगभग 2.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।
- योगदान: निजी क्षेत्र (64.5%) और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (DPSUs)।
- प्रमुख खरीदार: संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया।
- निर्यात पोर्टफोलियो: आकाश मिसाइल (SAM), एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (ATAGS), हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH ध्रुव)।
- सुधार पहलें: रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX), रक्षा औद्योगिक गलियारे (DICs), औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण, और सृजन पोर्टल।
- लक्ष्य: 2029 तक अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाकर ₹50,000 करोड़ करना।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर क्यों पहुंचा है? यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में क्या दर्शाता है?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- रक्षा निर्यात में निजी क्षेत्र (Private Sector) के बढ़ते योगदान का क्या महत्व है?
- रक्षा उपकरणों के लिए आयात निर्भरता (Import Dependency) को कम करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

2.5 S-400 वायु रक्षा प्रणाली और DEW हथियार

यह भारत की वायु रक्षा क्षमताओं और रणनीतिक निरोध को दर्शाता है।

• प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **S-400:** रूसी मूल की लंबी दूरी की, बहुस्तरीय सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, जिसे भारतीय सेवा में 'सुदर्शन चक्र' नाम दिया गया है।
- **भूमिका:** पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर हवाई क्षेत्र निषेध (Air Space Denial) और निवारण सुनिश्चित करना; विमान, कूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता है।
- **परिचालन:** ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया।
- **रणनीतिक अधिग्रहण:** अधिग्रहण में CAATSA (काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट) के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा शामिल था, जिसके लिए भारत-विशिष्ट छूट (India-specific waiver) को मंजूरी दी गई।
- **DEW प्रणाली:** भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एमके-II (ए) लेजर-डायरेक्टेड एनर्जी वेपन (DEW) प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
- **DEW विशेषता:** 30 किलोवाट लेजर; लागत प्रभावी (फायरिंग लागत = कुछ लीटर पेट्रोल); ड्रोन और मिसाइलों को न्यूनतम क्षति के साथ बेअसर करने के लिए आदर्श।
- **सामरिक बढ़त:** DEW क्षमताओं के मामले में भारत को अमेरिका, चीन और रूस के साथ स्थान मिला

• संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- S-400 प्रणाली भारत की रणनीतिक निरोध (Strategic Deterrence) क्षमता को कैसे मजबूत करती है?
- लेजर-निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEW) प्रणाली का विकास भारत की रक्षा क्षमताओं में 'गेम चेंजर' क्यों साबित हो सकता है?

• संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्या S-400 जैसे हथियारों का अधिग्रहण CAATSA के तहत भारत की स्वायत्त विदेश नीति पर दबाव डालता है?
- DEW हथियार पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में लागत प्रभावी (Cost-Effective) कैसे होते हैं?

2.6 मिग-21 और नौसेना आधुनिकीकरण (Project 17A)

यह रक्षा आधुनिकीकरण और नौसेना शक्ति के विस्तार को दर्शाता है।

• प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **मिग-21:** 1963 में भारतीय वायु सेना में शामिल; सोवियत संघ द्वारा डिज़ाइन किया गया; 400 से अधिक दुर्घटनाओं के कारण "उड़ते ताबूत" के रूप में जाना जाता है।
- **सेवानिवृत्ति:** भारतीय वायु सेना सितंबर 2025 में अपने अंतिम दो मिग-21 बाइसन स्क्वाड्रनों को सेवानिवृत्त कर देगी।
- **प्रतिस्थापन:** स्वदेशी रूप से विकसित तेजस एमके-1ए लड़ाकू विमानों के पक्ष में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है।
- **P-17A:** उन्नत प्रोजेक्ट 17A मल्टी-मिशन स्टील्थ फ्रिगेट (INS उदयगिरि और INS हिमगिरि) को पहली बार एक साथ नौसेना में शामिल किया गया।
- **स्वदेशीकरण:** P-17A जहाज़ों में उन्नत स्टील्थ क्षमताएँ हैं और वे ब्रह्मोस मिसाइल और शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से सुसज्जित हैं
- **उदयगिरि:** नौसेना के वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया 100वाँ जहाज़ भी है।

• संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- मिग-21 को 'उड़ता ताबूत' (Flying Coffin) क्यों कहा जाता था? इसका सेवानिवृत्त होना भारतीय वायु सेना के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
- प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील्थ फ्रिगेट (Stealth Frigates) का विकास भारत की 'ब्लू वाटर' नौसेना की महत्वाकांक्षाओं को कैसे साकार करता है?

• संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- भारतीय वायु सेना में मिग-21 का प्रतिस्थापन तेजस से क्यों किया जा रहा है? स्वदेशीकरण का क्या महत्व है?
- नौसेना में स्टील्थ तकनीक (Stealth Technology) क्या है, और यह पारंपरिक जहाज़ों से कैसे भिन्न है?

3. नवाचार और डिजीटल शासन (Innovation and Digital Governance)

3.1 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विकास और AI-आधारित पूर्वानुमान

यह AI के आर्थिक गुणक (Economic Multiplier) और समावेशी शासन (Inclusive Governance) में अनुप्रयोग को दर्शाता है।

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- आर्थिक गुणक: AI वर्ष 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 967 अरब डॉलर जोड़ने की संभावना है (GVA में 15% की वृद्धि)।
- रोजगार पर प्रभाव: AI सृजनात्मक विनाश (Creative Destruction) लाता है; एक ओर पुरानी नौकरियों को प्रभावित करता है, वहीं दूसरी ओर भारत के विशाल अनौपचारिक कार्यबल को औपचारिक बनाने और उसकी उत्पादकता बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करता है।
- AI-आधारित पूर्वानुमान: कृषि मंत्रालय ने गूगल के न्यूरल GCM और ECMWF के AIFS मॉडल का उपयोग करके 3.8 करोड़ किसानों को SMS (M-किसान) के माध्यम से AI-आधारित मानसून पूर्वानुमान भेजे।
- शासन में अनुप्रयोग: स्वास्थ्य सेवा (TB निदान), शिक्षा (व्यक्तिगत शिक्षा), MSME प्रतिस्पर्धात्मकता, और पर्यावरण प्रबंधन।
- चुनौतियाँ: अपर्याप्त डेटा पारिस्थितिकी तंत्र, अनुसंधान एवं विकास में कम निवेश, और कौशल कार्यबल की कमी।
- रणनीति: अधिकार-आधारित AI फ्रेमवर्क अपनाना, डेटा संरक्षण व्यवस्था को मज़बूत बनाना (DPDP अधिनियम 2023), और कौशल विभाजन को कम करना।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- AI भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सृजनात्मक विनाश (Creative Destruction) का सिद्धांत कैसे लागू करता है?
- कृषि में AI-आधारित पूर्वानुमान (AI-based Forecasting) किसानों के लिए किस प्रकार वरदान साबित हो सकता है?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- भारत में AI के विकास में सबसे बड़ी बाधा 'डेटा पारिस्थितिकी तंत्र की कमी' क्यों है?
- आप डिजिटल विभाजन (Digital Divide) को कम करने के लिए AI को स्थानीय भाषाओं और क्षेत्रीय समस्याओं से कैसे जोड़ेंगे?

3.2 विक्रम 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर और सेमीकॉन इंडिया

यह सेमीकंडक्टर निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता और रणनीतिक तकनीक के विकास को दर्शाता है।

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- विक्रम 3201: इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला (SCL), चंडीगढ़ द्वारा विकसित।
- उद्देश्य: लॉन्च व्हीकल्स के नेविगेशन, गाइडेंस और नियंत्रण प्रणालियों में भारत की आत्मनिर्भरता को सक्षम बनाना।
- तकनीकी विशेषताएँ: -55°C से 125°C तक के चरम तापमान को सहन करने में सक्षम; एडा (Ada) प्रोग्रामिंग भाषा के लिए डिज़ाइन किया गया कस्टम इंस्ट्रक्शन सेट।
- सेमीकॉन इंडिया 2025: ₹76,000 करोड़ के निवेश के साथ SEMICON India प्रोग्राम शुरू किया गया (इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन - ISM के माध्यम से लागू)।
- लक्ष्य: वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य शृंखला में भारत की स्थिति को मज़बूत करना; चिप डिज़ाइन, पैकेजिंग और निर्माण में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करना।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- विक्रम 3201 माइक्रोप्रोसेसर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
- SEMICON India प्रोग्राम (ISM) का उद्देश्य क्या है, और यह भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनाने में कैसे मदद करेगा?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- माइक्रोप्रोसेसर के लिए चरम तापमान सहनशीलता (Extreme Temperature Tolerance) क्यों आवश्यक है?
- वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में "आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा" (Supply Chain Security) की क्या भूमिका है?

3.3 6G विजन और दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास

यह भारत के दूरसंचार में वैश्विक नेतृत्व और डिजिटल समावेशन की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है।

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **6G विजन 2030:** भारत को 6G प्रौद्योगिकी के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में वैश्विक सह-नेता के रूप में स्थापित करना।
- **विशेषताएँ:** 5G की तुलना में 1,000 गुना तेज़ (लगभग शून्य अंतराल); उच्च रेडियो आवृत्तियों का उपयोग; दूरस्थ चिकित्सा सर्जरी, स्मार्ट रोबोटिक्स के लिए उपयोगी।
- **गठबंधन:** भारत 6G अलायंस (B6GA) उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप्स और अनुसंधान संस्थानों को एक साथ लाता है।
- **लक्ष्य:** 2035 तक 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के GDP प्रभाव और 10 प्रतिशत वैश्विक 6G पेटेंट का अनुमान।
- **समर्थन:** दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (TTDF) योजना (1 अक्टूबर 2022 को शुरू)।
- **वैश्विक सहयोग:** NextG एलायंस (अमेरिका), 6G IA (यूरोप) और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) जैसे अग्रणी अनुसंधान गठबंधनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- 6G तकनीक 5G से कैसे भिन्न है, और इसका दूरस्थ चिकित्सा सर्जरी (Remote Surgery) जैसे क्षेत्रों में क्या विशिष्ट उपयोग होगा?
- भारत 6G में वैश्विक नेतृत्व क्यों चाहता है? यह केवल एक उपभोक्ता बनने के बजाय 'प्रौद्योगिकी निर्माता' बनने की महत्वाकांक्षा को कैसे दर्शाता है?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्या 6G तकनीक ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन (Digital Divide) को कम करने में मदद करेगी?
- भारत 6G अलायंस और दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (TTDF) की भूमिका क्या है?

4. खनन और नवीकरणीय ऊर्जा (Mining and Renewable Energy)

4.1 ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 और नवीकरणीय ऊर्जा

यह ऊर्जा मिश्रण, नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता और उपयोग के रुझानों पर केंद्रित है।

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **रिपोर्ट:** राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी 'ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 रिपोर्ट'।
- **खपत:** प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 14,682 मेगाजूल (2014-15) से बढ़कर 18,410 मेगाजूल (2023-24) हो गई। औद्योगिक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता:** भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 21 लाख मेगावाट है, जिसमें पवन ऊर्जा (55%) का सर्वाधिक योगदान है।
- **राज्यवार योगदान:** राजस्थान (20.3%), महाराष्ट्र (11.8%) और गुजरात (10.5%) की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50% से अधिक हिस्सेदारी है।
- **लक्ष्य:** 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करना

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पवन ऊर्जा (Wind Power) का सर्वाधिक योगदान क्यों है, जबकि सौर ऊर्जा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है?
- प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में वृद्धि किस आर्थिक विकास को दर्शाती है?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए (ऊर्जा दक्षता)?
- 'टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई' (TPES) क्या है?

4.2 बायोई 3 नीति/ विश्व जैव उत्पाद दिवस 2025

यह जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology) और चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) के भविष्य को दर्शाता है।

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**

- नीति: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति को मंजूरी दी है।
- लक्ष्य: जैव विनिर्माण और जैव-एआई हब तथा बायोफाउंड्री की स्थापना करना।
- उद्देश्य: जलवायु परिवर्तन शमन, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों का समाधान करना, और चक्रीय प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- जैव अर्थव्यवस्था की स्थिति: 2023 तक भारत के GDP में 4.25% का योगदान; 2014 के 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 में 151 बिलियन डॉलर हो गई है।
- बायोफाउंड्री: डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण और सीख (DBTL) मॉडल पर काम करेगी, जिसमें एआई का उपयोग शामिल है।
- अंतरिक्ष अनुसंधान: तीन स्वदेशी मजबूत सूक्ष्म शैवाल प्रजातियों (Microalgae Strains) का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर किया गया।

- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**

- बायोई3 नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) के सिद्धांतों का समर्थन कैसे करती है?
- बायोफाउंड्री में डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण और सीख (DBTL) मॉडल कैसे कार्य करता है?

- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

- जैव-अर्थव्यवस्था (Bio-Economy) और हरित अर्थव्यवस्था (Green Economy) के बीच क्या अंतर है?
- अंतरिक्ष अनुसंधान (Space Research) में शैवाल प्रजातियों के प्रयोग का क्या महत्व है?

4.3 राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनेरल मिशन (NCMM)

यह आयात निर्भरता कम करने और ऊर्जा संक्रमण को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण है।

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**

- विधेयक: खनिज और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पारित।
- क्रिटिकल मिनेरल्स: आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक खनिज; जिनकी आपूर्ति दुर्लभता या सीमित भौगोलिक संकेंद्रण के कारण जोखिमग्रस्त हो।
- भारत की निर्भरता: भारत लिथियम और निकल के लिए 100% आयात पर निर्भर है।
- MMDR संशोधन: पट्टाधारकों को बिना अतिरिक्त रॉयल्टी दिए अपनी मौजूदा लीज़ में महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज शामिल करने की अनुमति। कैप्टिव माइंस पर 50% बिक्री सीमा को हटाया गया।
- NCMM: खान मंत्रालय के तहत 2025 में लॉन्च; उद्देश्य क्रिटिकल मिनेरल्स आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित करना और घरेलू तथा विदेशी स्रोतों से उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- वैश्विक कूटनीति: KABIL (NALCO-HCL-MECL का संयुक्त उद्यम) के माध्यम से अर्जेंटीना में 5 लिथियम खनिज ब्लॉक्स सहित विदेशों में खनिजों का अन्वेषण और अधिग्रहण।

- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**

- क्रिटिकल मिनेरल्स (Critical Minerals) क्या हैं, और भारत की ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition) में इनकी क्या भूमिका है?
- NCMM भारत की आयात निर्भरता (Import Dependency) को कम करने और चीन पर निर्भरता को कम करने में कैसे मदद करेगा?

- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**

- कैप्टिव माइंस पर बिक्री सीमा हटाने से खनन क्षेत्र को क्या लाभ होगा?
- KABIL का उद्देश्य क्या है, और यह विदेशों में खनिज अधिग्रहण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

4.4 राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन (Green Hydrogen)

यह उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर है, जो ऊर्जा संक्रमण में क्षेत्रीय नेतृत्व को दर्शाता है।

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**

- क्लस्टर: आईआईटी जोधपुर में लगभग ₹205 करोड़ की लागत से उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर स्थापित किया जाएगा।
- उत्पादन: यह क्लस्टर सालाना करीब 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा।

- स्रोत: नवीकरणीय ऊर्जा, जोधपुर के शहरों से निकलने वाले गंदे पानी से हाइड्रोजन का निर्माण, और 15 टन सालाना जैवमास से।
- उपयोग: परिवहन, उद्योगों के लिए अमोनिया उत्पादन और सिटी गैस वितरण नेटवर्क में मिश्रण के रूप में।
- राष्ट्रीय महत्व: यह देश का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर होगा, जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) का हिस्सा है
- संभावित प्रश्न (Potential Questions):
 - ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, और यह ब्लू हाइड्रोजन या ग्रे हाइड्रोजन से कैसे भिन्न है?
 - आईआईटी जोधपुर में ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर स्थापित करने से राजस्थान के गंदे पानी और जैवमास (Biomass) का उपयोग कैसे होगा?
- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):
 - राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) का मुख्य लक्ष्य क्या है?
 - ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन लागत (1-3 डॉलर प्रति किलोग्राम) प्राप्त करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

4.5 राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धि और उत्पादन

यह राजस्थान की सौर ऊर्जा नेतृत्व और PM-KUSUM की सफलता को दर्शाता है।

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):
 - PM-KUSUM सफलता: राजस्थान ने PM-KUSUM के तहत 2,000 मेगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त किया। घटक-A में भारत में पहले स्थान पर।
 - सौर क्षमता: कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का 70% है; सौर ऊर्जा से 29.5 गीगावाट और पवन ऊर्जा से 5.2 गीगावाट। स्थापित सौर क्षमता के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर।
 - नीति लक्ष्य: एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना
 - गोरबिया परियोजना: बीकानेर में 435 मेगावाट की परियोजना; प्रतिवर्ष 705,000 टन CO2 उत्सर्जन को रोकेगी।
 - सफाई तकनीक: MIT इंजीनियरों द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण का उपयोग करते हुए जलरहित, संपर्क रहित सफाई विधि विकसित की गई (रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण)
- संभावित प्रश्न (Potential Questions):
 - PM-KUSUM योजना किसानों को सौर ऊर्जा उत्पादक (Solar Energy Producer) बनने में कैसे मदद करती है?
 - 125 गीगावाट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राजस्थान को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा?
- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):
 - राजस्थान में पवन ऊर्जा की तुलना में सौर ऊर्जा पर अधिक जोर क्यों दिया जा रहा है?

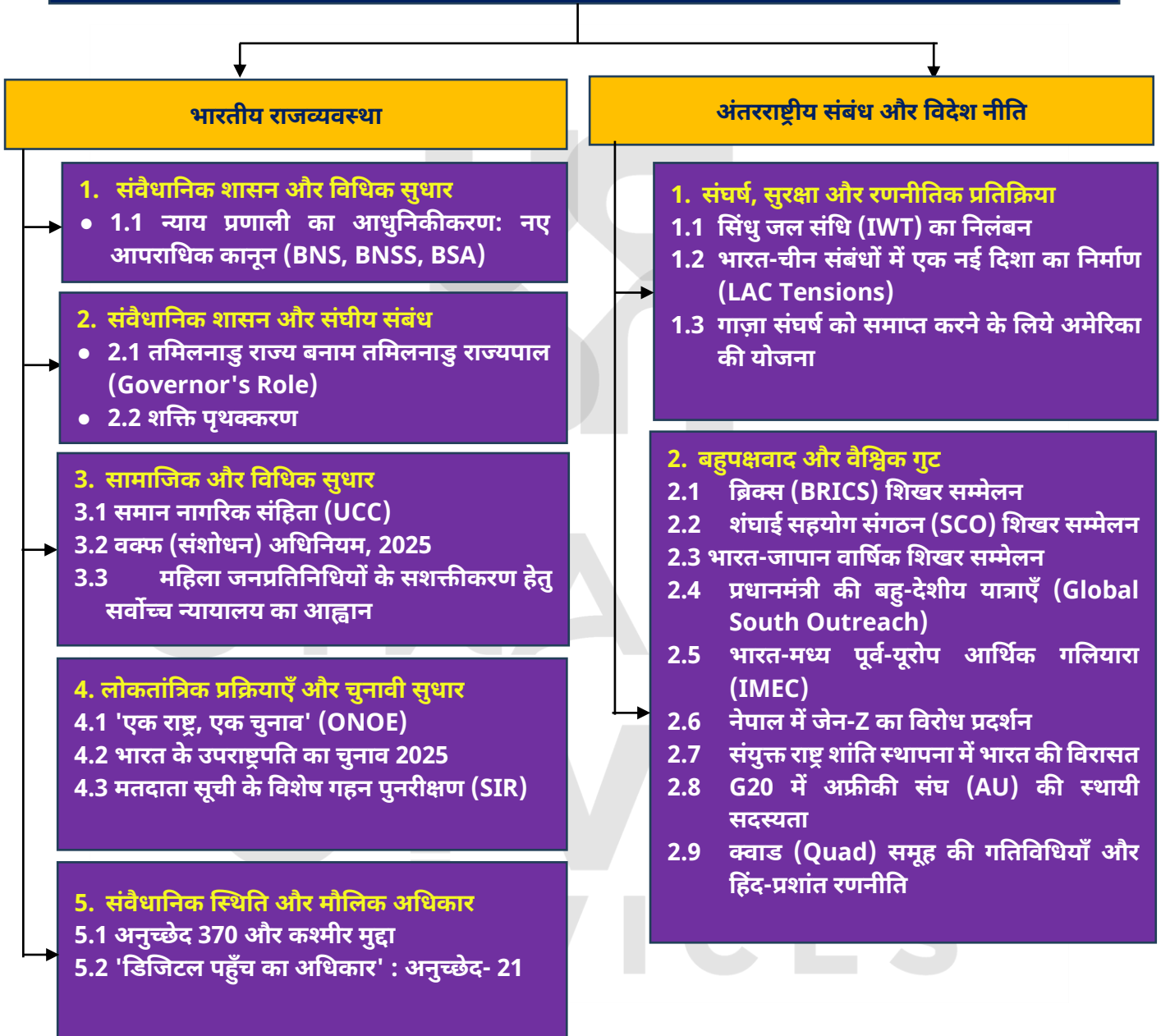
4.6 राजस्थान में दुर्लभ मृदा खनिज उत्पादन

यह रणनीतिक खनिजों (Strategic Minerals) के घरेलू अन्वेषण में महत्वपूर्ण है।

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):
 - खोज: बालोतरा स्थित सिवाना तहसील के भाटी खेड़ा में दुर्लभ मृदा खनिजों (Rare Earth Elements - REEs) के बड़े भंडार का पता चला है।
 - विशेषता: यह देश का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ खनिज ब्लॉक बनने जा रहा है, जिसमें कठोर चट्टान ग्रेनाइट में दुर्लभ मृदा खनिज मौजूद होंगे।
 - महत्व: REEs का उपयोग उच्च तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेट्स, नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों और रक्षा क्षेत्र में किया जाता है।
 - AI का उपयोग: राजस्थान सरकार ने खनिज अन्वेषण (Mineral Exploration) में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) का इस्तेमाल करने का फैसला किया है।
 - पायलट प्रोजेक्ट: भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ के कुछ क्षेत्रों में AI तकनीक का उपयोग
- संभावित प्रश्न (Potential Questions):
 - दुर्लभ मृदा खनिज (REEs) क्या हैं, और भारत की अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षेत्र के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण हैं?
 - खनिज अन्वेषण (Mineral Exploration) में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग पारंपरिक तरीकों की तुलना में कैसे अधिक कुशल और सटीक है?
- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):
 - चीन का दुर्लभ मृदा खनिजों के वैश्विक प्रसंस्करण पर प्रभुत्व क्यों है?
 - हार्ड रॉक में खनन, लिथियम क्ले में खनन की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण क्यों होता है?

05. भारतीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध और समकालीन विदेश नीति के मुद्दे (Indian Polity, International relations and contemporary foreign policy issues)

भारतीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध और समकालीन विदेश नीति के मुद्दे



RAS 2024 INTERVIEW GUIDANCE PROGRAM



डॉ. ललित के. पंवार सर
(रिटायर्ड आईएएस) पूर्व अध्यक्ष, RPSC



अंशुल गोएल
(Rank 20, RAS 2023)



डॉ. ए के मलिक सर
पिछले वर्ष विदेश एवं वाणिज्य विभाग



दीपक चंदन सर
सिखार मंत्रालय, वित्त एवं विदेश



Scan the
QR Code
to watch the
**Detailed video
solution of Probable
& Counter Questions**



1. संवैधानिक शासन और विधिक सुधार (Constitutional Governance and Legal Reforms)

1.1. न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण: नए आपराधिक कानून (BNS, BNSS, BSA)

यह उपनिवेशकालीन आपराधिक न्याय प्रणाली (Colonial Criminal Justice System) को नागरिक-केंद्रित (Citizen-Centric) बनाने का सबसे बड़ा विधिक सुधार है।

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- प्रतिस्थापन: भारतीय दंड संहिता (IPC, 1860) की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS); दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC, 1973) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS); और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEA, 1872) की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)।
- लागू: तीनों कानून 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गए (कुछ अपवादों के साथ)।
- BNS में प्रावधान: सामुदायिक सेवा (Community Service) को पहली बार छोटे अपराधों (जैसे <₹5,000 की चोरी) के लिए वैकल्पिक सज़ा के रूप में पेश किया गया। नाबालिग से गैंग रेप के लिए मृत्यु दण्ड तक की सज़ा का प्रावधान। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को राजद्रोह जैसे अपराधों से पहले प्राथमिकता दी गई।
- BNSS में प्रावधान: 7 साल या उससे अधिक की सज़ा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच (Forensic Investigation) को अनिवार्य किया गया। जाँच मुकदमे की कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में संचालित की जा सकती है।
- नागरिक अधिकार: महिलाओं, 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों, और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन जाने से छूट दी गई है।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- नए आपराधिक कानूनों (BNS, BNSS, BSA) का प्रमुख उद्देश्य क्या है, और वे उपनिवेशकालीन कानूनों से कैसे भिन्न हैं?
- सामुदायिक सेवा (Community Service) को सज़ा के रूप में शामिल करने के पीछे का न्यायिक दर्शन (Judicial Philosophy) क्या है?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- 7 साल या उससे अधिक की सज़ा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य करने से भारत की न्यायिक वितरण प्रणाली पर क्या प्रशासनिक बोझ (Administrative Burden) पड़ेगा?
- क्या डिजिटल सबूतों (Digital Evidence) के बढ़ते उपयोग से निजता का अधिकार (Right to Privacy) खतरे में पड़ सकता है?

2. संवैधानिक शासन और संघीय संबंध (Constitutional Governance and Federalism)

इस श्रेणी में राज्यपाल की भूमिका, न्यायिक सक्रियता और शक्ति पृथक्करण जैसे वे मौलिक सिद्धांत शामिल हैं, जो केंद्र-राज्य संबंधों को परिभाषित करते हैं।

2.1 तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्यपाल (Governor's Role)

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु के 10 विधेयकों को मंजूरी प्रदान की।
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों को मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श पर समयबद्ध तरीके से राज्य विधेयकों पर निर्णय लेना चाहिये।
- न्यायिक व्याख्या: न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्यपाल विधेयकों पर कार्रवाई में अनिश्चित काल के लिये विलंब नहीं कर सकते, और 'पूर्ण वीटो' या 'पॉकेट वीटो' की कोई संकल्पना नहीं है।
- समय सीमा: न्यायालय ने राज्यपालों के लिए राज्य विधानमंडल से प्राप्त विधेयकों पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक महीने की समय-सीमा निर्धारित की है।

- निहितार्थ: यह निर्णय राज्य विधेयकों को रोकने के लिए राज्यपाल के विवेकाधिकार के दुरुपयोग पर रोक लगाता है और विधायी प्रक्रिया की प्रधानता पर ज़ोर देता है।
- संभावित प्रश्न (Potential Questions):
 - तमिलनाडु मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 का प्रयोग करना, 'चेक्स एंड बैलेंस' (Checks and Balances) के सिद्धांत को कैसे प्रभावित करता है?
 - अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की 'वीटो शक्ति' (Veto Power) और 'राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित' करने की शक्ति की व्याख्या करें।
- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):
 - राज्यपालों के निष्कासन के लिए महाभियोग प्रक्रिया (Impeachment Process) क्यों नहीं है, और क्या इसे संविधान में शामिल किया जाना चाहिए?
 - सरकारी आयोग (Sarkaria Commission) और पुंछी आयोग (Punchhi Commission) ने राज्यपाल की भूमिका पर क्या प्रमुख सिफारिशें की थीं?

2.2 शक्ति पृथक्करण (Separation of Powers)

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):
 - अवधारणा: शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत तीन अलग-अलग शाखाओं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन को संदर्भित करता है।
 - आवश्यकता: सत्ता के दुरुपयोग को रोकना, जाँच और संतुलन सुनिश्चित करना, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा।
 - संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 50 सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने का आदेश देता है।
 - न्यायिक जाँच: एस.आर. बोम्मई केस और केशवानंद भारती केस में न्यायालय ने 'मूल ढाँचे' (Basic Structure) के सिद्धांत के तहत कार्यकारी और विधायी दोनों शक्तियों पर जाँच की आवश्यकता पर बल दिया।
 - अतिव्यापी शक्तियाँ: विधायिका न्यायपालिका पर महाभियोग (Impeachment) लगा सकती है। कार्यपालिका अध्यादेश (Ordinance) जारी कर सकती है। न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों की जाँच करती है।
- संभावित प्रश्न (Potential Questions):
 - शक्ति पृथक्करण (Separation of Powers) का सिद्धांत क्यों आवश्यक है, और भारतीय संविधान में इसे कैसे लागू किया गया है?
 - भारतीय संदर्भ में 'जाँच और संतुलन' (Checks and Balances) के सिद्धांत की व्याख्या करें।
- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):
 - क्या भारत में न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अतिक्रमण करती है?
 - संसदीय संप्रभुता (Parliamentary Sovereignty) और संवैधानिक सर्वोच्चता (Constitutional Supremacy) के बीच क्या अंतर है?

3. सामाजिक और विधिक सुधार (Social and Legal Reforms)

3.1 समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC)

यह लैंगिक न्याय (Gender Justice), राष्ट्रीय एकता और धार्मिक स्वतंत्रता (Religious Freedom) से संबंधित एक अत्यंत संवेदनशील संवैधानिक मुद्दा है।

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):
 - आधार: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य नीति के निदेशक तत्व (DPSP) के रूप में इसका उल्लेख।
 - उद्देश्य: विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाली विधियों को एक समान करना।
 - पक्ष में तर्क: विधि के अंतर्गत समता (Article 14), महिला सशक्तिकरण (पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देना), राष्ट्रीय एकता, और कानूनी प्रणाली को सरल बनाना।
 - विपक्ष में तर्क: धार्मिक स्वतंत्रता (Article 25) का उल्लंघन, सांस्कृतिक विविधता को क्षति पहुँचाना, अल्पसंख्यक अधिकारों पर प्रभाव, और व्यावहारिक कार्यान्वयन की जटिलता।
 - न्यायिक घोषणाएँ: शाह बानो केस (1985) ने UCC को राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ा।

- नवीनतम घटनाक्रम (उत्तराखंड): उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC), 2025 लागू किया है। इसके नियमों में जनजातीय कानूनों को छूट (Scheduled Tribes exemption) दी गई है, और लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationship) के पंजीकरण का प्रावधान है।
- संभावित प्रश्न (Potential Questions):
 - समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के संवैधानिक निहितार्थ (Constitutional Implications) क्या हैं, विशेषकर अनुच्छेद 25 के संदर्भ में?
 - UCC को राष्ट्रीय एकता (National Integration) के लिए आवश्यक क्यों माना जाता है, और यह लैंगिक न्याय (Gender Justice) को कैसे सुनिश्चित करेगा?
- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):
 - उत्तराखंड UCC में जनजातीय समुदायों (Scheduled Tribes) को क्यों छूट दी गई है? क्या यह छूट UCC के 'समानता' के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती?
 - क्या 'न्यायपूर्ण नागरिक संहिता' (Just Civil Code) 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code) की तुलना में अधिक उपयुक्त लक्ष्य है?

3.2 वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025

यह धार्मिक संपत्ति प्रबंधन में सुधार और पारदर्शिता (Transparency) लाने से संबंधित है।

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):
 - उद्देश्य: वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने, दक्षता में सुधार करने, और रिकॉर्ड प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना।
 - प्रमुख प्रावधान: ट्रस्टों को वक्फ से अलग करना; वक्फ समर्पण के लिए प्रैक्टिसिंग मुसलमान (कम से कम पांच वर्षों से) ही पात्र; धारा 40 को हटाकर मनमाने संपत्ति दावों को समाप्त करना।
 - सुधार: वक्फ बोर्डों के लिए अनिवार्य अंशदान 7 % से घटाकर 5 % कर दिया गया; वक्फ न्यायाधिकरणों में अपील अब उच्च न्यायालय में की जा सकती है।
 - चिंताएँ: आलोचकों का तर्क है कि यह अधिनियम सरकारी नियंत्रण में वृद्धि करता है और वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता को कम करता है। साथ ही, गैर-मुस्लिम अधिकारियों को शामिल करने से अनुच्छेद 26 का उल्लंघन होता है।
- संभावित प्रश्न (Potential Questions):
 - वक्फ (Waqf) क्या है, और इसकी संपत्ति को 'अविभाज्य' (Inalienable) क्यों माना जाता है?
 - वक्फ अधिनियम 2025 की धारा 40 को हटाने का उद्देश्य क्या है, और यह वक्फ बोर्डों की शक्तियों को कैसे प्रभावित करता है?
- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):
 - क्या वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनुच्छेद 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता) का उल्लंघन है?
 - 'एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ' के सिद्धांत के कारण क्या कानूनी जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं?

3.3 महिला जनप्रतिनिधियों के सशक्तीकरण हेतु सर्वोच्च न्यायालय का आह्वान

यह 73वें और 74वें संविधान संशोधन के उद्देश्यों को साकार करने का मुद्दा है।

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):
 - निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWR) को सशक्त बनाने के लिए शासन सुधारों का आह्वान किया है।
 - चुनौतियाँ: 'सरपंच-पतिवाद' (Sarpanch-Patiwad) प्रथा, नौकरशाही के अतिक्रमण, प्रणालीगत भेदभाव (Systemic Discrimination), और राजनीतिक वित्तीय बाधाएँ।
 - सरपंच-पतिवाद: इसमें निर्वाचित महिला पंचायत नेताओं के पति वास्तविक राजनीतिक और निर्णय लेने की शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिससे 73 वें संशोधन का उद्देश्य कमजोर होता है।
 - शासन में भूमिका: महिलाएं लैंगिक समानता को बढ़ावा देती हैं, पर्यावरणीय स्थिरता (Environmental Sustainability) को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती हैं (जैसे स्वच्छ भारत अभियान) और भ्रष्टाचार कम करती हैं।
 - प्रतिनिधित्व: पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के कुल प्रतिनिधियों में से 45.6 % EWR हैं।

- संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- 'सरपंच-पतिवाद' प्रथा 73 वें संवैधानिक संशोधन की 'आरक्षण' (Reservation) व्यवस्था के लिए क्या नैतिक चुनौती प्रस्तुत करती है?
- शासन में महिलाओं की भागीदारी से नीतिगत परिणामों (Policy Outcomes) और पारदर्शिता (Transparency) में कैसे सुधार आता है?

- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्या आरक्षण (Reservation) योग्यता (Merit) के सिद्धांत का उल्लंघन करता है?
- एक प्रशासक के रूप में आप नौकरशाहों को EWR की भूमिका का सम्मान करने और अतिक्रमण न करने के लिए कैसे संवेदनशील (Sensitize) करेंगे?

4. लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ और चुनावी सुधार (Democratic Processes and Electoral Reforms)

4.1 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (One Nation, One Election - ONOE)

यह शासन की स्थिरता और चुनावी लागत के प्रबंधन से संबंधित है।

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- विधेयक: 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' 129वाँ संविधान संशोधन विधेयक, 2024 लोकसभा में पेश किया गया।
- उद्देश्य: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को संरेखित (Align) करना।
- समिति: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर।
- समस्या: बार-बार चुनाव कराए जाने से अनिश्चितता उत्पन्न होती है, सार्वजनिक धन की हानि होती है, और प्रशासनिक व्यवस्था पर तनाव बढ़ता है।
- मुख्य संवैधानिक संशोधन: अनुच्छेद 82A (1-6) जोड़ने का प्रस्ताव; लोकसभा भंग होने पर अगली लोकसभा केवल शेष अवधि तक ही कार्य करेगी।
- चुनौतियाँ: बुनियादी ढाँचे का विकास (EVM, VVPAT), विधिक चुनौतियाँ, क्षेत्रीय असमानताएँ (स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा का खतरा) और संविधान संशोधन की आवश्यकता।

- संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के पक्ष और विपक्ष में आपके क्या तर्क हैं?
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को संरेखित करने के लिए संवैधानिक संशोधन क्यों आवश्यक है?

- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्या ONOE क्षेत्रीय दलों और संघवाद (Federalism) को कमजोर कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं?
- क्या अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) या राष्ट्रपति शासन (President's Rule) के कारण होने वाले मध्यावधि चुनावों की समस्या को ONOE हल कर सकता है?

4.2 भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव 2025

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- निर्वाचन: सी.पी. राधाकृष्णन भारत के 15 वें उपराष्ट्रपति चुने गए, जिन्होंने बी. सुदर्शन रेड्डी को हराया।
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 66 के अनुसार, चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है।
- पात्रता: उपराष्ट्रपति कम से कम 35 वर्ष का, भारत का नागरिक और राज्यसभा सदस्य बनने के लिये योग्य होना चाहिये।
- मुख्य भूमिका: राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष (ex-officio Chairman) के रूप में कार्य करते हैं।
- सुरक्षा उपाय: पार्टी व्हिप (Party Whip) की अनुमति नहीं होती है।

- संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- उपराष्ट्रपति (Vice President) का चुनाव राष्ट्रपति (President) के चुनाव से कैसे भिन्न होता है (निर्वाचक मंडल के संदर्भ में)?
- राज्यसभा के सभापति (Chairman) के रूप में उपराष्ट्रपति की क्या प्रमुख भूमिकाएँ होती हैं, विशेषकर सदन में व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में?

- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- 'एकल संक्रमणीय मत' (Single Transferable Vote) प्रणाली की व्याख्या करें।
- उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) की शक्तियों में क्या अंतर है?

4.3 मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR)

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- परिभाषा: SIR भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा किया जाने वाला मतदाता सूचियों का व्यापक, घर-घर जाकर (डोर-टू-डोर) सत्यापन और अद्यतन है।
- कानूनी आधार: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के तहत और अनुच्छेद 324 द्वारा ECI को प्रदत्त शक्तियों के तहत।
- आवश्यकता: दीर्घकालिक त्रुटियों का सुधार, डुप्लीकेट नकली मतदाताओं का उन्मूलन, और नए पात्र मतदाताओं को शामिल करना।
- चुनौतियाँ: हाशिये पर रह रहे समूहों के लिये दस्तावेजीकरण संबंधी बाधाएँ (Migrants, homeless), अवैध आप्रवासियों का समावेशन (Illegal Immigrants), और राजनीतिक हस्तक्षेप के जोखिम।

- संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की आवश्यकता क्यों है? यह लोकतंत्र (Democracy) को कैसे सशक्त बनाता है?
- SIR के दौरान हाशिये पर रह रहे समूहों (Marginalized Groups) को मताधिकार से वंचित होने से बचाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्या ईसीआई (ECI) को मतदाता सूचियों में संशोधन करने के लिए आधार (Aadhaar) को अनिवार्य कर देना चाहिए?
- "एक व्यक्ति, एक वोट" (One Person, One Vote) के सिद्धांत को बनाए रखने में SIR की क्या भूमिका है?

5. संवैधानिक स्थिति और मौलिक अधिकार (Constitutional Status and Fundamental Rights)

5.1 अनुच्छेद 370 और कश्मीर मुद्दा

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- निरस्तीकरण: 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, और जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू और कश्मीर और लद्दाख) में पुनर्गठित किया गया।
- आवश्यकता: एकीकरण और एकरूपता, आतंकवाद पर अंकुश, सामाजिक-आर्थिक विकास (निवेश पर प्रतिबंध हटाना), और भेदभावपूर्ण प्रावधानों (महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को प्रभावित करने वाले) को हटाना
- सकारात्मक विकास: रिकॉर्ड मतदाता भागीदारी (63 % से अधिक), पथराव और हिंसा में भारी गिरावट, और बुनियादी ढाँचा विकास (दुनिया का सबसे ऊँचा चिनाब रेल पुल)।
- चुनौतियाँ: उच्च बेरोजगारी दर (30 % से अधिक), आर्थिक मंदी (GSDP में गिरावट), और पुनर्बहाली (Restoration of Statehood) की मांग।
- नवीनतम: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में हुए, जिसने क्षेत्र में 64.28% का उच्च मतदान दर्ज किया।

- संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की संवैधानिक आवश्यकता और सामाजिक-आर्थिक तर्क (Socio-Economic Rationale) क्या थे?
- जम्मू-कश्मीर में उच्च बेरोजगारी दर और GSDP में गिरावट जैसी आर्थिक चुनौतियों का समाधान आप कैसे करेंगे?

- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) पर क्या प्रभाव पड़ा है?
- परिसीमन (Delimitation) प्रक्रिया ने जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कैसे बदला है?

5.2 'डिजिटल पहुँच का अधिकार' (Right to Digital Access) अनुच्छेद- 21

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- SC का निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने 'ई-गवर्नेंस और कल्याणकारी वितरण प्रणालियों तक समावेशी और सार्थक डिजिटल पहुँच' को जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का हिस्सा बताया।
- आधार: अनुच्छेद 21 केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि एक गरिमापूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन जीने के अधिकार से है।
- राज्य की जिम्मेदारी: राज्य की जिम्मेदारी है कि वह कमजोर और हाशिए पर रह रहे वर्गों के लिए एक समावेशी डिजिटल प्रणाली उपलब्ध कराएँ।
- डिजिटल पहुँच: इसमें इंटरनेट की पहुँच, डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता, और डेटा सुरक्षा शामिल है।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- 'डिजिटल पहुँच का अधिकार' किस प्रकार अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) की व्यापक व्याख्या को दर्शाता है?
- एक प्रशासक के रूप में आप डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy) को बढ़ावा देकर "हाशिए पर रह रहे वर्गों" तक डिजिटल पहुँच कैसे सुनिश्चित करेंगे?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- निजता का अधिकार (Right to Privacy) और डिजिटल पहुँच का अधिकार के बीच क्या नैतिक संबंध है?
- क्या इंटरनेट बंद करना (Internet Shutdown) मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है?

अंतरराष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति (International Relations and Foreign Policy)

1. संघर्ष, सुरक्षा और रणनीतिक प्रतिक्रिया (Conflict, Security and Strategic Response)

1.1 सिंधु जल संधि (IWT) का निलंबन (Operation Sindoor context)

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- संधि: सिंधु जल संधि (IWT), 1960; विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता; भारत को पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास, सतलुज) का जल आवंटित।
- निलंबन का कारण: पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा-पार आतंकवाद को जवाब देने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित।
- IWT में प्रावधान: संधि में एकतरफा निलंबन की अनुमति नहीं है।
- भारत की रणनीति: जल कूटनीति (Water Diplomacy) का उपयोग करना; पांच सूत्री कार्य योजना (Five-point Action Plan) लागू की गई।
- प्रभाव: पाकिस्तान की 80 % से अधिक कृषि भूमि इन नदियों पर निर्भर है। निलंबन से खाद्य असुरक्षा और आर्थिक अस्थिरता का खतरा है।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- आतंकवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया में सिंधु जल संधि को निलंबित करने का निर्णय नैतिक और कानूनी रूप से कितना उचित है?
- IWT और वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज (VCLT) के बीच क्या संबंध है?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्या IWT के निलंबन से एक जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय पक्षकार के रूप में भारत की विश्वसनीयता (Credibility) कमजोर होती है?
- पाकिस्तान की आर्थिक अस्थिरता भारत की सुरक्षा के लिए खतरा क्यों बन सकती है?

1.2 भारत-चीन संबंधों में एक नई दिशा का निर्माण (LAC Tensions)

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **टेंशन:** वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तनाव कम करने के लिए **डिसएंगेजमेंट, डी-एस्केलेशन और डी-इंडक्शन (3D दृष्टिकोण)** पर जोर।
- **आर्थिक सहयोग:** चीन **उर्वरक और दुर्लभ मृदा** की आपूर्ति करने पर सहमत; **सीमा व्यापार** (लिपुलेख, शिपकी ला, नाथू ला) को पुनः शुरू करने पर सहमति।
- **चुनौतियाँ:** 3,488 किलोमीटर लंबी LAC का स्पष्ट रूप से परिभाषित न होना; 85 अरब डॉलर का व्यापार घाटा; चीन का पाकिस्तान के साथ सामरिक सहयोग; और भारत की **UNSC स्थायी सीट** में बाधा।
- **रणनीति:** रणनीतिक बहुसंरेखण (Strategic Multi-Alignment) और **चयनात्मक भागीदारी (Selective Engagement)**।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- भारत-चीन संबंधों में '3D दृष्टिकोण' (डिसएंगेजमेंट, डी-एस्केलेशन, और डी-इंडक्शन) की व्याख्या करें।
- चीन के साथ **व्यापार घाटा (Trade Deficit)** भारत के लिए क्या **रणनीतिक जोखिम (Strategic Risk)** उत्पन्न करता है?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्या **SCO** और **BRICS** जैसे मंचों पर सहयोग करना, **LAC** पर तनाव की स्थिति में, भारत की **विदेश नीति** में विरोधाभास नहीं है?
- **ब्रह्मपुत्र और सतलुज** जैसी नदियों पर चीन का नियंत्रण भारत की **जल सुरक्षा (Water Security)** को कैसे प्रभावित करता है?

1.3 गाज़ा संघर्ष को समाप्त करने के लिये अमेरिका की योजना

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **योजना:** अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 20 सूत्री गाज़ा शांति पहल की घोषणा।
- **उद्देश्य:** हमास का निरस्त्रीकरण, गाज़ा का पुनर्निर्माण, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल (ISF) की तैनाती, और बंधक-कैदी विनिमय समझौता।
- **भारत की नीति:** 'टू-स्टेट सोल्यूशन' (Two-State Solution) का समर्थन; **डी-हाइफनेशन नीति (De-hyphenation policy)** अपनाना (इज़रायल और फिलिस्तीन के साथ अलग और स्वतंत्र संबंध)।
- **चुनौतियाँ:** हमास का हथियार छोड़ने में अनिच्छा, सुरक्षा और संप्रभुता संबंधी चिंताएं, और योजना में स्पष्टता की कमी।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- 'डी-हाइफनेशन नीति' क्या है, और भारत ने इसे इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष पर क्यों अपनाया है?
- गाज़ा संघर्ष भारत के **IMEC** (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा) की महत्वाकांक्षाओं को कैसे प्रभावित करता है?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- भारत **UNSC** में **फिलिस्तीन** के समर्थन में मतदान क्यों करता है, जबकि इज़रायल के साथ भी उसके मजबूत संबंध हैं?
- क्या 'टू-स्टेट सोल्यूशन' वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं में अभी भी संभव है?

2. बहुपक्षवाद और वैश्विक गुट (Multilateralism and Global Blocs)

2.1 ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **थीम:** "अधिक समावेशी और सतत् शासन के लिये वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना"।
- **विस्तार:** **इंडोनेशिया** आधिकारिक रूप से शामिल; 10 साझेदार देशों को स्वीकार किया गया।

- वैश्विक शासन: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन किया गया, ताकि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों से अधिक स्थायी सदस्य शामिल हो सकें।
- वित्तीय सहयोग: न्यू डेवलपमेंट बैंक का विस्तार और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए सीमा पार भुगतान पहल पर वार्ता।
- भारत का समर्थन: चीन और रूस ने ब्राजील और भारत की UNSC में बड़ी भूमिका निभाने की आकांक्षाओं के लिए समर्थन दोहराया।
- संभावित प्रश्न (Potential Questions):
 - ब्रिक्स विस्तार (BRICS Expansion) 'वैश्विक दक्षिण' (Global South) के हितों को कैसे प्रभावित करता है?
 - भारत UNSC में स्थायी सदस्यता के लिए किन प्रमुख तर्कों (जैसे BRICS, G4, Global South Leadership) का उपयोग करता है?
- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):
 - ब्रिक्स में संस्थागत सचिवालय की कमी क्यों है, और क्या चीन का बढ़ता प्रभाव समूह की एकता के लिए खतरा है?
 - 'डी-डॉलरकरण' (De-dollarisation) की प्रक्रिया ब्रिक्स देशों के लिए कितनी व्यावहारिक (Practical) है?

2.2 शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):
 - अध्यक्षता: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा।
 - दस्तावेज़: तियानजिन घोषणा और SCO विकास रणनीति (2035 तक)।
 - उद्देश्य: आतंकवाद-निरोध (क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना - RATS), आर्थिक सहयोग (SCO विकास बैंक), ऊर्जा सुरक्षा।
 - भारत की चिंताएँ: चीन का प्रभुत्व, BRI का विरोध (विशेषकर CPEC), और पश्चिम-विरोधी धारणा।
 - भारत की रणनीति: रणनीतिक बहुसंरेखण, और व्यापार तथा प्रौद्योगिकी जैसे सहयोगी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।
- संभावित प्रश्न (Potential Questions):
 - SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) आतंकवाद से निपटने में कितनी प्रभावी रही है?
 - चीन की BRI (बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव) के कारण SCO में भारत के क्या सामरिक मतभेद (Strategic Differences) हैं?
- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):
 - SCO को एक 'पश्चिम-विरोधी' गुट के रूप में क्यों देखा जाता है, और भारत की विदेश नीति इसे कैसे संतुलित करती है?
 - 'अफगानिस्तान संपर्क समूह' (ACG) का उद्देश्य क्या है?

2.3 भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):
 - घोषणा: 2025 को "भारत-जापान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार आदान-प्रदान" वर्ष घोषित किया गया।
 - समझौते: रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा-पत्र; 10 वर्षों में ₹10 ट्रिलियन का निवेश लक्ष्य; महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौता ज्ञापन।
 - तकनीकी साझेदारी: AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा में सहयोग; मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (शिकानसेन E10 ट्रेनों)।
 - मानव संसाधन: पाँच वर्षों में 5 लाख कुशल और अर्द्ध-कुशल भारतीय का आदान-प्रदान।
 - अंतरिक्ष सहयोग: संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन (LUPEX) के लिए इसरो और जाक्सा को एक साथ लाता है।
- संभावित प्रश्न (Potential Questions):
 - भारत-जापान साझेदारी को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में 'चीन कारक' (China Factor) को संतुलित करने के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है?
 - LUPEX मिशन और विकलांगों के लिए अंतरिक्ष सहयोग भारत-जापान संबंधों की गहराई को कैसे दर्शाते हैं?
- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):
 - क्या 10 ट्रिलियन यें का निवेश लक्ष्य भारत के बुनियादी ढांचे के अंतराल को भर सकता है?
 - 'दारुमा गुड़िया' का कूटनीतिक महत्व क्या है, और यह बोधिधर्म की विरासत से कैसे जुड़ा है?

2.4 प्रधानमंत्री की बहु-देशीय यात्राएँ (Global South Outreach)

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- देश: घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्राएं।
- Global South Outreach: भारत की विदेश नीति में 'ग्लोबल साउथ' (Global South) को प्राथमिकता देना; G20 और BRICS में उनके हितों को आगे बढ़ाना।
- मुख्य उपलब्धियाँ:
 - UPI: नामीबिया UPI तकनीक अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का पहला देश बना।
 - सम्मान: घाना का 'द ऑफिसर ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ द स्टार ऑफ़ घाना' और त्रिनिदाद और टोबैगो का 'द ऑर्डर ऑफ़ द रिपब्लिक ऑफ़ त्रिनिदाद एंड टोबैगो' (पहले विदेशी नेता)।
 - सहयोग: CDRI और ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस में शामिल होने की घोषणाएं।
 - सामरिक संसाधन: अर्जेंटीना में लिथियम, तांबा जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार में सहयोग।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- प्रधानमंत्री की 'ग्लोबल साउथ' (Global South) तक पहुँच भारत की विदेश नीति को किस प्रकार पुनर्परिभाषित करती है?
- UPI को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना भारत की 'डिजिटल कूटनीति' (Digital Diplomacy) को कैसे मजबूत करता है?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation) से आप क्या समझते हैं? क्या यह पश्चिमी देशों के वर्चस्व को चुनौती दे सकता है?
- भारत BRICS और G20 जैसे मंचों का उपयोग करके अफ्रीकी देशों के एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाता है?

2.5 भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)

यह चीन के BRI (Belt and Road Initiative) के खिलाफ भारत का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक विकल्प है।

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- प्रकृति: मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी पहल जिसे G20 शिखर सम्मेलन, 2023 में लॉन्च किया गया। इसमें रेलवे, समुद्री मार्ग, स्वच्छ हाइड्रोजन पाइपलाइन, और डिजिटल केबल शामिल हैं।
- कॉरिडोर: पूर्वी कॉरिडोर (भारत को खाड़ी क्षेत्र से) और उत्तरी कॉरिडोर (खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से)।
- रणनीतिक लाभ: स्वेज़ नहर मार्ग की तुलना में लॉजिस्टिक्स लागत को लगभग 30 % और परिवहन समय को लगभग 40 % कम करता है।
- भू-रणनीतिक महत्व: चीन की BRI के पारदर्शी, सतत् और ऋण-मुक्त विकल्प के रूप में कार्य करता है। भारत की एक्ट वेस्ट (Act West) नीति और OSOWOG (One Sun One World One Grid) लक्ष्यों का समर्थन करता है।
- चुनौतियाँ: पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अस्थिरता (चल रहे संघर्ष), विशाल वित्तपोषण की आवश्यकता, और अंतर-सरकारी समन्वय की जटिलता।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) क्या है, और यह चीन की BRI से किस प्रकार भिन्न है?
- IMEC भारत की एक्ट वेस्ट (Act West) नीति और OSOWOG ऊर्जा लक्ष्यों को कैसे मजबूत करता है?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक अस्थिरता IMEC की व्यवहार्यता (Viability) के लिए क्या सुरक्षा और नैतिक चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है?
- IMEC के लिए आवश्यक अरबों डॉलर का वित्तपोषण जुटाने में निजी क्षेत्र की क्या भूमिका हो सकती है?

2.6 नेपाल में जेन-Z का विरोध प्रदर्शन

• प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- प्रसंग: नेपाल में "जनरेशन Z" के विरोध-प्रदर्शन के कारण सत्तारूढ़ सरकार का पतन।
- कारण: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध ('अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' का उल्लंघन), बढ़ता भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी।
- युवा आंदोलनों की विशेषता: विकेन्द्रीकृत और नेतृत्व-रहित आंदोलन, प्रौद्योगिकी और डिजिटल माध्यमों का उपयोग (एन्क्रिप्टेड ऐप्स, VPNs)।
- प्रभाव: युवाओं में नीरसता की भावना कम करने और सुशासन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल।

• संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- नेपाल में जेन-Z विरोध से डिजिटल माध्यमों (Digital Mediums) की भूमिका नागरिक आंदोलनों (Civil Movements) में कैसे बदल गई है?
- क्या भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी युवाओं को अपरंपरागत तरीकों से विरोध करने के लिए प्रेरित करती है?

• संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्या सोशल मीडिया (Social Media) पर प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Expression) का उल्लंघन है?
- एक प्रशासक के रूप में आप युवाओं की सक्रिय भागीदारी को सामाजिक-आर्थिक नीतियों में कैसे सुनिश्चित करेंगे?

2.7 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत की विरासत

• प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- विरासत: भारत 1953 में कोरिया में UN अभियान से शुरू होकर 50 से अधिक मिशनों में 2,90,000 से अधिक शांति सैनिकों को भेजने वाला सबसे बड़ा योगदानकर्ता।
- भारतीय दर्शन: "वसुधैव कुटुम्बकम्" और "सर्व भवन्तु सुखिनः" शांति स्थापना के अनुरूप।
- सम्मान: वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च शांति सम्मान "डाग हैमरशॉल्ड" पदक प्रदान किया गया।
- नेतृत्व: मेजर राधिका सैन को "वर्ष 2023 की सैन्य जेंडर अधिवक्ता" नामित किया गया।
- दावा: भारत का योगदान UNSC स्थायी परिषद में शामिल होने की उसकी पर्याप्त योग्यता को दर्शाता है।

• संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना (UN Peacekeeping) में भारत के योगदान का नैतिक आधार (Ethical Foundation) क्या है?
- मेजर राधिका सैन को सैन्य जेंडर अधिवक्ता (Military Gender Advocate) नामित करने का क्या महत्व है?

• संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्या 'ना फर्स्ट यूज़' (NFU) की परमाणु नीति संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना लक्ष्यों के अनुरूप है?
- UNSC में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी को आप कैसे सही ठहराएंगे?

2.8 G20 में अफ्रीकी संघ (AU) की स्थायी सदस्यता

• प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- उपलब्धि: अफ्रीकी संघ (AU) को भारत की G20 अध्यक्षता (सितंबर 2023) के दौरान G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया।
- महत्व: इसने G20 को एक विशिष्ट क्लब से अधिक समावेशी मंच में बदल दिया और इसकी वैधता (Legitimacy) में सुधार किया।
- AU का एजेंडा: AU को एजेंडा 2063, जलवायु वित्त जुटाने, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार और AfCFTA (अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र) के क्रियान्वयन जैसे प्रमुख अफ्रीकी हितों को आगे बढ़ाने का मंच मिला।
- भारत की भूमिका: भारत ने ग्लोबल साउथ (Global South) के विकासवादी एजेंडे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया, और अफ्रीकी महाद्वीप की चिंताओं को विश्व मंच पर मुखर रूप से उठाया।
- UNSC सुधार: AU की सदस्यता से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) सुधार की मांग को बल मिलता है, ताकि ग्लोबल साउथ की आवाज़ (Amplified Voice of Global South) को बढ़ाया जा सके।

- संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- G20 में अफ्रीकी संघ (AU) को स्थायी सदस्यता प्रदान करने का भू-राजनीतिक और नैतिक महत्व क्या है?
- AU को G20 में शामिल करने से वैश्विक शासन (Global Governance) में ग्लोबल साउथ के एजेंडे को कैसे बल मिलता है?

- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- G20 में AU की प्रभावी सदस्यता के सामने समन्वय और वित्तीय संसाधन जुटाने की क्या चुनौतियाँ हैं?
- जलवायु वित्त और ऋण संकट (Debt Crisis) के मुद्दे पर भारत और दक्षिण अफ्रीका मिलकर AU के एजेंडे को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं?

2.9 क्वाड (Quad) समूह की गतिविधियाँ और हिंद-प्रशांत रणनीति

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- सदस्य: भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया।
- उद्देश्य: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त एवं खुली व्यवस्था (Free and Open Indo-Pacific - FOIP) को बढ़ावा देना, नियम-आधारित व्यवस्था (Rules-based order) और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना।
- बदलाव: क्वाड एक सैन्य-केंद्रित समूह से आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर देने वाले एक व्यापक गठबंधन में बदल गया है।
- सहयोग के क्षेत्र: आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (Supply Chain Resilience), महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियाँ (AI, Quantum), जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, और स्वास्थ्य सुरक्षा (Quad Health Security Partnership)।
- भारत का रुख: भारत क्वाड का उपयोग रणनीतिक प्रौद्योगिकी (Strategic Technology) को सुरक्षित करने के लिए करता है, लेकिन अपनी रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) (जैसे रूस के साथ संबंध) को भी संतुलित रखता है।

- संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- क्वाड (Quad) समूह का स्वरूप हाल के वर्षों में 'सैन्य गठबंधन' से 'आर्थिक गठबंधन' में कैसे बदला है?
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता (ASEAN Centrality) और क्वाड के उद्देश्यों के बीच क्या संतुलन आवश्यक है?

- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्या रूस और चीन के साथ भारत के संबंध क्वाड के रणनीतिक उद्देश्यों के विपरीत हो सकते हैं?
- आपदा प्रबंधन (Disaster Management) और जलवायु परिवर्तन (Climate Change) जैसे क्षेत्रों में क्वाड सहयोग भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?



SERVICES

06. राजस्थान की राजनीति, शासन और संबंधित मुद्दे (Rajasthan Polity, Governance and Related Issues)

राजस्थान की राजनीति, शासन और संबंधित मुद्दे

1. संवैधानिक और प्रशासनिक निकाय

- 1.1 राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का पुनर्गठन
- 1.2 राजस्थान का 7वाँ वित्त आयोग (SFC)
- 1.3 राज्य निर्वाचन आयोग (SEC)

2. शासन और विकास संबंधी निर्णय

- 2.1 राजस्थान सरकार ने 9 ज़िलों को निरस्त किया (District Reorganization)

UTKARSH
CIVIL
SERVICES

RAS 2024 INTERVIEW GUIDANCE PROGRAM



डॉ. ललित के. पंवार सर
(रिटायर्ड आईएएस) पूर्व अध्यक्ष, RPSC



अशोक सिंह
(Rank 20, RAS 2023)



डॉ. ए के मलिक सर
विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक, राजस्थान विश्वविद्यालय



दीपल खान सर
सिनिअर सॉल्यूशन प्रोफेशनल के बिजनेस



Scan the
QR Code
to watch the
**Detailed video
solution of Probable
& Counter Questions**

1. संवैधानिक और प्रशासनिक निकाय (Constitutional and Administrative Bodies)

इस श्रेणी में वे निकाय शामिल हैं जो राज्य प्रशासन की रीढ़ हैं और हाल ही में संरचनात्मक परिवर्तनों या नियुक्ति विवादों के कारण चर्चा में रहे हैं।

1.1 राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का पुनर्गठन

• प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **पुनर्गठन:** राजस्थान मंत्रिमंडल ने RPSC में सदस्यों की संख्या वर्तमान सात से बढ़ाकर दस करने का निर्णय लिया है।
- **विधिक आधार:** RPSC में सदस्य संख्या की वृद्धि के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तों) विनियम, 1974 के विनियम- 3 (1) में संशोधन किया जाएगा।
- **योग्यता पर ज़ोर:** सरकार राजनीतिक नियुक्तियों की बजाय योग्यता के आधार पर चयन को प्राथमिकता दे रही है।
- **पदोन्नति में छूट:** सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति देने के लिए वांछित अनुभव या सेवा अवधि में दो वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।
- **संरचना:** RPSC एक संवैधानिक संस्था है (संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत प्रावधान)।
- **नियुक्ति/कार्यकाल:** अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र (जो भी पहले हो) होता है।

• संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- RPSC में सदस्यों की संख्या बढ़ाने के पीछे का प्रशासनिक तर्क (Administrative Rationale) क्या है, और यह भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता (Impartiality) को कैसे सुनिश्चित करेगा?
- पदोन्नति (Promotion) के लिए वांछित अनुभव में छूट देने का प्रशासनिक उद्देश्य क्या है? क्या इससे सेवा की गुणवत्ता (Quality of Service) पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है?

• संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- लोक सेवा आयोगों की स्वायत्तता (Autonomy) और जवाबदेही (Accountability) के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है?

1.2 राजस्थान का 7वाँ वित्त आयोग (SFC)

• प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **गठन:** 01 अगस्त, 2025 को 7 वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा की गई।
- **अध्यक्ष/सदस्य:** अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी; सदस्य सचिव नरेश ठकराल।
- **संवैधानिक आधार:** संविधान के अनुच्छेद 243-I (पंचायतों के लिए) और 243-Y (नगरपालिकाओं के लिए) के तहत।
- **कार्य:** राज्य, पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच करों, शुल्कों, टोल और फीस की शुद्ध आय के वितरण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करना।
- **महत्व:** SFC स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करके उनकी स्वायत्तता और सेवा वितरण में सुधार सुनिश्चित करता है।
- **चुनौतियाँ:** SFC की प्रमुख समस्याओं में राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव, संसाधनों की कमी, और सिफारिशों की अनदेखी शामिल है।

• संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- राज्य वित्त आयोग (SFC) की स्थापना का संवैधानिक उद्देश्य क्या है? यह संघवाद (Federalism) को कैसे मजबूत करता है?
- SFC की सिफारिशों की राज्य सरकार द्वारा अनदेखी (Ignorance) करने के पीछे क्या कारण हैं, और आप इस समस्या को कैसे हल करेंगे?

• संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के कार्यों में क्या अंतर है?
- पंचायत हस्तांतरण सूचकांक (PDI) क्या है, और यह SFC की प्रभावशीलता को मापने में कैसे मदद करता है?

1.3 राज्य निर्वाचन आयोग (SEC)

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **नियुक्ति:** 17 सितंबर 2025 को राजेश्वर सिंह को राजस्थान के नए मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त (SEC) के रूप में नियुक्त किया गया।
- **मुख्य कार्य:** परिसीमन (Delimitation) और आरक्षण (Reservation), मतदाता सूची नवीनीकरण, आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) का कार्यान्वयन, और चुनावों का शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करना।
- **पहले:** वेबकास्टिंग (Webcasting) द्वारा पारदर्शिता, दिव्याकृति सिंह को 'स्टेट इलेक्शन आइकॉन' नियुक्त करना, होम वोटिंग (Home Voting) की पहल, और डिजिटल अभियान विनियम।
- **समावेशिता:** 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान (Home Voting) की पहल।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) की संवैधानिक स्वायत्तता (Constitutional Autonomy) सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान हैं?
- SEC द्वारा 'होम वोटिंग' (Home Voting) और 'वेबकास्टिंग' (Webcasting) जैसी पहलों को लागू करने का उद्देश्य क्या है?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- SEC और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की शक्तियों में क्या अंतर है?
- स्थानीय चुनावों के दौरान डिजिटल अभियान विनियम (Digital Campaign Regulations) लागू करने की क्या चुनौतियाँ हैं?

2. शासन और विकास संबंधी निर्णय

(Governance and Development Decisions)

इस श्रेणी में प्रशासनिक पुनर्गठन, विवादित परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं के माध्यम से विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

2.1 राजस्थान सरकार ने 9 ज़िलों को निरस्त किया (District Reorganization)

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- **निर्णय:** राजस्थान सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए 9 ज़िलों (जैसे दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, अनूपगढ़) और 3 संभागों (पाली, सीकर और बांसवाड़ा) को निरस्त कर दिया।
- **कारण (प्रशासनिक/वित्तीय):** व्यवहार्यता का अभाव, बुनियादी ढाँचे का अभाव (कार्यालय भवन, प्रशासनिक पद), और राज्य पर बोझ।
- **निष्कर्ष:** एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में नए ज़िलों को अव्यवहारिक पाते हुए उन्हें समाप्त करने की अनुशंसा की गई।
- **वर्तमान स्थिति:** राजस्थान में अब 41 ज़िले और 7 संभाग होंगे। 8 ज़िलों को प्रशासनिक आवश्यकताओं के चलते बरकरार रखा गया है।
- **जनगणना से संबंध:** राजस्व इकाइयों के पुनर्गठन पर 31 दिसंबर 2025 के बाद जनगणना कार्य पूरा होने तक रोक रहेगी।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- नए ज़िलों को निरस्त करने के पीछे का राजनीतिक और प्रशासनिक तर्क क्या है? क्या यह निर्णय स्थिरता (Stability) के सिद्धांत के विपरीत है?
- जिला पुनर्गठन (District Reorganization) के समय व्यवहार्यता (Viability) और राजनीतिक इच्छाशक्ति (Political Will) के बीच संतुलन कैसे बनाया जाना चाहिए?

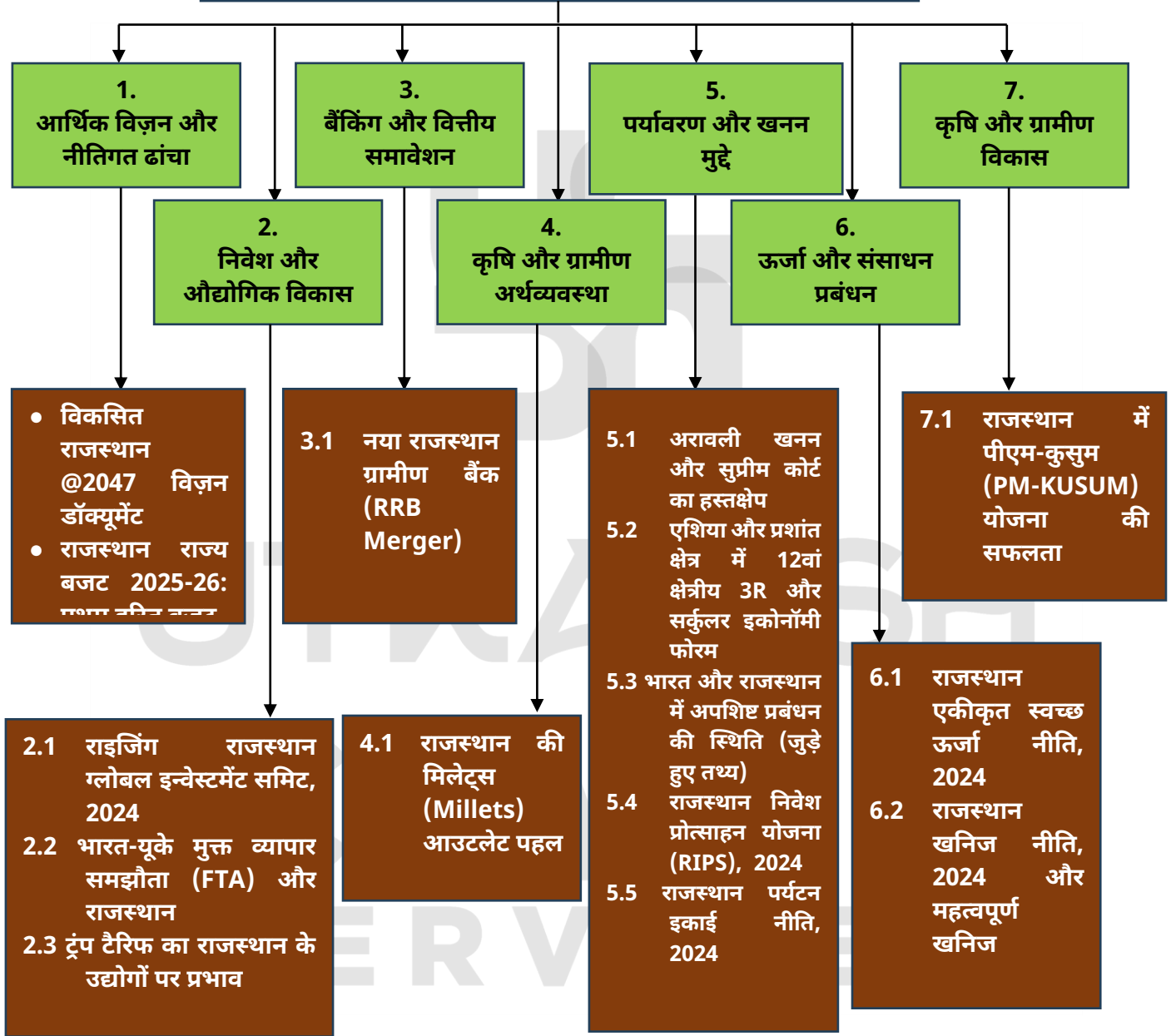
● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- जिला पुनर्गठन से जनगणना (Census) कार्य कैसे प्रभावित होता है?
- एक जिले के निर्माण में बुनियादी ढाँचे (Infrastructure) की क्या वित्तीय लागत (Financial Cost) होती है?



07. राजस्थान के आर्थिक मुद्दे और नवीनतम विकास (Economic Issues of Rajasthan and Latest Developments)

राजस्थान के आर्थिक मुद्दे और नवीनतम विकास



RAS 2024 INTERVIEW GUIDANCE PROGRAM



डॉ. ललित के. पंवार सर
(रिटायर्ड आईएएस) पूर्व अध्यक्ष, RPSC



अंशुक सिंग
(Rank 20, RAS 2023)



प्रो. ए. के. मलिक सर
विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय



दीपक खान सर
सिनिअर सॉल्यूटिंस एंड कोचिंग के डिरेक्टर



Scan the
QR Code
to watch the
**Detailed video
solution of Probable
& Counter Questions**



1. आर्थिक विज्ञान और नीतिगत ढांचा (Economic Vision and Policy Framework)

इस श्रेणी में राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों, बजट प्राथमिकताओं और भविष्य की रूपरेखा को शामिल किया गया है।

1.1 विकसित राजस्थान @2047 विज़न डॉक्यूमेंट

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**
 - **लक्ष्य:** राजस्थान को वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना।
 - **मध्यावधि लक्ष्य:** वर्ष 2029 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य।
 - **स्तंभ (Pillars):** कृषि, उद्योग, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) विकास के मुख्य चालक होंगे।
 - **4 प्रमुख थीम्स:**
 - सार्वजनिक कल्याण और सामाजिक सशक्तीकरण: मानव विकास और सामाजिक समानता।
 - तीव्र विकास, समृद्धि और रोज़गार: उद्योग, खनन और सांस्कृतिक विकास।
 - बुनियादी ढाँचा और सतत् विकास: जल सुरक्षा और जलवायु लचीलापन (Climate Resilience)।
 - नीति, वित्त और प्रशासन: सुशासन और वित्तीय प्रबंधन।
 - **विशिष्ट लक्ष्य (2047 तक):**
 - निर्माण उद्योग का GSVA में हिस्सा 20 % तक बढ़ाना।
 - जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष तक बढ़ाना।
 - शिशु मृत्यु दर (IMR) को 10 से कम करना।
 - महिला कार्यबल भागीदारी को 60 % से अधिक करना।
 - घरेलू पर्यटकों में राजस्थान का हिस्सा 15 % तक बढ़ाना।
- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**
 - 'विकसित राजस्थान @2047' विज़न डॉक्यूमेंट के मुख्य आर्थिक लक्ष्य क्या हैं, और राज्य 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा?
 - इस विज़न में महिला सशक्तीकरण और श्रम बल भागीदारी के लिए क्या विशिष्ट लक्ष्य रखे गए हैं?
- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**
 - क्या आपको लगता है कि 2047 तक निर्माण उद्योग का हिस्सा 20% तक बढ़ाना यथार्थवादी (Realistic) है, जबकि वर्तमान में सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व है?
 - सतत् विकास (Sustainable Development) और तीव्र औद्योगिकीकरण के बीच संतुलन बनाने के लिए विज़न डॉक्यूमेंट में क्या प्रावधान हैं?

1.2 राजस्थान राज्य बजट 2025-26: प्रथम हरित बजट

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**
 - **विशेषता:** यह राज्य का प्रथम हरित बजट (Green Budget) है।
 - **प्रस्तुतकर्ता:** उप मुख्यमंत्री (वित्त) दिया कुमारी (19 फरवरी, 2025)।
 - **10 प्रमुख बिंदु:**
 - जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (Climate Change Adaptation)।
 - वन और पर्यावरण - जैव विविधता/पारिस्थितिकी।
 - सतत् कृषि और जल संचयन/पुनर्भरण।
 - सतत् भूमि उपयोग (Sustainable land use)।
 - हरित ऊर्जा (Green Energy)।
 - रीसाइक्लिंग और चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy)।
 - क्लीन टेक डेवलपमेंट (Clean Tech Development)।
 - ग्रीन ऑडिट (Green Audit)।
 - क्षमता निर्माण (शिक्षा, कौशल)।
 - ग्रीन फंडिंग (Green Funding)।
- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**
 - राजस्थान के 'प्रथम हरित बजट' की अवधारणा क्या है, और यह पारंपरिक बजट से कैसे भिन्न है?
 - बजट में उल्लिखित 'ग्रीन ऑडिट' (Green Audit) और 'ग्रीन फंडिंग' से आप क्या समझते हैं?
- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**
 - क्या एक विकासशील राज्य के लिए हरित बजट की प्राथमिकताएं बुनियादी ढांचे के विकास की लागत को बढ़ा सकती हैं?
 - चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) को बढ़ावा देने से राजस्थान के औद्योगिक कचरे की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है?

2. निवेश और औद्योगिक विकास

(Investment and Industrial Development)

यह श्रेणी राज्य में निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक सम्मेलनों और वैश्विक भागीदारी पर केंद्रित है।

2.1 राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- आयोजन: 9 - 11 दिसंबर 2024, जयपुर (JECC)।
- उद्घाटन: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा।
- निवेश समझौता (MoU): कुल ₹35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र में सर्वाधिक (₹26 लाख करोड़) निवेश।
- भागीदारी: 32 देशों के प्रतिनिधि, 17 पार्टनर कंट्री (जैसे डेनमार्क, जापान, सिंगापुर)।
- प्रमुख सत्र:
 - प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव: 10 दिसंबर को 'प्रवासी राजस्थानी दिवस' घोषित।
 - MSME कॉन्क्लेव: लघु उद्योगों के लिए एक एकड़ जमीन के लैंड कन्वर्जन में छूट की घोषणा।
 - देश-विशिष्ट सत्र: जापान, अमेरिका, इजरायल (जल सुरक्षा पर), डेनमार्क (सरस्वती नदी पुनर्जीवन)।
- 'R' फैक्टर: प्रधानमंत्री ने राजस्थान के Reliable, Receptive, Refine, Responsive, Reformist गुणों की सराहना की।
- भविष्य: वर्ष 2026 में दूसरे समिट का आयोजन और एमओयू की समीक्षा।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' का मुख्य उद्देश्य क्या था, और इसमें ऊर्जा क्षेत्र को सर्वाधिक निवेश क्यों मिला?
- 'प्रवासी राजस्थानी दिवस' की घोषणा का राज्य की अर्थव्यवस्था और निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- अक्सर देखा जाता है कि निवेश समिट में हुए MoU धरातल पर नहीं उतर पाते। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने क्या रणनीति अपनाई है?
- MSME के लिए लैंड कन्वर्जन में छूट देने से औद्योगिक विकास को कैसे गति मिलेगी?

2.2 भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA) और राजस्थान

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- प्रभाव: राजस्थान के रत्न-आभूषण, वस्त्र, हस्तशिल्प और मार्बल उद्योगों को प्रत्यक्ष लाभ।
- शून्य शुल्क (Zero Tariff): समझौते से यूके में भारतीय निर्यात के 99 % पर शुल्क समाप्त (रत्न-आभूषण पर पहले 2-4 %, वस्त्र पर 12 %)।
- निर्यात क्षमता: राजस्थान का यूके को निर्यात वर्तमान में ₹5,000 करोड़ है, जिसके 20 % बढ़ने की उम्मीद है।
- लाभान्वित क्षेत्र:
 - रत्न और आभूषण: मीनाकारी और कुंदन आभूषणों में राजस्थान का एकाधिकार (60-90 % हिस्सा)।
 - टेक्सटाइल: भीलवाड़ा, जयपुर, पाली के कपड़ा उद्योगों को बांग्लादेश/वियतनाम से प्रतिस्पर्धा में बढ़त।
 - हस्तशिल्प: जयपुर की ब्लू पॉटरी, जोधपुर का फर्नीचर।
 - ऑटो पार्ट्स: टपूकड़ा (होंडा) से इंजन पार्ट्स के निर्यात को बल।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- भारत-यूके FTA से राजस्थान के हस्तशिल्प और रत्न-आभूषण उद्योग को क्या विशिष्ट लाभ होंगे?
- यह समझौता राजस्थान के टेक्सटाइल सेक्टर को बांग्लादेश और वियतनाम की प्रतिस्पर्धा से कैसे उबार सकता है?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्या FTA से स्थानीय उद्योगों पर सस्ते ब्रिटिश सामान के आयात का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है?
- शून्य शुल्क (Zero Tariff) का लाभ उठाने के लिए राजस्थान के निर्यातकों को गुणवत्ता मानकों (Quality Standards) में क्या सुधार करने होंगे?

2.3 ट्रंप टैरिफ का राजस्थान के उद्योगों पर प्रभाव

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- मुद्दा: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50 % टैरिफ लगाने की घोषणा।
- प्रभाव: राजस्थान के रत्न-आभूषण, हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट उद्योगों के 60 % ऑर्डर रद्द (लगभग ₹4,000 करोड़ के)।
- डंप माल: लगभग ₹2500 करोड़ का निर्यात माल गोदामों में अटक गया है।
- सर्वाधिक प्रभावित: जेम्स एंड ज्वैलरी (जयपुर का प्रमुख उद्योग)। अमेरिका भारत के जेम्स एंड ज्वैलरी का सबसे बड़ा आयातक (16 %) है।
- अन्य प्रभावित क्षेत्र: हथकरघा और हस्तशिल्प (जोधपुर का फर्नीचर, उदयपुर की नक्काशी) और गारमेंट्स (भीलवाड़ा, जयपुर)।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- अमेरिकी टैरिफ नीति में बदलाव का राजस्थान के निर्यात-उन्मुख उद्योगों (Export-Oriented Industries) पर क्या तत्काल प्रभाव पड़ा है?
- जेम्स एंड ज्वैलरी सेक्टर में ऑर्डर रद्द होने से राज्य में रोज़गार पर क्या असर पड़ेगा?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- निर्यात बाजार में विविधता (Diversification) की कमी राजस्थान के उद्योगों के लिए जोखिम क्यों है? अमेरिका के विकल्प के रूप में किन बाजारों को देखा जा सकता है?
- राज्य सरकार को इस संकट से निपटने के लिए निर्यातकों को क्या तत्काल राहत (Immediate Relief) देनी चाहिए?

3. बैंकिंग और वित्तीय समावेशन (Banking and Financial Inclusion)

3.1 नया राजस्थान ग्रामीण बैंक (RRB Merger)

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- विलय: राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय।
- नई इकाई: "राजस्थान ग्रामीण बैंक"।
- प्रभावी तिथि: 1 मई, 2025।
- नीति: केंद्र सरकार की "एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" (One State, One RRB) नीति के तहत।
- उद्देश्य: ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना, संचालन लागत कम करना और सुव्यवस्थित प्रबंधन।
- ग्राहकों पर प्रभाव: खाते सुरक्षित रहेंगे, लेकिन IFSC/खाता संख्या में बदलाव संभव; एकीकृत प्रणाली से बेहतर सुविधा।

● संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- राजस्थान में ग्रामीण बैंकों के विलय का मुख्य उद्देश्य क्या है? "एक राज्य, एक आरआरबी" नीति के क्या लाभ हैं?
- इस विलय से ग्रामीण ऋण वितरण (Rural Credit Delivery) और किसानों को कैसे लाभ होगा?

● संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्या बैंकों के विलय से शाखाओं के युक्तिकरण (Rationalization) के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच कम होने का खतरा है?
- RRB (Regional Rural Banks) और व्यावसायिक बैंकों (Commercial Banks) के उद्देश्यों में क्या मूल अंतर है?

4. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Agriculture and Rural Economy)

4.1 राजस्थान की मिलेट्स (Millets) आउटलेट पहल

● प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- पहल: राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों के माध्यम से 152 मिलेट्स आउटलेट्स स्थापित किए (लक्ष्य 34 से अधिक)।
- उद्देश्य: मिलेट्स (श्री अन्न) को सुरक्षित और पोषक विकल्प के रूप में लोकप्रिय बनाना और रोज़गार सृजन।
- मिलेट्स में राजस्थान: क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में प्रथम। प्रमुख फसलें - बाजरा, ज्वार।
- लाभ: कम पानी की आवश्यकता, सूखा प्रतिरोधी, ग्लूटेन-फ्री और पोषक तत्वों (आयरन, जिंक) से भरपूर।
- चुनौतियाँ: प्रति हेक्टेयर कम उपज, प्रसंस्करण इकाइयों की कमी।

- संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- राजस्थान सरकार द्वारा मिलेट्स आउटलेट्स खोलने का ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पोषण सुरक्षा (Nutritional Security) पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
- राजस्थान को 'मिलेट्स हब' के रूप में विकसित करने की क्या संभावनाएं हैं?

- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- मिलेट्स की मूल्य संवर्धन (Value Addition) शृंखला में राजस्थान अभी भी पीछे क्यों है? प्रसंस्करण इकाइयों (Processing Units) की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है?
- सहकारी समितियों (Cooperatives) की भूमिका इस पहल में क्यों महत्वपूर्ण है?

5. पर्यावरण और खनन मुद्दे (Environment and Mining Issues)

5.1 अरावली खनन और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा तय करने पर फैसला सुरक्षित रखा।
- महत्व: अरावली थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने, भूजल पुनर्भरण और दिल्ली-NCR के लिए प्राकृतिक ढाल है।
- नुकसान: अवैध खनन के कारण राजस्थान में अरावली की 25 % से अधिक और 31 पर्वत शृंखलाएँ विलुप्त हो गई हैं।
- समिति रिपोर्ट: MoEF&CC समिति ने वैज्ञानिक परिभाषा (100 मीटर ऊँचाई, ढलान सहित) और सख्त संरक्षण का सुझाव दिया।
- अवैध खनन: 2023 - 24 में बजरी और पत्थर के अवैध खनन के मामले बढ़े; कार्यवाही केवल परिवहन तक सीमित।

- संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- अरावली की वैज्ञानिक परिभाषा तय करना अवैध खनन को रोकने में कैसे मदद करेगा?
- अरावली के विलुप्त होने से राजस्थान और NCR की जलवायु और जल सुरक्षा पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेंगे?

- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- अवैध खनन को रोकने में ड्रोन और सैटेलाइट मैपिंग जैसी तकनीकों का उपयोग राजस्थान में कितना प्रभावी रहा है?
- खनन माफिया और प्रशासन की मिलीभगत के आरोपों पर आपकी क्या राय है, और इसे रोकने के लिए क्या संस्थागत सुधार (Institutional Reforms) आवश्यक हैं?

5.2 एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम

यह आयोजन राजस्थान को वैश्विक पर्यावरणीय कूटनीति और सतत् विकास के केंद्र के रूप में स्थापित करता है।

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- आयोजन: 12 वां उच्च स्तरीय क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, जयपुर (राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर) में आयोजित।
- तिथियां: 3 - 5 मार्च, 2025।
- थीम: "एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य (SDGs) और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर सोसायटी का निर्माण"।
- आयोजक: भारत सरकार (आवास और शहरी कार्य मंत्रालय), संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केंद्र (UNCRD), और जापान का पर्यावरण मंत्रालय।
- मुख्य घोषणा: 'नयी 3R और सर्कुलर इकोनॉमी घोषणा (2025-2034)' पर सहमति, जो अगले दशक के लिए रोडमैप तैयार करेगी।
- गठबंधन (Coalition): केंद्रीय मंत्री द्वारा 'सर्कुलरिटी के लिए शहरों के गठबंधन (C3)' की घोषणा की गई, जो एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन है।
- समझौता: 'सिटीज 2.0' (CITIIS 2.0) के लिए समझौता ज्ञापन, जो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है।
- प्रदर्शन: 'कचरे से कंचन' (Waste to Wealth) पहल और '3R व्यापार और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी' का आयोजन।
- भारत का विजन: प्रधानमंत्री का 'P-3' (Pro-Planet People) विजन और LiFE (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) अभियान।

- संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- '3R' (Reduce, Reuse, Recycle) और 'सर्कुलर इकोनॉमी' (Circular Economy) की अवधारणा क्या है? यह पारंपरिक 'लीनियर इकोनॉमी' (Linear Economy) से कैसे भिन्न है?
- जयपुर में आयोजित 12वें 3R फोरम का राजस्थान के शहरी विकास और अपशिष्ट प्रबंधन (Waste Management) नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- 'सर्कुलरिटी के लिए शहरों के गठबंधन (C3)' का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या भारतीय शहर इसके लिए तकनीकी रूप से तैयार हैं?
- क्या 'कचरे से कंचन' (Waste to Wealth) पहल वास्तव में आर्थिक रूप से व्यवहार्य (Viable) है, या यह केवल सब्सिडी पर निर्भर है?

5.3 भारत और राजस्थान में अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति (जुड़े हुए तथ्य)

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- स्वच्छ भारत मिशन (SBM-U): भारत में 80.29 % ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जा रहा है।
- घरेलू शौचालय: SBM-U के तहत लक्ष्य से अधिक (108.62 %) सफलता हासिल की गई।
- गोबर-धन योजना: इसका उद्देश्य जैविक अपशिष्ट को बायोगैस/CNG में बदलना है। फरवरी 2025 तक 1008 बायोगैस संयंत्र चालू हो जाएंगे।
- ई-कचरा (E-Waste): वित्त वर्ष 2024 - 25 (दिसंबर तक) में 5.82 लाख मीट्रिक टन ई-कचरा एकत्र किया गया और 5.18 लाख मीट्रिक टन का पुनर्चक्रण (Recycle) किया गया।
- EPR (विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व): प्लास्टिक और ई-कचरे के लिए उद्योगों की जवाबदेही तय की गई है। भारत ने 1 जुलाई, 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक (SUP) पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- चुनौतियाँ: तीव्र शहरीकरण, संसाधनों की कमी, और लीनियर से सर्कुलर मॉडल में संक्रमण की उच्च लागत।

- संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' (EPR) क्या है, और यह ई-कचरा प्रबंधन में कैसे मदद करता है?
- गोबर-धन योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) और स्वच्छता से कैसे जोड़ती है?

- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- प्लास्टिक प्रतिबंध के बावजूद धरातल पर एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग क्यों जारी है? प्रवर्तन (Enforcement) में क्या कमियाँ हैं?
- लैंडफिल साइट्स (Landfill Sites) की समस्या का स्थायी समाधान क्या है? क्या 'वेस्ट टू एनर्जी' (Waste to Energy) प्लांट ही एकमात्र विकल्प हैं?

5.4 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2024

यह नीति राज्य में निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन का मुख्य आधार है।

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- उद्देश्य: समावेशी, संतुलित और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- 3 प्रमुख स्तंभ: हरित विकास (Green Growth), निर्यात संवर्धन (Export Promotion), और क्षमता विकास (Capability Development)।
- नवाचार: पहली बार मौजूदा उद्यमों को भी प्रोत्साहन दिया गया है यदि वे 'हरित विकास' या 'निर्यात संवर्धन' में निवेश करते हैं।
- नए क्षेत्र (Sunrise Sectors): एयरोस्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, एग्री-टेक और वेस्ट-टू-एनर्जी को 'सनराइज सेक्टर' के रूप में विशेष प्रोत्साहन।
- रोजगार सृजन: रोजगार सृजन पर विशेष जोर, जिसमें स्थानीय युवाओं के कौशल विकास (Upskilling) के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।
- MSME: थ्रेशोल्ड निवेश सीमा को कम करके MSME और महिला उद्यमियों के लिए अधिक सुलभ बनाया गया है।

- संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2024 के तीन प्रमुख स्तंभ क्या हैं? यह RIPS 2019 या 2022 से किस प्रकार अधिक व्यापक है?
- इस नीति में 'सनराइज सेक्टर्स' को बढ़ावा देने के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं?

- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- क्या केवल वित्तीय प्रोत्साहन (Financial Incentives) निवेश आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हैं? राजस्थान में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की वास्तविक स्थिति क्या है?
- हरित विकास (Green Growth) को प्रोत्साहित करने से राज्य के पारंपरिक उद्योगों (जैसे टेक्सटाइल, माइनिंग) पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

5.5 राजस्थान पर्यटन इकाई नीति (Rajasthan Tourism Unit Policy) 2024

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- उद्देश्य: पर्यटन को 'उद्योग' का दर्जा देने के लाभों को औपचारिक रूप देना और निजी निवेश को आकर्षित करना।
- उद्योग का दर्जा: पर्यटन इकाइयों को अब औद्योगिक दरों पर बिजली, शहरी विकास कर में छूट और बिल्डिंग प्लान अनुमोदन में प्राथमिकता मिलेगी।
- हेरिटेज संरक्षण: हेरिटेज होटलों और संपत्तियों के लिए विशेष छूट और नियमों में ढील।
- ग्रामीण पर्यटन: ग्रामीण पर्यटन इकाइयों के लिए निवेश सीमा को कम किया गया है।
- प्रक्रियात्मक सुधार: लाइसेंस और अनुमोदन के लिए समयबद्ध मंजूरी (Time-bound approvals) और सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत किया गया।
- प्रोत्साहन: स्टाम्प ड्यूटी में छूट (75-100%), कन्वर्जन चार्ज में छूट, और SGST का पुनर्भरण।

- संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 के तहत पर्यटन को 'उद्योग का दर्जा' देने के क्या व्यावहारिक लाभ हैं?
- यह नीति ग्रामीण पर्यटन (Rural Tourism) और हेरिटेज संरक्षण को कैसे संतुलित करती है?

- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- राजस्थान में पर्यटन का मौसमी (Seasonal) होना एक चुनौती है। नीति इस समस्या का समाधान कैसे करती है?
- क्या पर्यटन के अनियंत्रित विकास से राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण पर दबाव नहीं बढ़ रहा है?

6. ऊर्जा और संसाधन प्रबंधन (Energy and Resource Management)

6.1 राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 (Integrated Clean Energy Policy)

- प्रमुख तथ्य (Factual Details):

- लक्ष्य: वर्ष 2029-30 तक 125 गीगावाट (GW) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना।
- घटक: सौर ऊर्जा (90 GW), पवन और हाइब्रिड (25 GW), और हाइड्रो/स्टोरेज (10 GW)।
- नया फोकस: ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS और Pumped Hydro), हरित हाइड्रोजन, और अपशिष्ट से ऊर्जा (Waste-to-Energy)।
- ग्रिड स्थिरता: केवल उत्पादन ही नहीं, बल्कि ग्रिड स्थिरता (Grid Stability) और डिस्पैचबिलिटी (Dispatchability) पर जोर।
- प्रोत्साहन: भूमि आवंटन में प्राथमिकता, ट्रांसमिशन शुल्क में छूट, और मैनुफैक्चरिंग जोन का विकास।
- स्थिति: राजस्थान वर्तमान में सौर ऊर्जा क्षमता में देश में प्रथम है (लगभग 23 GW)।

- संभावित प्रश्न (Potential Questions):

- राजस्थान की 'एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024' पारंपरिक सौर नीति से कैसे भिन्न है? ऊर्जा भंडारण (Energy Storage) पर इतना जोर क्यों दिया गया है?
- 125 GW के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भूमि अधिग्रहण और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा?

- संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):

- पम्पड हाइड्रो स्टोरेज (Pumped Hydro Storage) क्या है और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति इसके लिए कितनी उपयुक्त है?
- क्या नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार ओरण और चारागाह भूमि के संरक्षण के साथ संघर्ष पैदा कर रहा है?

6.2 राजस्थान खनिज नीति 2024 और महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals)

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**
 - **फोकस:** सतत और शून्य-अपशिष्ट खनन (Zero-Waste Mining), तकनीकी एकीकरण, और महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) का अन्वेषण।
 - **महत्वपूर्ण खोज:** बाड़मेर, सीकर, सिरोंही और भीलवाड़ा में दुर्लभ मृदा तत्वों (Rare Earth Elements - REE) के भंडार की पुष्टि।
 - **अन्य खनिज:** लिथियम (नागौर), पोटाश (हनुमानगढ़-बीकानेर बेसिन - दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक), और गोल्ड (बांसवाड़ा)।
 - **प्रौद्योगिकी:** अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन, AI और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग।
 - **राजस्व:** खनिज क्षेत्र राज्य के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है (FY24 में ₹7400 करोड़ से अधिक)।
- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**
 - राजस्थान में दुर्लभ मृदा तत्वों (REE) और लिथियम की खोज भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
 - नई खनिज नीति में 'शून्य-अपशिष्ट खनन' (Zero-Waste Mining) की अवधारणा को कैसे लागू किया जाएगा?
- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**
 - अवैध बजरी खनन राज्य की एक पुरानी समस्या है। क्या नई तकनीक (जैसे ड्रोन) इसका प्रभावी समाधान हो सकती है?
 - पोटाश खनन के लिए 'सॉल्यूशन माइनिंग' (Solution Mining) तकनीक क्या है और राजस्थान में इसकी क्या प्रासंगिकता है?

7. कृषि और ग्रामीण विकास (Agriculture and Rural Development)

7.1 राजस्थान में पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना की सफलता

- **प्रमुख तथ्य (Factual Details):**
 - **उपलब्धि:** राजस्थान पीएम-कुसुम योजना के घटक-A (बंजर भूमि पर सौर संयंत्र) के क्रियान्वयन में देश में प्रथम है।
 - **क्षमता:** 2000 मेगावाट से अधिक की क्षमता स्थापित (घटक A और C के तहत)।
 - **मॉडल:** किसानों को 'ऊर्जा दाता' (Energy Provider) बनाना। सौर ऊर्जा से सिंचाई और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचना।
 - **सौरऊर्जाकरण:** कृषि फीडरों का सौरऊर्जाकरण (Solarization) करने से दिन के समय बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।
- **संभावित प्रश्न (Potential Questions):**
 - पीएम-कुसुम योजना ने राजस्थान के किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में कैसे योगदान दिया है?
 - राजस्थान इस योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी क्यों है? इसके पीछे के भौगोलिक और नीतिगत कारण क्या हैं?
- **संभावित प्रतिप्रश्न (Probable Counter-Questions):**
 - क्या सौर पंपों के अनियंत्रित उपयोग से भूजल दोहन (Groundwater Exploitation) बढ़ने का खतरा है?
 - डिस्कॉम (DISCOMs) की खराब वित्तीय स्थिति सौर ऊर्जा खरीद भुगतान को कैसे प्रभावित करती है?



RAS 2024

INTERVIEW GUIDANCE PROGRAM



डॉ. ललित के. पंवार सर
(रिटायर्ड आईएएस) पूर्व अध्यक्ष, RPSC



अशोक गोयल
(Rank 20, RAS 2023)



डॉ. ए. के. मलिक सर
(विभागाध्यक्ष एवं राजस्व विभाग)



दीपक खान सर
(सिबिल सर्विस रजिस्ट्रार एवं राजस्व विभाग)





Scan the QR Code to watch the Detailed video solution of Probable & Counter Questions